खण्ड-166, अंक-4
गुरूवार, 11 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(1 मार्च, 1956 ई0)

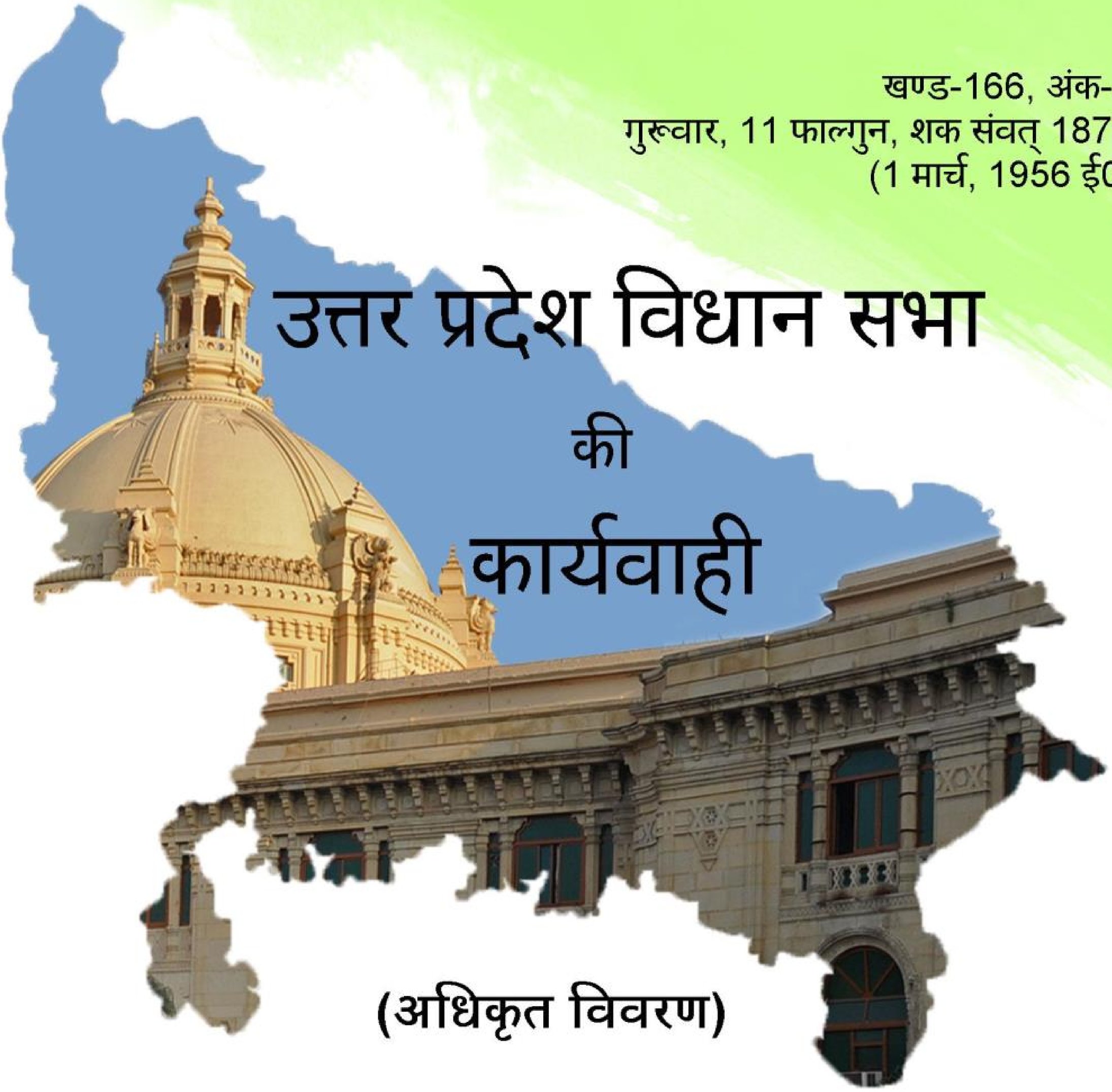

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 166 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE
25 JUL 1956
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १ मार्च, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफअली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर श्री,
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
ख्याली राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह श्री,
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह ,श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री

जगत नारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालारप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम श्री,
दलहबादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीन दयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ठ, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री (बनारस)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री

बैजू राम, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुलनबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखिरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअवार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
राम नरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राम भजन ,श्री
राम मूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती

लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

१९५६–५७ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं कल निवेदन कर रहा था कि उद्योग धंधों के लिये १७ करोड़ रुपया जो रखा गया है उसमें से ५ १/४ करोड़ ही अन्त में बेसिक उद्योगों के लिये बच जाता है, मैं इसे बहुत ही कम समझता हूं। इस सिलसिले में "समाजवाद की ओर जो कार्य प्रारम्भ हुआ है उसकी शुरुआत बहुत ही अशुभ है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में जिन नामों की घोषणा आज हुई है उसमें प्रायः सभी पूंजीपति भरे हुये हैं और मजदूरों का एक भी प्रतिनिधि इस कमेटी में जो उद्योगों के विषय में जांच-पड़ताल करेगी, नहीं रखा गया है। यह समाजवाद की ओर तो कदम कतई नहीं कहा जा सकता है। इस सिलसिले में पूंजी का प्रश्न आता है। मेरा एक सुझाव है कि सरकार इस तरह के कानून बनाये कि हमारे प्रदेश में जो पूंजीपति हैं वह अपने पूरे मुनाफे का कम से कम ८० फीसदी अनिवार्यतः उद्योगों में लगावें। उन पर इस तरह से कानूनी बंधन लगाये जायं तब पूंजी की समस्या, जिसका प्रश्न अक्सर उठाया जाता है, भी हल होगी।

छोटे उद्योगों के बारे में जो रुपया दिया गया है, वह पौने दस करोड़ रुपया है। लेकिन सन् १९४८–४९ से लेकर अब तक काटेज इंडस्ट्रीज के जरिये से जो आमदनी हुई है उसको देखें तो १३४.७ हुई। उसी दाम के आधार पर सन् १९५४–५५ में देखते हैं तब भी १३४.७ ही प्राप्त है। दामों की गिरावट के बाद भी देखें तब भी उतना ही १३४.७ ही रह जाता है, उसमें कोई भी प्रगति नहीं होती है। सरकार का ध्यान इधर जाना चाहिये अन्यथा इन सब रुपयों के व्यय से कोई लाभ नहीं होगा।

मुझे एक बात का डर है, उधर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। पिछली पंचवर्षीय योजना में १४९ करोड़ रुपया सारे हिन्दोस्तान में कल-कारखानों, वैज्ञानिक खोजों, धातुओं आदि के मद में रखा गया था लेकिन उसमें से केवल ७० करोड़ खर्च हुआ। इसी तरह से १०१ करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर के उद्योगों के लिए रखा गया लेकिन उसमें से ६० प्रतिशत ही खर्च होने की आशा है। संदेह है कि साढ़े ५ करोड़ रुपया जो व्यय हेतु प्रदेश के लिये रखा गया है वह भी खर्च न हो और वह अन्य मदों में डाल दिया जाय यह मेरी आशंका है पूर्व अनुभव के आधार पर।

अध्यक्ष महोदय, जमीन के बटवारे के बारे में जब बात उठायी जाती है तो वह कुछ लोगों को बहुत बुरी मालूम होती है। लेकिन बगैर जमीन के बटवारे के हमारी प्रारम्भिक समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान की रूप रेखा में प्रथम पंच-वर्षीय योजना की चर्चा करते हुए इस बात की चर्चा की गयी है कि "भूमिहीन खेत मजदूरों के प्रत्यक्ष फायदे के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। पिछले दो या तीन वर्षों में कुछ राज्यों के अन्दर किसान बड़े पैमाने पर बेदखल हुए हैं और उनसे खुद अपनी मरजी से खेत वापस करा लिये गये हैं। खुद अपनी मरजी से छोड़े हुए खेतों के अधिकांश मामले संदेहजनक हैं। प्लान फ्रेम में, कृषि क्षेत्र में उद्देश्य की घोषणा की गयी है कि :

"The fixation of ceilings and procedural arrangements for the redistribution of land to peasant cultivators must be decided at an early date in each state in accordance with the general principles and standards settled on an all-India basis, and the redistribution must be completed by 1958."

यह उद्देश्य ही प्रशंसनीय है। परन्तु इस तरफ कदम नहीं बढ़ा, यह शोचनीय है।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूं कि आपने मुझे इस सन् १९५६ और ५७ के आय-व्ययक के अनुदानों में अपनी सम्मति व्यक्त करने के लिए समय प्रदान किया।

[श्री गुप्तार सिंह]

श्रीमान् जी, आपके द्वारा मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है शायद भवन के इतिहास में इतना बड़ा और इतना उत्तम बजट और समाज के सब अंगों को शक्ति भर सहायता देने वाला बजट शायद कभी न उपस्थित किया गया हो। मैं श्रीमान् जी, साम्यवाद और समाजवाद का पंडित नहीं हूं। समाजवाद के पंडित समाजवाद के मामले में क्या व्याख्या करते हैं, यह तो वही जान सकते हैं, लेकिन मैंने जहां तक इस बजट को देखा, यह बजट समाज के कल्याणार्थ और समाज की गरीबी दूर करने के लिये ही बना है और यहां तक कि समाज के भिखारियों को शिल्प की शिक्षा देने के लिए और बेकारी दूर करने के लिए जहां तक हो सका है इसमें अपनी शक्ति भर कोशिश की गई है।

श्रीमन्, दो तीन रोज से सदन के अन्दर सिर्फ विवाद का विषय यह है कि यह बजट समाजवादी है या असमाजवादी है, और कोई तथ्य की बहस मैंने जहां तक समझा, इसमें नहीं हुई। हमारे प्रतिपक्षी नेता माननीय गेंदा सिंह जी ने जो अपना दो घंटे से ऊपर व्याख्यान दिया, जो कि भावुकता से और पार्टीबाजी से परिपूर्ण विदित हो रहा था, उन्होंने कोई तथ्य की बात नहीं बतायी है कि कैसे राज्य का संचालन किया जाय और समाजवादी ढांचा है क्या? यह तो उन्होंने बताया कि यह नहीं किया गया, अभी फलां की फीस नहीं माफ की गयी, स्कूल के मास्टरों की तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिये, दो सौ के नीचे के नौकरों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये, लेकिन एक बात छोड़ कर बजट में उन्होंने यह नहीं कहा कि फलां आंकड़ा बजट के अन्दर गलत रखा गया है और यह अनुदान पास न होना चाहिये। वह बात जो उन्होंने कहीं थी यह थी कि राज्यपाल को ३२ हजार की मोटर नहीं देनी चाहिये, यह एक तथ्य उनको १४७.४१ लाख के बजट के भीतर जो अनावश्यक प्रतीत हुआ वह राज्यपाल की ३२ हजार की मोटर का है। मेरे खयाल से उन्होंने बजट को आगे नहीं पढ़ा। क्योंकि जो सूचना अफसरों को १६-१६ हजार की आठ मोटरें देने के लिये १ लाख २४ हजार में खरीदी जाने वाली हैं और २० मोटरों की आवश्यकता है, वहां तक वे नहीं गये, सिर्फ राज्यपाल में अटक कर रह गये। शायद उनके खयाल से दो हजार की एक फटफटी राज्यपाल को दे दी जाती और वे बुलगानिन साहब को रिसीव करने जाते और बीच में वह फेल हो जाती, तब यह बजट समाजवादी हो जाता। या अगर एक टुटही मोटर खरीद करके इतने बड़े उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को दे दी जाती और उसमें चढ़ कर वे मार्शल टिटो और ईरान के शाह का स्वागत करने जाते और बीच में ही वह मोटर फेल हो जाती और जब वे पूछते कि राज्यपाल क्यों नहीं आये तो कहा जाता कि मोटर फेल हो गई तब शायद उनका समाजवाद हो जाता। या फिर एक पुराने जमाने की बैल गाड़ी उनको दी जाती जिस पर राज्यपाल दौरा करने को जाते तो समाजवाद व त्यागवाद दोनों हो जाते क्योंकि त्याग की बहुत बात की गयी है कि इससे अर्थात् मोटर से इज्जत नहीं बढ़ती है सिर्फ त्याग से इज्जत बढ़ती है और मुझे दुख है कि इतने बड़े भौतिकवादी जो कि सोशलिज्म के विचारों को मानने वाला हो वह यह कहे कि त्याग से इज्जत बढ़ती है, अगर ऐसा है तो बिनोवा भावे की नकल करो, लंगोटी बांध कर भूमि व द्रव्य मांगो, यहां इन कुर्सियों से तो त्याग की भावना नहीं पैदा होती, तो बैलगाड़ी अगर राज्यपाल को दे दी जाय तो अधिक त्याग भी होगा और काम भी बहुत होगा और जो कोई विदेशी मेहमान योरुप, अमेरिका, इंगलैन्ड, चैकोस्लोवाकिया, रूस आदि से आयेगा तो वहां बड़ी इज्जत हो जायगी। मेरे खयाल से उनकी कोई गवर्नमेंट होगी तो पुराने जमाने की बैलगाड़ी ढूंढ़ेंगे राज्यपाल के लिये।

हां, एक बात मेरी समझ में आयी है कि समाजवाद में शायद गेंदासिंह वाला कोई और समाजवाद हो क्योंकि इस वक्त समाजवाद की भी बीमारी चली है। एक गेंदासिंह जी का समाजवाद है जिस पर हमारे राजनारायणजी को विश्वास नहीं है। तो गेंदासिंह जी वाला समाजवाद अलग है और वे अपने समाजवाद की तरह सरकार बनाना चाहते हैं।

हमारे राजनारायण जी कहते हैं कि उनका समाजवाद अलग है और वे गेंदासिंह जी और झारखंडे राय जी दोनों के समाजवाद पर विश्वास नहीं करते, वे अपने समाजवाद की तरह सरकार बनाना चाहते हैं। इसके बाद एक तीसरा समाजवाद श्री झारखंडे राय का है। उनका समाजवाद ऐसा है कि वह न तो गेंदा सिंह जी के समाजवाद पर विश्वास करते हैं न राजनारायण जी के समाजवाद पर विश्वास करते हैं, वे अपनी समाजवादी सरकार बनाना चाहते हैं। अब ये तीन समाजवाद हो गये। तो जैसे सामन्त लड़ें तो तीसरा एक संतुलन पैदा करने के लिये समाजवाद रखा जाता है वही हमारे नेता जवाहरलाल जी और ढेबरजी ने एक हल निकाला है कि झगड़े वाले समाजवादों के बीच यह संतुलन करेगा। अगर आप लोगों के समाजवाद में झगड़ा है तो कृपा कर के आप इस समाजवाद में आयें जो सब जगह पहुंचा देगा, रूस भी पहुंचायेगा और टिटो के यहां भी पहुंचा देगा और अमरीका की सरहद में भी कोई जाना चाहे तो अपने को बेचेगा नहीं, लेकिन पहुंचा देगा। अध्यक्ष महोदय, अब इस विवाद में तो मैं अधिक समय अपना लेना नहीं चाहता क्योंकि हम जानते हैं कि समय केवल १५ मिनट का ही है। इतना तो हमने एक सेवक की हैसियत से अपने विरोधियों का जो कि हमारे विपक्षी हैं,उनका पथ-प्रदर्शन का काम किया है, जैसे कि सेवक लालटेन दिखाता है कि अंधकार में मत भटको, यही समाजवाद है जो उत्तम है यही ढेबर की दी हुई रोशनी हम दिखा रहे हैं।

अब मैं अपने वित्त मंत्री और अपने मंत्री समुदाय से एक प्रार्थना करता हूं कि आप में मेरा ही नहीं वरन् सारे सदन का पूरा विश्वास है और आप का कार्य पूर्णरूप से ईमानदारी से परिपूर्ण है। इसमें कोई शक नहीं है कि कल हमारे मित्र माननीय गोपीनाथ जी दीक्षित ने कहा कि राजा तो एक सूर्य का रूप होता है और यही चीज स्मृति में भी कही गई है। यही बात सदन में कई बार कही गई है कि जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों द्वारा जल को अपनी ओर आकर्षित करता है और अपनी ओर खींच लेता है और ग्रीष्म ऋतु में यथावत् उस जल को वृष्टि के रूप में भूमि पर बरसा देता है जिससे हमारी भूमि शस्य श्यामला बन जाती है। उसी प्रकार से श्रीमन्, मैंने पहले भी कई मर्तबा कहते सुना है कि आप जल को खींचते हैं और सूर्य की तरह ही बरसा देते हैं। लेकिन कभी आप ने यह भी सोचा कि दूषित वायु से ठंढक पाकर जब वह जल गिरता है और ओला बन कर गिरता है तो बजाय फायदा पहुंचाने के उलटे उसको क्षति पहुंचाता है। मैं आप से प्रार्थना करता हूं यह जो नौकरशाही की दूषित वायु है वह पानी को ओला बना देती है। यह मैं नही कहता कि आप के सब नौकर ऐसे ही हैं, बहुत से ईमानदार हैं लेकिन जो दूषित हैं वह पानी को ओला बना देते हैं और जिस गेहूं को आप प्रफुल्लित करना चाहते हैं, वह उसको नष्ट कर देता है। इस वायु को आप ठीक कर लीजिये जिससे पानी बरसे तो यह ठीक प्रकार से गेहूं, जौ और बेझड़ वगैरा पर बरसे और ऐसा न हो कि उल्टे यह आपकी खेती को ओला बनकर नष्ट कर दे।

श्रीमान् जी, अब लाल रोशनी हो गई है और मेरा समय खत्म हो गया है। इसलिये मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं लेकिन एक बात और कह देना चाहता हूं कि यह जो विकास जिलों के ऊपर आपने छोड़ा है और वह आपको आंकड़े देते हैं वह बहुत ही भ्रामक होते हैं। अगर मैं सत्य बात कहूं तो ऐसी ही हालत होगी जैसे कि कहा गया है कि:—

"जन प्रतिनिधि और वैद्य, गुरु, प्रिय बोलहिं भय आश,
तो राज धर्म तन तीन कर, होहि वेगही नाश।"

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आंकड़े ग़लत होते हैं। रायबरेली की एक नियोजन पुस्तकमाला छपी है। इसमें लिखा है कि वहां दो नलकूप बने हैं। वहां एक नलकूप है वह भी अधूरा है, पानी गंदा है और दो कहां से बन गये? क्या इस तरह के प्रचार से संसार में काम चल

[श्री गुप्तार सिंह]

सकता है? दूसरी बात यह है कि हमारे यहां खादी नियोजन का काम हुआ बताया गया है जिस से २५ मन और ३० मन सूत तैयार हुआ है और इसके बाद यह भी बताया गया है कि ६१५ व्यक्ति ट्रेन्ड किये गए हैं। मैं नहीं जान सका कि ये व्यक्ति कहां से मिल पाये लेकिन हमको ट्रेन्ड सूत वाले व्यक्तियों की जरूरत है अपने आश्रम के लिये लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि वे सब कहां चले गये। जिले में एक भी ट्रेन्ड नहीं हैं।

श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५६-५७ के बजट पर माननीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिये अत्यन्त अथक परिश्रम कर के यह बजट सदन के सम्मुख उपस्थित किया है। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता कि यह बजट समाजवादी है या नहीं। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि समाज कहते किसे हैं उसमें मैं यह जानता हूं कि आखिर आदमियों का ही नाम तो समाज है। अगर बजट यहां के किसानों के लिये, विद्यार्थियों के लिये, महिलाओं के लिये और हरिजनों के लिये कल्याण करने वाले आंकड़े पेश करता है तो हम लोगों को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि यह बजट उत्तर प्रदेश की जनता का कल्याण करने का बजट है।

जब हम लोग बजट पर दृष्टि डालते हैं और जब हम अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यों को देखते हैं तो हमको स्वीकार करना पड़ता है कि किसानों के लिये जो इन दिनों कार्य किये गये हैं उनमें अगला कदम हमारी सरकार ने बढ़ाया है। आखिर हमको यह देखना पड़ेगा कि हमारी समस्यायें क्या हैं और अगर उन समस्याओं को पूरा करने के लिये सरकार कदम बढ़ाती है तो हमको यह मानना पड़ेगा कि यह बजट जनता के लिये कल्याणकारी बजट है।

उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है जिसमें ८० फीसदी जनता किसानों की है। हम को यह देखना है कि क्या इस बजट से किसानों की समस्याओं का हल किया गया है अथवा नहीं। किसानों की समस्याओं को, जहां तक मैं विचार करता हूं, हम पांच भागों में बांट सकते हैं। किसानों के पास पहली चीज भूमि है। यहां उनकी भूमि की समस्या को हल किया गया। हजारों एकड़ भूमि में जहां पहले कांस होती थी और जो बंजर पड़ी थी, जो नष्ट-भ्रष्ट थी और जिसके लिये लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि कभी यह उपजाऊ हो सकती है, और लोग समझते थे कि ट्रैक्टर केवल आस्ट्रेलिया और कैनाडा में ही चला करता है, उस सब जमीन को उत्तर प्रदेशीय सरकार ने ट्रैक्टर चला कर ठीक किया है और भविष्य में भी इस बजट में भी उसको ठीक करने की योजना बनायी है। हमारे सोशलिस्ट भाई कहते हैं कि यह कल्याणकारी बजट नहीं है। आखिर उनकी परिभाषा क्या है, कल्याणकारी की मैं समझ नहीं पाया।

दूसरी बात जब हम देखते हैं प्रत्येक जिले में हजारों जगह, जगह-जगह पर बंधियां बनाई गई हैं और पानी एकत्रित किया गया है ताकि वहां की पैदावार बढ़े। मुझे ऐसे क्षेत्रों को देखने का मौक़ा मिला है जहां कतई पैदावार नहीं होती थी लेकिन आज उन्हीं क्षेत्रों में ५० हजार मन गेहूं पैदा होता है। छोटे-छोटे क्षेत्रों को देखने से पता चलता है कि आज वहां क्या कायाकल्प हो रहा है। किसानों की भूमि समस्यायें हल करने के लिये और दूसरी चीजें हो चुकी हैं, जमींदारी का विनाश हुआ, किसानों को समानता का अधिकार दिलाया गया और उन पर से जमींदारों का बोझ हटाया गया, चकबन्दी की योजना आज सारे उत्तर प्रदेश के अंदर फैलाई जा रही है और किसानों के सुख और कल्याण के लिये जो और दूसरे प्रबन्ध किये जा रहे हैं वह आखिर किसानों के लिये नहीं हैं तो किसके लिये हैं?

इसके बाद हम देखते हैं कि खेती की समस्या में किसानों के लिये भूमि के बाद दूसरा नम्बर पानी का आता है। अगर किसी के पास भूमि तो है और पानी का प्रबन्ध ठीक नहीं है तो किसान मुसीबत में रह सकता है। हमारी उत्तर प्रदेशीय सरकार ने मेरा ऐसा ख्याल है कि मनु महाराज के जमाने से, जब से ऐसा माना जाता है कि दुनिया बनी थी, तब से लेकर अब तक सारे हिन्दू, मुस्लिम और अंग्रेजी राज्यों में कभी सिंचाई का प्रबन्ध इतना नहीं हुआ जितना कि इस कांग्रेसी शासन में हुआ है। अगर इतना होने के बाद भी हम इसको स्वीकार नहीं करते तो यह अफसोस की बात है। समाज का कल्याण व्यक्तियों के कल्याण से होता है, पेड़ों, पत्थरों और पहाड़ों के कल्याण से नहीं। आखिर समाज का कल्याण आदमियों के लिये है उन आदमियों के लिये और किसानों के लिये लगातार इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि उनका जीवन सुखी हो। इस बात से आंख मीच लेना, लगातार नुक्ताचीनी करना और नुक्स निकालना उचित नहीं है। क्या नहीं हुआ है। हम तो कहते हैं कि जो हुआ है उसको आप देखिये जो नहीं हुआ है उसको अगले साल पूरा करने का प्रयत्न किया जायगा। यह सिंचाई का प्रबन्ध जो हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है वह बहुत बड़ा काम है। हमारे बुन्देलखंड में इतने बड़े बांध बांधे गये हैं जो बहुत बड़े काम के हैं। अकेले माता टीला बांध पर तीन करोड़ ८७ लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है। पूर्वी जिलों में नलकूप लगाये गये हैं। हजारों पानी के नलकूप बनाये गये हैं जिधर भी आप देखिये पानी का प्रबन्ध किया ज रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं जैसा कि एक कवि ने कहा है कि: "ध्यान लगा कर देखो मित्रो, सृष्टि की सुघराई को। बात बात में पाओगे उस कर्ता की चतुराई को।" श्रीमान् जी, मैं आपको बतलाऊं कि यह जो नहरों का जाल बिछाया गया है उससे अकेले यही लाभ नहीं हुआ कि खेतों को पानी मिला हो बल्कि उस सिंचाई से दूसरे लाभ भी हुए हैं। पशु पानी पीते हैं और जानवरों को पानी पीने को मिलता है। हमें किसानों से बात-चीत करने का मौक़ा मिला है तो सैकड़ों और हजारों किसानों को बतलाया गया कि गर्मी के दिनों में जहां पर ८०-८० हाथ गहरे कुओं से पानी निकाल कर पशुओं को पानी पिलाना पड़ता था अब उनको पीने और नहाने को खूब पानी मिलता है, चारों तरफ अब तालाब भरे हुये दिखलाई पड़ते हैं। सपरार बांध से जो सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है उससे लोगों की दिक्कत दूर हो गई है और जगह-जगह पानी भरा हुआ है। लोग साबुन से नहाते हैं और चिड़ियां आनन्द से पानी पीती हैं। अगर आप देखें तो आप को इन सब बातों का पता लगेगा। अब आप इस बात को देखिये कि जहां पर नहरें बनायी गयी हैं वहां पर उन नहरों के किनारे सड़कें भी बनायी गयी हैं। हमारे यहां गरौठा में जहां पर नहरें बनी हैं और जहां पर कोई नहीं जा सकता था अब वहां पर सड़क बन गयी है और मोटरें धड़ाधड़ चलती हैं। हर एक सड़क पर लोग आते जाते हैं। नहरों के निकालने से खेतों की सिंचाई होती है लेकिन यह फुटकर काम भी हुआ है जिससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है।

इसके बाद तीसरी चीज जो किसानों के लिये आवश्यक है वह बीज है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में दर्जनों बीज गोदाम खोले गये हैं जहां पर नये क़िस्म के बीज सप्लाई किये जाते हैं। उनके लिये नई बिल्डिंग बनायी गई हैं और कुछ नई बिल्डिंग बन कर तैयार हो चुकी हैं। वहां पर बीज सप्लाई किया जाता है और अच्छे खाद का प्रबन्ध किया गया है। किसानों के लिये रुपये की व्यवस्था की गई है। जहां पर सेठ साहूकार दो रुपया सैकड़ा पर लोगों को कर्जा दिया करते थे और १०० रुपये पर किसानों को २४ रुपया देना पड़ता था जो सवाया हो जाता था अब वहां पर किसानों के लिये कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये से रुपये देने का प्रबन्ध किया गया है। रुपये की सहूलियत भी किसानों के लिये की गयी है। हजारों कोआपरेटिव सोसाइटीज देहातों में खोली जा रही हैं। यह सब काम समाज कल्याण के लिये नहीं तो क्या है? इसके अलावा जो किसानों के लिये फुट कर काम हुआ है उससे भी समाज का कल्याण हुआ है।

[श्री राम सहाय शर्मा]

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है आप इस बात को देखिये कि हमारा उत्तर प्रदेश ही केवल ऐसा प्रदेश है जहां पर कई विश्वविद्यालय हैं। वहां पर दो विश्वविद्यालय और खोले जा रहे हैं। एक गोरखपुर में और दूसरा काशी का संस्कृत का कालेज था, उसको विश्वविद्यालय किया जा रहा है। डिगरी कालेज हमारे यहां खोले गये हैं और कई डिगरी कालेज और हाई स्कूल खोले जा रहे हैं। ५ हजार प्राइमरी स्कूल खोलने की योजना इस बजट में की गयी है। ८०० लाइब्रेरी कालेजों के अन्तर्गत खोली जा रही हैं। १,२०० कमरे एडेड स्कूलों में बनाने की सरकार ने योजना बनायी है। तो आखिर यह सारा काम किसके लिये हो रहा है। क्या विद्यार्थी हमारे समाज के अंग नहीं हैं? क्या किसान समाज के अंग नहीं हैं? स्थान-स्थान पर जो जिलों में यह महिला मंगल योजना चालू की गयी है और जच्चा-बच्चा के लिये जो अस्पताल बनाये जा रहे हैं, और अनेक प्रकार की जो योजना उनके लिये बनायी जा रही हैं वह क्या समाज के कल्याण के लिये नहीं हैं? मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि हर विषय में सरकार ने आगे कदम उठाया है। आप देखें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर २,११० मील सड़कें बनाने का प्रयत्न किया जायगा। जब सड़कें बन जाती हैं तो उनके मेन्टेनेन्स में भी व्यय होता है। जो सड़कें बनायी जायंगी, जो उनके रखरखाव पर व्यय होगा उस भार को वहन करने के लिये सरकार समर्थ है। दर्जनों चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। आदर्श अस्पताल भी हर जिले के अन्दर खोले जायंगे। २० साल पहले जब हम लोग जिलों के अस्पतालों में जाते थे तो दवाइयों का प्रबन्ध नहीं रहता था और न कोई मशीन थी। लेकिन आज वहां पर हर एक अस्पताल के अन्दर एक्सरे की मशीन है। हजारों प्रकार की दवाइयों का स्टाक रहता है। जगह-जगह पर क्वालिफाइड डाक्टर मिलते हैं। वहां पर जनता को पूरी-पूरी सुविधा देने का प्रबन्ध किया जा रहा है। आखिर ये कल्याणकारी कार्य नहीं हैं तो क्या हैं? वे जनता के लिये नहीं हैं तो किसके लिये हैं? यह बजट समाज के कल्याण के लिये नहीं है तो फिर किसके कल्याण के लिये हैं? समाज का कल्याण फिर किसे कहते हैं? कोरी हवाई बातें कहने से तो काम नहीं चल सकता है।

मैंने अभी पिछले दिनों गर्मियों के दिनों में, अपने जिले में अपने क्षेत्र में देखा कि हमारे एक सोशलिस्ट कार्यकर्ता ने इस बात के पर्चे छपवाकर बांट दिये कि लोगों को लगान नहीं देना चाहिये। कितना सस्ता सौदा उन्होंने यह ढूंढ निकाला। मैंने वहां पब्लिक को बतलाया कि यह अफ़ीमचियों की सी बात है। कोई राज्य दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें लगान नहीं लिया गया हो। अगर वह लोग किसान को बरगलाने के लिये ऐसी बातें करेंगे तो उनके आदर्श को जनता नहीं मानेंगी। किसानों ने उनकी बात नहीं मानी और लगान दिया। अगर उनका यह दावा है कि कांग्रेस के राज्य से कल्याण नहीं हो सकता और उनके कामों से जनता खुश होती है तो क्या कारण है कि उनको जनता नहीं चुनती है? बात यह है कि आप के ऊपर जनता विश्वास करने के लिये तैयार नहीं है। इसीलिये कांग्रेस के इतने अधिक लोग यहां चुनकर आते हैं। ट्रावनकोर कोचीन में आपकी सरकार का शासन आया लेकिन उसे आप नहीं चला सके। तो फिर इतने बड़े उत्तर प्रदेश का शासन का कार्य आप कैसे चला सकते हैं। यह तो आप के लिये स्वप्न की चीज होगी। महज हवाई बातें हांकने से दुनिया का काम नहीं चलता है। उन्हें देखना चाहिये कि जगत में व्यावहारिक बात क्या है?

अगर आप बजट के आंकड़ों को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इससे समाज प्रगति करेगा। आज दुनिया के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं कि हिन्दुस्तान ने और विशेष कर उत्तर प्रदेश ने ऐसे बड़े कदम उठाये हैं जिनसे वहां बड़ा संतोष है। मैं समझता हूं कि हमारे सोशलिस्ट भाइयों को यह बात सोचनी चाहिये और रचनात्मक सुझाव देने चाहिये। मालूम पड़ता है कि बहुत से लोग इधर

उधर की लोगों की बातें सुन कर कह देते हैं कि हम तुम्हारे लिये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हवाई बातों में गरीब आदमियों को फांस कर, उनको ग़लत प्रकार के प्रलोभन दे कर इस प्रकार की बातें कह देते हैं जिससे उन्हें ऐसा खयाल रहता है कि वे इस प्रकार का विध्वंस कर देंगे या उलट देंगे। हमारा जो आदर्श पहले था वही अब भी है। जब सैलरी बिल पास हुआ तो हमारे इन भाइयों ने कहा था कि लाखों रुपये का खर्च सरकार ने बढ़ा दिया है। आप बजट से देख सकते हैं कि जहां ७ लाख रुपया आप के लिये खर्च होता था अब ६ लाख २८ हजार रुपया इसमें है, यानी ७२ हजार रुपये की किफायत हो गई। मैं अपने सोशलिस्ट भाइयों से और दूसरे भाइयों से अपील करता हूं कि वे इस बात को ध्यान पूर्वक देखें। हमारे कुछ भाइयों ने कहा है कि पुलिस का प्रबन्ध ठीक नहीं है और सरकारी अफसरों का व्यवहार ठीक नहीं है। वे लोग भी मनुष्य हैं और ग़लती कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में इस देश का शासन चला रहे हैं, उनके अफ़सरों में इतनी योग्यता है और वे अपने प्रेम और व्यवहार से उनके ऊपर ऐसा जादू करते हैं कि देश का शासन कितनी अच्छी तरह से वे लोग चला रहे हैं। यहां प्रदेश में हमारे सम्पूर्णानन्द जी हैं और उनके चीफ़ सेक्रेटरी हैं, और दूसरे कई सेक्रेटरी हैं, जिनके द्वारा शासन चलाया जाता है। इसलिये हमारे एम० एल० एज० को भी अपनी नम्रता और रचनात्मक काम के द्वारा ऐसे कार्य करने चाहिये जिससे वे जिले में वहां के अफ़सरों के साथ प्रेम से कार्य कर सकें। उनको अफ़सरों की शिकायत नहीं करनी चाहिये। हमको अपनी बुद्धि और व्यवहार से अफ़सरों को प्रभावित करना आवश्यक है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी बार-बार ऐसी बात करता है जानबूझ कर कि जिससे जनता का अहित होता है तो हम उसे शासन के द्वारा भी ठीक कार्य करने को मजबूर कर सकते हैं। लेकिन यह भी एक्सपेरिमेन्ट आप को करना आवश्यक है। इतना कह कर मैं सरकार को कल्याणकारी बजट पेश करने के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं आप को ही धन्यवाद दूंगा कि इस बजट के सामान्य वादविवाद पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया है। इसके पश्चात् मैं अपने माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना का अन्तिम बजट और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रथम बजट हमारे सदन के सामने प्रस्तुत किया है। इस बजट को देखने से हमें पता चलता है कि पिछले बजट से यह डेढ़ गुना बढ़ गया है। आज १ अरब ४७ करोड़ का बजट है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रथम बजट होने के नाते हमें यह अन्दाजा लगता है कि हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी तेजी के साथ क़दम बढ़ा रहे हैं। डेढ़ गुनी प्रगति हमको जाहिर होती है। आप देखेंगे कि हर दृष्टिकोण से हर विभाग में धन की वृद्धि हो गई है। पूरे बजट में सभी आंकड़ों को और प्रत्येक विभाग के अलग-अलग कार्यों को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, और चाहे उद्योग विभाग हो, कोई हमारे प्रदेश का विभाग हो, सब में हम इस प्रकार का परिवर्तन देखते हैं कि हम सचमुच समाजवादी राज्य की स्थापना कर रहे हैं। जब हम बजट को देखते हैं और इसके कार्यों को देख कर इसकी स्थिति का अनुभव करते हैं तो हमको यह पूर्णरूप से अनुभव होता है कि सचमुच हमारे सामने समाजवादी ढांचा आने वाला है। हमें पता चलता है कि हमारे समाजवादी ढांचे का रूप कैसा होगा। आखिर समाजवादी ढांचा उसे ही तो कहा जा सकता है जिससे हमारे रहन सहन का स्तर ऊंचा हो, हमारे बीच में समता का व्यवहार हो, छोटे लोग ऊंचे उठें और अन्तर कम हो। इस बजट में जो धन व्यय किया जायगा उससे इस प्रकार की चीजें हमको मिलती हैं कि सचमुच छोटे रोजगारों को बढ़ाने की व्यवस्था इसमें की गई है। निवास का प्रबन्ध किया गया है और हमारा छोटा वर्ग उन्नति कर सकता है। निवासों के लिये ही हम देखते हैं कि जगह-जगह पर निवास स्थान फ्री बनने जा रहे हैं। छोटे धन्धों के लोगों के लिये

[श्री श्री नाथराम]

और छोटी तनख्वाह वालों के लिये हम देखते हैं कि लेबर कालोनीज और तरह-तरह के मकान बनाने की व्यवस्था इसमें है और अधिक से अधिक धन व्यय करने का प्रयास है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे निवास के प्रबन्ध में हमारे लिये जो सब से बड़ी कठिनाई है हमारी धन की कमी के कारण, वह यह है कि हमारे रहने के स्थान साफ-सुथरे नहीं हैं। हमारे स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है और अधिक कार्य करने की क्षमता हममें नहीं रह जाती है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम देश की पैदावार अधिक बढ़ा सकेंगे। हम देखते हैं कि इसकी भी व्यवस्था बजट में की गई है। हमारी बहुत बड़ी संख्या शिक्षा से महरूम रहती है परन्तु अब उनके लिये भी इस बजट में प्रबन्ध है। बच्चों की फ़ीस में कमी कर दी गई है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि शिक्षा की प्रगति तेजी के साथ हुई है। जो छोटी तनख्वाह पाने वाले आदमी हैं उनका किसी भी प्रकार से व्यवस्था नहीं होती है लेकिन इस बजट में उनको भी आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई है। जब हम देखते हैं कि इस प्रकार से हम अपनी आर्थिक दशा को सुधार सकेंगे, शिक्षा में प्रगति कर सकेंगे तो हमें ज्ञात होता है कि हम उन्नति के रास्ते पर जा रहे हैं।

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और उसमें सिंचाई का न होना बड़ी हानिकारक चीज है, लेकिन हम इस बजट में उसके साधनों की व्यवस्था भी देखते हैं और उसके द्वारा हम सिंचाई की व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे-धीरे नलकूपों का बढ़ाया जाना, नहरों और बांधों का बढ़ाया जाना यह स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है।

जब हम दूसरी ओर उद्योगधंधों की ओर आते हैं तो हमें मालूम होता है कि उनके द्वारा बेकारी और बेरोजगारी को दूर किया जा रहा है। छोटे उद्योग धंधों को उन्नतिशील बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यही हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। पहली पंचवर्षीय योजना का हमारा लक्ष्य था कृषि के साधनों को बढ़ाना, सिंचाई को बढ़ाना, और इस प्रकार से उत्पादन को बढ़ाना लेकिन इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें सब से अधिक जोर बेरोजगारी पर देना है और इसीलिये उद्योग-धंधों को बढ़ाये जाने का सब से अधिक प्रयास किया गया है। इसके द्वारा हमारे प्रदेश में हर आदमी रोजगार पायेगा, बेकारी की समस्या हल हो सकेगी। इसीलिये हम कहते हैं कि यह बजट हमारे लिये सब से महत्वपूर्ण बजट है और यह हमारे देश की गरीबी और भुखमरी को दूर करेगा। जब हम इस दृष्टि से इस बजट को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि यह अवश्य ही कल्याणकारी बजट है और समाजवादी ढांचे को निर्माण करने के लिये यह प्रथम प्रयास किया गया है। यदि हम इस दृष्टिकोण को रखेंगे तो अपने प्रदेश को हम उन्नतिशाली बना सकेंगे।

इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी समस्यायें हमारे सामने हैं जिनको हल करने की आवश्यकता है। हममें जो सब से बड़ी कलंक की बात है वह हमारे नैतिक स्तर का गिरा हुआ होना है। जब तक हम इस ओर अपना कदम नहीं बढ़ायेंगे तब तक चाहे कितने ही हम आर्थिक मामलों में आगे बढ़ जायं, चाहे कैसी ही आर्थिक स्थिति हमारी ठीक हो जाय लेकिन अगर हमारे अन्दर भ्रष्टाचार और हमारा नैतिक पतन है तब तक हम यह नहीं कह सकते कि हम गौरवान्वित हुए हैं और न हम अपने देश को समाजवाद के असली रास्ते पर ही ला सकते हैं। भ्रष्टाचार का उदाहरण अध्यक्ष महोदय, मैं पेश करूं। एक छोटे से आबकारी विभाग को ही ले लीजिये। एक्साइज इन्सपेक्टर को ताड़ी के व्यापारियों से ही ५० हजार रुपया सालाना की आमदनी होती है और अगर उसका हिसाब लगाया जाय तो इस प्रकार से होता है कि जब ताड़ी का ठेकेदार रुपया जमा करने के लिये जाता है तो एक्साइज इंसपेक्टर उससे ६ रुपया फी ताड़ के हिसाब से लेता है। २ रुपया ६ आना फी फार्म के हिसाब से लेता है, एक रुपया ताड़ के पेड़ पर नंबर लगाने का लेता है, और जब

वह जमा करने के लिये जाता है तो १ रुपया फी ताड़ के हिसाब से उसको फिर देना पड़ता है। इस प्रकार से लगभग १० रुपये ६ आना फी ताड़ के हिसाब से एक्साइज इंस्पेक्टर अथवा उसके कर्मचारी ठेकेदार से ले लेते हैं। अब प्रत्येक ठेकेदार के पास १२०—१२५ के क़रीब पेड़ होते हैं और प्रत्येक इंसपेक्टर के क्षेत्र में ६०—७० ठेकेदार होते हैं। इस प्रकार मोटा हिसाब लगाया जाय तो आप देखेंगे कि एक-एक इंसपेक्टर को ५० हज़ार रुपया सालाना की आमदनी होती है जब कि आप अफीम, गांजा और शराब को छोड़ ही दें। हमने जब इस प्रकार की चीजें देखीं और ठेकेदार मेरे पास आये तब मैंने वहां जांच पड़ताल की और यह मालूम हुआ कि एक्साइज इंस्पेक्टर को ५० हजार रुपये सालाना की आमदनी होती है जब दूसरी चीजों को छोड़ दीजिये तब। अब इसका बटवारा कैसे होता है इसका भी एक छोटा सा उदाहरण रखता हूं। रिश्वत के मामले से जो सारी आमदनी होती है उसमें से ७ फी सदी सिपाही ले लेता है, १६ फी सदी सुपरवाइजर ले लेता है और बाक़ी सब पैसा एक्साइज इन्सपेक्टर साहब की पाकेट में जाता है। इस प्रकार की चीज को देखकर आश्चर्य होता है कि सरकार के पास जो पैसा पहुंचता है उसके अलावा कितना रुपया दूसरों के पाकेट में चला जाता है। इस तरह के कितने ही उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं कि किस-किस तरह के भ्रष्टाचार हमारे देश में फैले हुये हैं। जब तक इस चीज को खत्म करने का प्रयत्न नहीं किया जायगा तब तक हम इस बात का दावा नहीं कर सकते कि समाजवादी ढांचे का समाज हम यहां पर लाना चाहते हैं। आर्थिक मामलों में तो हम प्रगति कर सकते हैं, शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं, दूसरे क्षेत्रों में भी प्रगति कर सकते हैं लेकिन जब तक नैतिक स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक हमारे देश का कल्याण होना हम तो समझते हैं कि सम्भव ही नहीं है।

दूसरी चीज में आपके सामने यह रख देना चाहता हूं कि इस बजट में ९ १/२ करोड़ रुपये का घाटा है और इसकी पूर्ति तरह-तरह के टैक्स लगा कर की जायगी। टैक्स लगाना हमारे लिये आवश्यक है इसलिये कि हम चाहते हैं कि हमारे देश का निर्माण-कार्य आगे बढ़े। तरह-तरह के क्षेत्रों में हम निर्माण-कार्य करना आवश्यक समझते हैं जिससे हमारी सारी समस्यायें हल हो जायं। आर्थिक मामलों में और दूसरे निर्माण कार्य कर के हम अपने देश की उत्पत्ति बढ़ा सकते हैं, उद्योगधंधों और कृषि का उत्पादन भी बढ़ा सकें इसलिये जो नलकूप, जो पावर हाउस, जो बांध और जो नहरें बनाई जायंगी उस के लिये धन की आवश्यकता होगी। और उसकी पूर्ति हम तरह-तरह के टैक्स लगा कर करेंगे। लेकिन इस टैक्स के मामले में पिछले साल भी हमने कहा था कि हमारे यहां सेल्स टैक्स लग रहा है, लेकिन जो सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है, हमारा नैतिक स्तर इतना गिर गया है कि उसको देख कर आश्चर्य होता है। मऊ में कपड़े का व्यापार होता है, सूत की खपत वहां पर बहुत ज्यादा होती है और उस पर सेल्स टैक्स लगता है लेकिन आश्चर्य होता है कि करीब ५ लाख रुपये सेल्स टैक्स से सूत पर केवल मऊ से मिलता है। अगर सचमुच अच्छे प्रकार से टैक्स वसूल किया जाय तो मैं समझता हूं कि १२, १३ लाख रुपया मिल सकता है लेकिन बाकी ७ लाख नहीं मिलता है। यह रुपया व्यापारी चोरी करता है और इस चोरी के करने में सरकार को घाटा होता है। मैं चाहता हूं कि जो सेल्स टैक्स सूत पर लगाया जाता है उसका हिसाब उसी तरह से लगना चाहिये जैसे और बहुत सी लाइसेंस की चीजों पर जैसे कोयला, लोहा और सीमेंट आदि पर होता है अर्थात् जो चीजें व्यापारी खरीद कर ले आते हैं उसको सप्लाई डिपार्टमेंट जो है वहां देखा जाता है. कि किस व्यापारी के पास कितना माल आया। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार सूत का भी हिसाब वहां पर रखा जाय और वहां पर ही उसके सेल्स टैक्स का मामला भी चेक हो जाय ताकि जो माल बाजार में आता है उसका अन्दाजा हो जाय और फिर सेल्स टैक्स लगे। दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जैसे मैंने अभी-अभी बताया कि सही पैसा सेल्स टैक्स से वसूल नहीं होता है। मेरा सुझाव अगर उचित समझिये तो यह है कि मिलों से जिस वक्त कपड़ा निकलता है, उसकी निकासी होती है उस वक्त मिलों से निकलते

[श्री श्री नाथराम]

समय व्यापारियों से टैक्स वसूल कर लिया जाय ताकि वहां जो चोरियां हुआ करती हैं, जो गलत सही बहियां पेश कर दी जाती हैं वह नहीं होने पावे। इस चोरी का नतीजा आज यह होता है कि जिस धन का हम अन्दाज लगाते हैं कि उस माल से मिल सकता है उतना धन नहीं मिलता।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं जो उन्होंने इस साल का बजट प्रस्तुत किया है। उस बजट में हमारे प्रान्त का नक्शा सही-सही रूप में दिखायी देता है, इससे हमें विदित होता है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था दिन प्रति दिन कितनी उन्नति की ओर बढ़ती ही जा रही है। अभी तक सदन में २ दिन से लगातार यही चर्चा रही है कि इसमें समाजवाद पैटर्न का कोई नक्शा दिखायी देता है या नहीं, मैं इन चर्चाओं में न पड़कर सिर्फ इसी पर अपने को सीमित रखूंगा जिस से कि मेरा बिलकुल व्यक्तिगत सम्बन्ध है, खासकर पर्वतीय प्रदेश के लिये बहुत कम चर्चा अभी तक इस सदन में इस बजट के दौरान में हुयी है। इसलिये मैं चाहूंगा कि पर्वतीय प्रदेश के बारे में ही अपने को सीमित रखूं। यहां बड़े-बड़े महानुभाव जो बड़ी-बड़ी योजनाओं और बड़े सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं तक और बातों को छोड़ूंगा।

मैंने अध्यक्ष महोदय, इस बजट भाषण को बड़े ध्यान पूर्वक सुना और पढ़ा भी। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि पर्वतीय प्रदेश के लिये कई किस्म की धनराशियां इस में रखीं गयीं मगर उन धनराशियों के रखे जाने पर भी जो पर्वतीय प्रदेश की समस्यायें हैं उन का हल बिलकुल उन से नहीं हो सकता, भले ही इससे थोड़ी बहुत वहां की समस्यायें हल हो जायं मगर पर्वतीय प्रदेश हमेशा से, कई शताब्दियों से पिछड़ा हुआ रहा और अब भी वह पिछड़ा हुआ ही है। अंग्रेजी हुकूमत भी उन की अवहेलना करती रही क्योंकि उन प्रदेशों में न तो कोई कारोबार हैं न कोई उद्योग हैं और न वहां कृषि ही ऐसी होती है कि वहां की आर्थिक व्यवस्था सुधर सके और वे आत्मनिर्भर (सेल्फसफीशियेन्ट) हो सकें। लेकिन अब तो प्रजातंत्र राज्य कायम हो गया है तो यह देखना नहीं है कि कहां से कितनी आय होती है और उसी आमदनी के अनुपात से वहां खर्च किया जाय बल्कि देखना यह चाहिये कि कौन सबसे ज्यादा डिजर्विंग है, कौन सब से ज्यादा पिछड़ा और गरीब है—उनकी सहायता करना सरकार का सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए।

मैं जिला अल्मोड़ा के बारे में सरकार का ध्यान खास तौर पर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिले के बेसिस पर यहां से अनुदान दे दिये जाते हैं मगर उन अनुदानों का खर्च उन्हीं जगहों पर हो रहा है जहां कि अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में काफी विकास था; जैसे पर्वतीय प्रदेश में अगर आप देखें तो सिर्फ नैनीताल, रानीखेत या अल्मोड़ा जो प्रमुख स्थान हैं उन्हीं के विकास पर अब भी खर्च किया जा रहा है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उनका ध्यान उन्हीं जगहों पर सीमित न रहकर बार्डर के इलाकों पर भी जाय जैसे भोटिया और बोरा आदि जातियों के क्षेत्र हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जान कर आश्चर्य होगा कि इस जमाने में मेरी कांस्टीट्युएन्सी में ऐसे इलाके भी हैं जहां के लोग कमर में रस्सी बांधकर, चार अंगुल का कपड़ा लपेट कर जिसे यहां लंगोटी कहते हैं बिना सिये हुये ही चिथड़े पहन कर गुजर करते हैं। इतने गरीब इलाके से मैं प्रतिनिधि हो कर आया हूं, मेरी वेष-भूषा को देखकर यहां गलतफहमी हो जाती है कि वह इलाका भी शायद ऐसा ही हो और मेरी इन बातों का शायद इतना जोर भी न होता हो लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरी इच्छा तो होती है कि वहां का प्रतिनिधि ऐसा ही आता जैसा कि वह इलाका है तो वह वहां की बातों को और अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सकता। मैं उन लोगों की बातों को अपने मुख से जाहिर नहीं कर पाता हूं कि वहां के लोग कितने गरीब हैं और दुखी हैं, उस का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूं कि उसका सही प्रदर्शन इस सदन में कर सकूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उस इलाके में खाने की बहुत कमी है, मेरे पास आजकल तार आ रहे हैं कि उस डेफिसिट

क्षेत्र में लोग भूख से कितने पीड़ित हैं और कितना हाहाकार वहां पर मचा हुआ है। पिछले साल तक सप्लाई विभाग की ओर से यह व्यवस्था वहां के लिये थी कि वहां सब्सीडाइज्ड ग्रेन वितरित होता था जिससे वहां के लोगों के प्राणों की काफी रक्षा होती थी लेकिन दुर्भाग्य है कि अब वह भी सरकार ने बन्द कर दिया जिस के कारण आजकल बहुत आंतक छाया हुआ है। अब यहां से अनाज भेजा भी जायगा तो वह उन्हीं जगहों को जायगा जो प्रमुख स्थान हैं, लेकिन जो दूर के इलाके हैं जहां मोटरें नहीं जा सकतीं, जहां लोगों को खाने के लिये नहीं है, जहां के लोग अपने भावों को सरकार तक प्रदर्शित नहीं कर सकते वहां के लोग उस से महरूम ही रह जाया करते हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस विचारधारा को लेकर वहां की असली परिस्थिति को पूरे-पूरे तौर से समझने की कोशिश करेगी। मैं आज इस अवसर का पूरा लाभ उठाकर यह भी सरकार के सामने कहना चाहता हूं कि अगर उनकी हालत को वर्णन न करूं तो मैं अपने कर्त्तव्य का पालन न कर सकूंगा। जहां तक अलमोड़े जिले का सवाल है उसमें साढ़े ७ लाख आबादी है, और वह बहुत फैला हुआ क्षेत्र है लेकिन यहां से जो वहां के लिये धनराशि मिलती है वह वेस्ट अल्मोड़ा में ही खर्च हो जाया करती है, चाहे वह शिक्षा का कार्य हो, सड़कों का हो, चिकित्सा का हो या एन०ई०एस० ब्लाक्स आदि का हो। हर एक विकास का कार्य पश्चिमी भाग में ही होता है और पूर्वी भाग वैसे का वैसा ही रह जाता है। माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी अभी हाल में उस इलाके में दौरे पर गये थे उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, जिला नियोजन के बड़े बड़े अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर सब से पहले इसी बार उस इलाके में उनके साथ गये थे, वहां के बड़े कर्मचारियों के बारे में तो कहना ही क्या है, उस इलाके की जो व्यवस्था है उसके बारे में न तो उनको कुछ जानकारी है और न कुछ करने की इच्छा ही वहां के लिये कोई रखता है और न सोचता है। मुझे दुख है कि ऐसी हालत में सरकार उस ओर खास ध्यान नहीं देगी तो यह जो व्यवस्था कायम है इसमें सुधार नहीं हो सकता।

जिला नियोजन कमेटी के बारे में मैं बताऊं कि पिथौरागढ़ से एक आदमी जिला नियोजन कमेटी में अगर आता है तो उसे ४ दिन का सफर करना पड़ता है। उसको सौ मील मोटर से, फिर १५० मील रेल से और फिर सौ मील मोटर से सफर करना पड़ता है, और इस सफर में उसको करीब ५०-६० रुपया खर्च करना होता है। उसका नतीजा यह है कि पूर्वी क्षेत्र का कोई मेम्बर जिला नियोजन कमेटी में नहीं जाता और जिला अल्मोड़ा के पश्चिमी भाग में ५–६ कम्युनिटी प्रोजेक्ट और एन०ई०एस० ब्लाक्स बन चुके लेकिन पूर्वी क्षेत्र में केवल एक ही एन०ई०एस० ब्लाक खुला है। जिला नियोजन कमेटी में यह हुआ करता है कि जितने एन० ई०एस० ब्लाक बनें वह पश्चिमी क्षेत्र में बनें और जितना रुपया सड़कों या अस्पतालों के लिये मिल रहा है और श्रमदान की योजनाओं के लिये मिल रहा है उन का अधिक अंश पश्चिमी क्षेत्र में खर्च कर दिया जाता है। ऐसे ही जिला बोर्ड की योजनाओं को लिया जाय तो यह देखा जाता है कि जो स्कूल खोले जाते हैं, अस्पताल खोले जाते हैं या सड़कें बनायी जाती हैं, हर प्रकार की सुविधाओं के लिये पश्चिमी क्षेत्र में ही खर्च किया जाता है और पूर्वी क्षेत्र उनसे महरूम रह जाया करता है। प्रशासन के दृष्टिकोण से लिया जाय या किसी भी दृष्टिकोण से लिया जाय तो मेरा मत है और उस इलाके की जनता का निश्चित मत है कि इस जिले के दो जिले हो जायं तभी यह जिला पनप सकता है और इसका प्रशासन भी सुचारु रूप से चल सकता है और भविष्य भी वह का उज्वल हो सकता है। पश्चिमी क्षेत्र से मेरी कोई इल विल नहीं है, हम सब को एक ही समान दृष्टि से देखते हैं किन्तु प्रशासन की दृष्टि से यह नितांत आवश्यक है कि इस विशाल जिले के दो भाग कर दिये जायं तो हर प्रकार से इस जिले की तरक्की हो सकती है। मैं इन्हीं विचारधाराओं को सरकार के सामने रखता हूं और अगर न रखूं तो अपने कर्त्तव्य को पूरा-पूरा नहीं निभाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे विचारों को उसी दृष्टि से देखेंगे और पूरी–पूरी छानबीन करेंगे कि मेरी बातों में कितना तथ्य है और उस जिले में क्या क्या काम किये जा सकते हैं। वैसे तो मुझे बहुत सी बातें कहने को थीं मगर मैं जल्दी में थोड़ी-थोड़ी बातों पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि समय बहुत सीमित है। अगर हमारे जिले की दशा को देखेंगे तो आप को वाकई यह महसूस होगा कि इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ वहां करना आवश्यक है।

[श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट]

वहां की बेकारी की समस्या को लें, तो हमारे जिले में जब अंग्रेजी हुकूमत थी, तो वहां से मिलिटरी में बहुत लोग जाया करते थे। यद्यपि पर्वतीय प्रदेश में कोई इंडस्ट्री नहीं थी लेकिन वहां मार्शल स्प्रिट होने के कारण कुमायूंनी रेजीमेंट ने बहुत नाम कमाया है। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के जाने के बाद, मार्शल रेस खत्म कर दी गयी और कहा गया कि देश का प्रत्येक व्यक्ति देश भक्त है और सब को समान अधिकार है कि आर्मी में लिये जायं। इस प्रकार जो यह रोजगार का जरिया था वह भी खत्म हो गया। आजकल जितना भी रिक्रूटमेंट होता है उसमें बहुत कम कुमायूंनो लिये जाते हैं। इसलिये बहुत ज्यादा बेरोजगारी वहां पर हो गयी है। वहां कोई इंडस्ट्री ऐसी है नहीं जिसको सरकार ने पनपाया हो। मैंने पहले बहुत दफा सरकार का ध्यान आकर्षित किया। बहुत काटेज इंडस्ट्री तो नहीं हो सकतीं लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिनके सम्बन्ध में वहां बहुत सी योजनायें बन सकती हैं। खासकर जो उनमें सब से महत्वपूर्ण है वह है माइनिंग इंडस्ट्री! मुझे पर्वतीय प्रदेश के कई तरह के पत्थर जो वहां कई जगह मिलते हैं, कई लोगों ने दिये थे और मैंने उनको सरकार के सामने अन्वेषण के लिये पेश किया और बतलाया भी गया कि कुछ सम्भावना पायी जाती है खासकर अबरक के लिये बताया था, और वह इतना बढ़िया अबरक बताया गया है कि ८ सौ रुपये मन बिक सकता है। मैं महज इस ख्याल से कि वहां के लोगों को रोजगार का एक जरिया मिल सके और साथ ही साथ हमारे देश की उन्नति हो यह सुझाव देता हूं कि अगर इन खनिज पदार्थों की ओर सरकार अपना ध्यान दे तो काफी ऐसी चीजें हैं कि जो हमें पर्वतीय क्षेत्रों से मिल सकती हैं,जैसे चांदी, लोहा,तांबा, जिप्सम, खरिया मिट्टी, अबरक और गंधक कई किस्म की खानें जिला अल्मोड़ा में हैं जो कि सारे जिले में कई जगहों पर इस खनिज पदार्थों की मेन्स चली गयी हैं। सारे पर्वतीय प्रदेश में और खास कर, नैपाल तक व हिमांचल प्रदेश की ओर बतलाया जाता है कि ये खनिज पदार्थ फैले हैं। इसका अगर अनुसंधान किया जाय तो पूर्ण आशा है कि इस इलाके में बहुत ज्यादा काम हो सकता है। इसके अलावा कई और इंडस्ट्रीज हैं जिनके सम्बन्ध में सरकार को कई दफा लिखा भी गया खासकर वन की इंडस्ट्री। वन हमारे देश में बहुत फैले हुए हैं। वहां कई कई किस्म की चीजों की इंडस्ट्री कायम की जा सकती है। थोड़ा बहुत विकास जो होने भी लगा है उसमें मुझे दुख यह है कि जो ग्रान्ट और लोन हमें सरकार से मिलता है, वह दूर-दूर के इलाके हैं, जो बहुत गरीब हैं, पहले वहां इंडस्ट्रीज थीं लेकिन अब वह अपनी गरीबी के कारण उन्हें नहीं चला पाते, उनको कोई सहायता सरकार से नहीं मिल पाती, जितनी थोड़ी बहुत सहायता मिलती है वह अल्मोड़े तक ही सीमित हो जाती है। जो लोग धनी हैं, जिनकी अप्रोच हो सकती है उन्हीं तक यह सीमित होती है। जो वहां की गरीब जनता है, लोहार, चमार, और टमटा हैं, ऐसे लोग जो छोटे-छोटे उद्योगों को करते हैं उन बेचारों को सहायता मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती कि उन लोगों को यह चीजें मिल सकतीं तो बहुत कुछ उन्नति पर्वतीय प्रदेश की की जा सकती थी। खासकर हरिजनों के लिये मुझे कहना है। मैं देखता हूं कि जिला अल्मोड़ा में जितना काम हरिजनों के लिये होता है वह वेस्ट अल्मोड़ा तक ही सीमित रहता है। हरिजनों के लिये मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे यहां उनको ग्रान्ट मिलती हो। जो चीजें सरकार कर रही है बड़ी-बड़ी योजनायें हैं, बड़ा अच्छा लक्ष्य है, बड़ी अच्छी भावना से चलायी जा रही हैं लेकिन उसका समान वितरण नहीं हो रहा है, और जो नीचे स्तर की जनता है उसको उसका सही सुख नहीं प्राप्त हो रहा है।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)—मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर को, उनकी काबिलाना तकरीर और बजट पर मुबारकबाद देता हूं। हुजूरवाला, दो रोज से इस बजट पर बहस हो रही है। हमारी गवर्नमेंट की नीयत पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि यह बजट जो है वह समाजवादी बजट नहीं है। मैं हुजूरवाला, इस गवर्नमेंट की नीयत की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता

हूं जो इससे जाहिर होगी कि जो एक रिजोल्यूशन सन् ४६ में १३ अगस्त को इसी भवन में पेश किया गया था। हिन्दुस्तान का सोशलिस्ट पार्टी का वजूद भी नहीं था जिस वक्त कांग्रेस सरकार ने यह रिजोल्यूशन पेश किया था, और जो आजकल माननीय मुख्य मंत्री हैं वे उस वक्त मिनिस्टर आफ एजूकेशन और फाइनेंस थे, उन्होंने पेश किया था। मैं आपकी इजाजत से अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं।

"This Assembly is of opinion that liquidation of capitalism in all its forms is essential to the well being of society and trusts that necessary steps to bring about the socialisation of the principal means of production, exchange and distribution, will be taken as soon as possible."

तो हुजूरवाला, आप देख सकते हैं जिस गवर्नमेंट का सन् १९४६ से यह रुख हो और उस समय के एजूकेशन और फाइनेंस मिनिस्टर साहब आज चीफ मिनिस्टर हों तो वे उसी रास्ते पर यानी सोशलिस्ट रास्ते पर चलेंगे। हमारी गवर्नमेंट के सामने दिक्कतें हैं क्योंकि बहुत सी चीजें जो हम करना चाहते हैं वह सेंटर के अख्तियार में हैं। नेशनलाइजेशन आफ इंडस्ट्रीज जो है वह अगर हम करना भी चाहें तो हम कर नहीं सकते। लेकिन जो चीज हम अख्तियार कर रहे हैं और जिससे कि जो कुछ हम मीन्स आफ प्रोडक्शन और अनएम्प्लायमेंट को दूर कर सकते हैं, वह हम कर रहे हैं और दिखला रहे हैं। मसलन आप यह देखिये, जमींदारी एबालिशन हुआ। एक राइट स्टेप था सोशलाइजेशन की तरफ और जमींदारी जो है वह खत्म हुयी। खत्म होने के बाद काश्तकारों को एक सिक्योरिटी मिली मुल्क में एक बहुत बड़ी चीज पैदा हुयी। अब सिवाय इसके कि उसमें एक और भी रिकमन्डेशन थी जिसकी तरफ सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट करेगी। उस जमींदारी एबालिशन कमेटी में यह भी एक रिकमन्डेशन थी कि अनइकोनोमिक होल्डिंग जितनी हैं उनके ऊपर लगान माफ कर दिया जाय। अब हमारी गवर्नमेंट को, जबकि इस तरफ स्टेप लेने जा रही है, उसको चाहिए कि वह लगान माफ कर दे।

मैं गेंदासिंह जी से हमनवा हूं। वह यह कि फिक्सेशन आफ होल्डिंग्स हो जाना चाहिये। अगर्चे उसमें बहुत कुछ फायदा नहीं है जितना कि आप समझते हैं। लेकिन मुल्क के बहुत कुछ काश्तकारों का फायदा हो सकता है। मसलन यह है कि हमारी गवर्नमेंट के पास बहुत से फार्म्स हैं। आप देखें कि तराई भावर में १६ हजार एकड़ लैन्ड है। अगर उसको काश्तकारों को डिस्ट्रीब्यूट करें तो बहुत कुछ अनएम्प्लायमेंट की तरफ फायदा हो सकता है।

हुजूरवाला, हमारे सोशलिस्ट ढांचे के लिये नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट, कोआपरेटिव डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें हम सोशलिस्ट तरीके अख्तियार करना चाहते हैं और कर रहे हैं। कोआपरटिव डिपार्टमेंट के जरिये से हम यह चाहते हैं कि सूबे भर में सोसाइटीज बन जायं और दूसरी पंचवर्षीय योजना में सूबे का कोई भाग ऐसा न रहे जहां कोआपरेटिव सोसाइटीज बन न जायं और उनके जरिये से मुख्तलिफ तरीके की क्रेडिट सोसाइटीज और मार्केटिंग सोसाइटीज और फार्मिंग सोसाइटीज, गर्ज की मुख्तलिफ तरीके से हम तरक्की करने जा रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि जो मौजूदा कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट है वह इस अन्दाज का है कि वह जो हमारे उसूल हैं उन्हें चला सकें? मिसाल के लिये प्रोविंशियल कोआपरेटिव बैंक है वह लोगों से फिक्स्ड डिपाजिट ३ परसेंट पर लेता है और डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक्स को ५ परसेंट से एडवांस करता है। आप कर्जे के जरिये से रुपया लेते हैं लेकिन यह उस रकम को हाई रेट आफ इंटरेस्ट लेते हैं तो नतीजा यह है कि जो और सोसाइटीज हैं उनको काफी हाई रेट आफ इंटरेस्ट पर मिलती है और गरीब काश्तकारों को मिल नहीं सकता। मसलन् उनकी बहुत सी ब्रान्चेज हैं। सीतापुर में हैं, बाराबंकी में हैं। मिसाल की सूरत से कहता हूं कि अब सीतापुर के जिले में २४ लाख रुपया बाकी है। वह ३४० सोसाइटीज वहां

[श्री ऐजाज रसूल]

रजिस्टर्ड हो चुकी है और उस रजिस्ट्रेशन के बाद भी उनको रुपया और कर्जा नहीं दिया जाता। तो इस कदर टेक्निकल्टीज और डिफीकल्टीज रास्ते में कोआपरेटिव डिपार्टमेंट डालता है और कोआपरेटिव बैंक डालता है कि जिसका नतीजा यह है कि यह कोआपरेटिव मूवमेंट जो है, जिसके जरिये से आइन्दा जनरल पब्लिक को फायदा हो सकताहै, आज कोई तरक्की नहीं कर पा रहा है। आप और जगहों को देखिये। मैं मद्रास गया था, मुख्तलिफ जगहों पर मैं यह देख आया हूं कि हर जगह कोआपरेटिव मूवमेंट नान-आफिशियल्स के हाथ में है। लेकिन यहां यह आफिशियल्स के हाथ में है। बिलकुल आफिशियल मूवमेंट है और आफिशियल्स के जरिये से चलाया जा रहा है। सबके आफिशियल प्रेसीडेंट हैं और वह अपने-अपने नुक्ते नजर से उसको चलाना चाहते हैं। कोआपरेटिव मूवमेंट उसी वक्त प्रास्पर कर सकता है जबकि नान-आफिशियल्स से उसका कान्टैक्ट हो और जब तक उनसे कान्टैक्ट नहीं होगा तब तक चाहे जितना आप रुपया खर्च कीजिये। इन्तजाम कीजिये वह तरक्की नहीं कर सकता है।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ढाई करोड़ रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कोआपरेटिव बैंक को दिया और यह कहा कि जून, सन् ५५ तक यह रुपया खर्च हो जाय लेकिन इस कदर डिफीकल्टीज और रुकावटें रास्ते में डाली गयीं कि कुल २४ लाख रुपया खर्च हो पाया। तो इसका यह ढांचा आपको बदलने की जरूरत है। अगर आप कोआपरेटिव मूवमेंट का ढांचा नहीं बदलेंगे तो आप जो समाज में चाहते हैं कि समाजवादी ढांचा आ जाय तो वह ढांचा नहीं आ सकता है। वही ढांचा रहेगा जो कि पहले था। जो तरीका पहले से चला आया है वही उनका नुक्तेनजर आज भी है। जब तक आप उनका नुक्तेनजर नहीं बदलेंगे तब तक यह मूवमेंट तरक्की नहीं कर सकेगा। सर्किल आफिसर होता है उसको ले लीजिये, देहात का उसका नुक्तेनजर ही नहीं है, वह अर्बन एरिया में रहना चाहता है। देहात की सोसाइटीज में जाता ही नहीं है। उसके लिये हालांकि २० दिन फिक्स्ड हैं कि इतने दिन वह दौरा करेगा। इसी तरह ए० आर० और डी० सी० ओ० के लिये भी है। लेकिन वह दौरा करते ही नहीं हैं। तो फिर कोआपरेटिव प्रास्पर कैसे करेगी। सुपरवाइजर्स के ऊपर छोड़ दिया गया है। मैं एक बैंक का चेयरमैन हूं। हमारे यहां सोसाइटीज सन् ५४ में बनीं। लेकिन आज तक उनका शेयर मनी नहीं आया, तो जब तक इसके ढांचे को बदला नहीं जायगा तब तक इस कोआपरेटिव मूवमेंट की तरक्की हो नहीं सकती।

हुजूरवाला, उद्योगधंधों की तरफ भी मैं गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज का दफ्तर कानपुर में था। उसका नाम बदलकर डाइरेक्टर आफ काटेज इंडस्ट्रीज कर दिया गया। हुजूरवाला, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह डिपार्टमेंट तकसीम कर दिया जाय एक डाइरेक्टर आफ हेवी इंडस्ट्रीज और दूसरा डाइरेक्टर आफ काटेज इंडस्ट्रीज कर दिया जाय और काटेज इंडस्ट्रीज के डाइरेक्टर का दफ्तर कानपुर से लखनऊ में कर दिया जाय। क्योंकि कानपुर की आबोहवा काटेज इंडस्ट्रीज के लिये माफिक नहीं है और कानपुर में काटेज इंडस्ट्रीज की तरक्की का काम नहीं हो सकता, क्योंकि जहां कोई स्कीम उसके लिये रखी गयी, पूंजीवाद वाले जो हैं वह उसमें रुकावटें डालते हैं। गवर्नमेंट की हजारों लाखों स्कीमें हैं जो उद्योगधंधों की तरक्की के लिये बनायी गयी हैं और उनसे उनकी तरक्की हो सकती है, लेकिन तरक्की नहीं हो सकती है। मुझे इस बारे में डिपार्टमेंट से भी शिकायत है। गवर्नमेंट आफ इंडिया रुपया देती है लेकिन हमारे यहां का फाइनेंस डिपार्टमेंट जनवरी में रुपया सैंक्शन करता है और चाहता है कि दो महीने के अन्दर ५५ लाख रुपया खर्च कर दिया जाय। नतीजा यह होता है कि कुछ ही रुपया खर्च हो पाता है और बाकी लैप्स हो जाता है। इसलिये मुझे यह कहना है कि जब बजट पास हो तो जल्द ही स्कीमें सैंक्शन हो जायं और चालू हो जायं बजाय इसके कि तमाम स्कीमें बाद में बनती रहें।

अब हुजूरवाला, मुझे काटेज इंडस्ट्रीज की बाबत कहना है। बहुत सी स्कीमें गवर्नमेंट ने बनायीं लेकिन मेरा खासतौर से हैन्डलूम से वास्ता है। इस बजट में दो किस्म के हैन्डलूम हैं, कोआपरेटिव हैन्डलूम और वीवर्स कोआपरेटिव। अब ये दोनों अलग-अलग चीजें क्या हैं यह मेरी समझ में नहीं आता। वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये हैन्डलूम को कर्जा दिया जा रहा है, उसका एक प्राविंशियल आर्गेनाइजेशन है, तमाम सेल्स डिपोज हैं, डाई हाउसेज हैं, यह डिपार्टमेंट पैटर्न मेकिंग डिपार्टमेंट है, डिजाइन्स बनाता है लेकिन आज तक उन डिजाइन्स का किसी कोआपरेटिव सोसायटी में डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ। तो जो २ लाख ६४ हजार रुपया इस पर खर्च किया जा रहा है बजाय इसके उनको वीवर्स कोआपरेटिव के जो आफिसर्स हैं उनमें तब्दील कर दें क्योंकि हमारे आर्गेनाइजेशन में स्टाफ की बहुत कमी है जिसकी वजह से काम बहुत कम हो रहा है।

दूसरी बात गवर्नमेंट से मुझे यह कहनी है कि हैन्डलूम बोर्ड और दूसरे बोर्डों ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि यार्न से सेल्स टैक्स हटा दिया जाय। राव साहब जो फाइनेन्स सेक्रेटरी थे वे प्रेसीडेंट हुए। आज तक उस कमेटी ने कोई तवज्जह ही नहीं की। नतीजा यह हुआ कि दूसरे सूबों में, मैं मद्रास वगैरह गया, वहां यार्न पर सेल्स टैक्स नहीं है लेकिन यहां है। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि यार्न पर से सेल्स टैक्स जल्द से जल्द हटा दिया जाय।

हुजूरवाला, जहां तक पंचायतों का ताल्लुक है मुझे यह कहना है कि उन्होंने बहुत से टैक्सेज लगा दिये हैं जिससे पब्लिक को परेशानी है। मिसाल के लिये घरवारा टैक्स लीजिये। अब देहात में पंचायतें मकानों पर टैक्स लगायें यह बहुत गलत चीज है। ऐसे टैक्सेज को गवर्नमेंट को खत्म करना चाहिये।

जहां तक बजट में कमी का ताल्लुक है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यह ख्वाहिश की कि सदन खुद टैक्स लगाये। मैं गवर्नमेंट से यह जानने की ख्वाहिश करूंगा कि जो एकोनामी कमेटी उसने बनायी थी उसकी रिपोर्ट क्या हुयी। दूसरे गवर्नमेंट खुद हमें बताये कि वह किन चीजों पर टैक्स लगाना चाहती है बजाय इसके कि हम लोगों से पूछा जाय। यह जरूर है कि बगैर टैक्स के हमारा काम नहीं चल सकता लेकिन उसके साथ-साथ आपको सदन को कन्विन्स करना चाहिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिये माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन के सामने पेश किया है उस पर सोशलिज्म की बात करने का मौका आज हमारे सभी माननीय सदस्यों को मिला है। मुझे बड़ी खुशी है और इस बात की है कि जिस सोशलिज्म की बात हम किया करते थे, जिस सोशलिस्टिक स्टेट की बात हम कहा करते थे, आज वह दिन आया जबकि सभी माननीय सदस्य सोशलिस्टिक स्टेट की बात कह रहे हैं। और हमें भरोसा है कि चाहे हम इधर रहें और चाहे उधर रहें लेकिन सोशलिस्टिक स्टेट की स्थापना कराने के लिये विरोधी पक्ष में रहकर ही ज्यादा सोशलिस्टिक स्टेट की स्थापना हम हिन्दुस्तान में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप इस पर मुहर लगा दीजिये सोशलिस्टिक की, चाहे ब्यूरोक्रेसी कहिये, लेकिन बात यह है कि जब किसी बजट पर रोशनी डालते हैं तो हम यह कोशिश करते हैं कि जिस स्टेट को कायम करने के लिये हमारी सरकार कोशिश कर रही है वह स्थापित होने वाली है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, हम यह भी जानते हैं कि सोशलिस्टिक स्टेट के अन्दर जो डेमोक्रेसी सोशलिस्ट की बात कर रहे हैं उसमें डेमोक्रेटिक अपोजिशन का क्या काम होगा और हम क्या कर रहे हैं वह भी शायद पीछे कोई लेक्चर दे। इसलिये हम उसको भी बतला देना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा क्या काम है? मैं जानता हूं कि यह डेमोक्रेटिक अपोजीशन का काम नहीं है कि गवर्नमेंट के खिलाफ वाइल्ड ऐलीगेशन्स लगा दे जिनको वह साबित

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

न कर सके, लेकिन उसका काम यह है कि वह जनता को बतला दे कि उसके पास गट्स हैं प्रोग्राम हैं, जिम्मेदारी है और अगर इस प्रदेश के शासन की जिम्मेदारी उस पर आजाय तो, उसे भी वह ठीक-ठीक ढंग से कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय, हम यह जानते हैं कि हमारा काम सरकार की कमियों को बताना है, करप्शन को बताना है। हम यदि यह कह दें कि सरकार गंदी है, बुरी है तो इससे हमारा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। यह कोई डेमोक्रेटिक अपोजीशन नहीं है। हमारी आल इंडिया पार्टी है और हम आशा करते हैं कि भलेही हम गवर्नमेंट में न जायं लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर हम खड़े हुये हैं उनको हमारी प्रादेशिक सरकार और केन्द्रीय सरकार मानें। इसी उद्देश्य को लेकर मैं बजट पर बहस करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कभी भी किसी मंत्री की नीयत पर आक्षेप करने के लिये तैयार नहीं हूं। वह देश के बड़े भारी लोग थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हमारे साथ काम किया और आजादी मिलने के बाद हमने डेमोक्रेटिक पद्धति चलाने की कोशिश की। हमारी पार्लियामेंट बनी, असेम्बली बनीं और हमें अधिकार मिले और हम आशा करते थे कि हम अपने देश में प्रजातंत्र राज्य की स्थापना करेंगे और हमने इसके लिये कोशिश की। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब तक हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन्स कायम नहीं करेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमें देश को जाग्रत करना होगा। आज हमारे मंत्री महोदयों की नीयत साफ है और डेमोक्रेटिक भी हैं और हम आशा करते थे कि हमारे यहां जो ब्यूरोक्रेसी है उसको खत्म करके डेमोक्रेट बना देंगे। लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि आज भी हमारे यहां ब्यूरोक्रेसी बनी हुई है और हमारा देश कभी इस तरह से पनप नहीं सकता है। क्या यह डेमोक्रेसी है? हमारे प्रदेश का बजट चल रहा है, हमारा शासन कैसे चलेगा, हम इस नीति को निर्धारित कर रहे हैं। हम सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। हमारे ब्यूरोक्रेट्स आकर सुनते हैं। हमारी पालिसी पर क्या दफ्तर का असिस्टेंट विचार करेगा और इंतजाम करेगा। अध्यक्ष महोदय, दुःख इस बात का है कि जो ट्रेडीशंस थे, डेमोक्रेटिक ट्रेडीशंस थे, हम उनको कायम करने के बजाय उसके उल्टे गये। आज हमारे स्टेट के अन्दर स्टेट, गवर्नमेंट, पार्टी सब को हमारी सरकार ने एक में मिला दिया है और जो पार्टी आज पावर में है वह पार्टी इस बात की कोशिश करती है कि अपने सारे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज सारी गवर्नमेंट का इंफ्ल्युयेंस, सारे आफिसर्स जो हैं उन सब का इस्तेमाल उस पार्टी को मजबूत करने में किया जाय। आज सारे पब्लिसिटी के साधनों का इस्तेमाल उस पार्टी को मजबूत करने के लिये किया जाता है। जितने हमारे बड़े-बड़े नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वह इंडिपेंडेंस का त्योहार हो अथवा और कोई, उनको पार्टी फेस्टिवल्स का रूप दिया जाता है और जो पार्टी फेस्टिवल्स होते हैं उनको राष्ट्रीय त्योहार का रूप दिया जाता है। हम लोग इस तरह गिरते जा रहे हैं और हमारे सरकारी अफसरान इसका फायदा उठाते हैं। वह चाहे प्लानिंग विभाग में हों या स्वास्थ्य विभाग में, सब जगह ऐसा होता है। मुझे दुख है इस बात का। मैं माननीय गुप्त जी की बड़ी इज्जत करता हूं, पर मुझे कहते हुये बड़ा अफसोस होता है कि अगर इस प्रदेश का कोई सत्यानाश करेगा तो वह माननीय गुप्त जी करेंगे और कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसका कारण है। उनकी इज्जत करते हुए, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं मुझे कहना पड़ता है कि उसका एक कारण यह है कि उन्होंने सारे डिपार्टमेंटों को हथिया रखा है। वह सोशलिस्ट हैं, पुराने सोशलिस्ट हैं, हमारी पार्टी के मेम्बर हैं, सोशलिस्ट विचारधारा के हैं।

आज सबेरे जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें प्रकाशित मैंने फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों के नाम पढ़े। पढ़ कर तबियत खुश हो गयी। माननीय गेंदा सिंह जी जैसा समझते थे वही हुआ। उसमें सारे कैपिटलिस्ट भरे हुए हैं। कहा गया था कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स होंगे, असेम्बली के मेम्बर होंगे। हमें वहां जाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उनका मंशा देखिये। कैपिटलिस्ट हमारे स्टेट में इंडस्ट्री कायम करवाने में मदद करेंगे। मुझे मेम्बरों

की लिस्ट पढ़ कर ताज्जुब हुआ। उसमें सारे कैपिटलिस्ट भरे हुए हैं। अगर हम उसमें चले जाते तो सारी पोल न खुल जाती। हमारे माननीय परिपूर्णानन्द जी रूस की और तमाम दूसरे देशों की बात किया करते हैं किन्तु अपने प्रदेश का विचार नहीं करते। जब इस कमेटी का निर्माण हुआ तो उसके मेम्बरों के नामों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सोशलिस्ट स्टेट का सपना पूरा होने वाला नहीं है। जिस इंडस्ट्रियल पालिसी को सोशलिस्ट स्टेट के अन्दर कायम होना चाहिये वह होने वाली नहीं है, इसका नमूना इस कमेटी के मेम्बरों की लिस्ट पढ़ कर मिल जाता है और यह बात जाहिर सी बात है। आखिर उसमें पद्मपत सिंहानियां, जैयपुरिया, रामरतन गुप्त आदि जितने भी उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वह सब हैं और दो चार नाम कारख ने वालों के, जूते बनाने वालों के भी हैं। आखिर वह भी तो एक काटेज इंडस्ट्री है। मैं अध्यक्ष महोदय अपने ब्यूरोक्रेट्स को भी दोष नहीं देना चाहता। उन से हमारे से दुश्मनी नहीं है। वह हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं। देश के और इसी देश के रहने वाले हैं। वह भी ताकत को हथियाना चाहते हैं और इसलिये वह चाहते हैं कि जब तक हो सके हम अपने मंत्रिगणों को गलत रास्ते पर ले जायं। उनको गलत चीजें बतलायें, ताकि उनकी सत्ता भी कायम रहे। यह हर ब्यूरोक्रेट चाहता है जैसे कि पार्टी वाले माननीय गुप्त जी चाहते हैं। वह पूरे ब्यूरोक्रेट होते हैं। वह अपने मंत्री के रुख को देखते हैं इसलिये कि माननीय गुप्त जी उनके विभाग के अफसर हैं। विभागीय अफसर भी सब समझते हैं। वह जानते हैं कि गुप्त जी पार्टीबाज हैं, उनकी पार्टी के इलाके में कोई अस्पताल खोल दिया जाय, कोई इंडस्ट्री खोल दी जाय, उसमें .....

श्री अध्यक्ष—जरा व्यक्तिगत हो रहा है। आप नाम बार बार ले रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय नियोजन मंत्री, माननीय नियोजन मंत्री के विभाग वाले लोग, अध्यक्ष महोदय, वह हमेशा इस बात का ख्याल करेंगे कि कहीं माननीय नियोजन मंत्री जी नाराज न हो जायं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आप देखिये कि इसका रास्ता, हल क्या है? हमारे भाई कहते हैं कि हवा में बात करते हो, बताओ कि इसका सेल्यूशन क्या है। मेरा मतलब यह नहीं कि इस ब्यूरोक्रेसी की बात को ले कर उनको निकाल दीजिये। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जब तक लेजिस्लेचर का कंट्रोल नहीं होगा तब तक इस प्रदेश में न सोशलिज्म आनेवाला है और न कोई और इज्म आने वाला है। मेरी एक राय है और वह यह है कि जो हमारी असेम्बली की स्टैंडिंग कमेटीज हैं और जो हर एक डिपार्टमेंट के लिये बनी हुयी हैं वह अब हमारी सरकार को राय देने वाली कमेटीज न रहकर चाय पीनेवाली कमेटीज बन गयी हैं माननीय गुप्ता जी ने रानीखेत में एक कमेटी बुलायी और हम लोगों को आड़ू खिला खिला कर घर भेज दिया और वहां से सब घर चले गये और कह दिया कि अब इसकी मीटिंग जुलाई में होगी। अब मार्च आगया है लेकिन अभी तक उसकी कोई बैठक नहीं हुई। अगर आप डेमोक्रेसी को पनपाना चाहते हैं और इस ब्यूरोक्रेसी के गलत प्रभाव को खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिये एक ही रास्ता है कि आप इन स्टैंडिंग कमेटीज को ज्यादा पावर दीजिये और जो राय वह दें उसको माना जाय और उनकी बातों पर को अमल किया जाय। तब यह ब्यूरोक्रेसी जिसकी बात पर सरकार चलती है उसका असर खत्म हो जायगा और वह भी समझने लगेंगे कि हमारे ऊपर लेजिस्लेचर अलर्ट हो गया है और सारी बातों की जांच करता है। अब जो पालिसी ब्यूरोक्रेसी निर्धारित करती है उस पर लेजिस्लेचर कंट्रोल नहीं करता है और यही कारण है कि लेजिस्लेचर के अन्दर हर एक डिपार्टमेंट पर क्रिटिसिज्म होता है। इसलिये मेरा प्रस्ताव यह है कि हम लोगों की जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनको ज्यादा पावरफुल बनाया जाय।

दूसरी चीज यह है कि सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी के अन्दर डिसेंट्रलाइजेशन बहुत आवश्यक है। हम आज देखते हैं कि हमारे लेजिस्लेचर की जो पावर है और हमारी पार्लियामेंट की जो पावर है उनको तो बढ़ाया गया है लेकिन हमारी पंचायतों की जो पावर हैं उनको कम कर दिया गया है। हमारी यूनिवर्सिटी की पावर को खत्म किया जा रहा है और उसकी अटानोमी को खत्म किया जा रहा है। हमारे लोकल यूनिट्स की पावर को आप ले रहे हैं। अभी कुछ दिन हुए पंचायतों का चुनाव हुआ। पंचायतों के चुनाव दिसम्बर अक्तूबर में समाप्त हो गये।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

पंचायतों के जो सभापति थे और उनके जो रजिस्टर थे वह एक पंचायत का जो सेक्रेटरी होता है उसने अपने पास रख लिये हैं और आज पांच महीने हो गये हैं सभापति हमारे गांवों के अन्दर कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्या यही डेमाक्रेसी है और यही डिसेंट्रलाइजेशन है। कम से कम मैं तो इस हद तक डिसेन्ट्रलाइजेशन लाने के लिये तैयार नहीं हूं कि जिसमें हमारी नेशनल यूनिटी हट जाय। लेकिन जैसे कि रोजमर्रा के उनके झगड़े हैं, उनका फैसला करने का अधिकार हमारी डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट को होना चाहिये। इससे फिर बचत यह होगी कि एक सेंट्रल आर्गनाइजेशन जो लखनऊ में बैठा हुआ है और जिसके लिये एक सारी फौज बनी हुयी है, वह इधर दौड़ती है उधर दौड़ती है और माननीय मंत्री जी को गलत रास्ते पर चलाती है, वह नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कितने ऐसे नोट इन चार सालों के अन्दर लिखे हैं जिनमें उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से डिसएग्री किया हो। उनकी हिम्मत नहीं है कि वह उनसे डिसएग्री कर सकें चाहे उनकी सारी गवर्नमेंट खत्म हो जाय। वह जानते हैं कि उनके पास सपोर्ट है। अपोजीशन कम है वह बक-बक के सिवाय और क्या कर सकता है। इन अपने तरफ के लोगों को टिकट की धमकी दे सकते हैं लेकिन हमारा क्या कर सकते हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि हमारा देश पनपे। हमको खुशी इस बात की है कि हमारे मुख्य मंत्री जी विद्वान् हैं, सोशलिस्ट हैं, सब बातें जानते हैं और समझते हैं।

मुझे इस बात की खुशी है कि जो गवर्नमेंट आफिशियल्स हैं, और जो बहुत सालों से टैम्पोरेरी चले आते थे, उनको उन्होंने परमानेन्ट करने का फैसला किया है और उनको परमानेन्ट करने जा रहे हैं। उनकी इस्टेबलिटी होगी और वह अपने को इस्टबिल समझेंगे। हम समझते हैं कि सरकारी अफसरों का भी यह फर्ज है कि वह इस प्रदेश का काम करें और वह अपने को इस प्रदेश का समझें और किसी पार्टी का अपने को वह आदमी न समझें। उनके अधिकार सुरक्षित हैं फिर कौन सा कारण है कि हमारे प्रदेश के तमाम सरकारी अफसर इस प्रदेश की उन्नति करने के लिये प्रयत्न न करें परन्तु उनके बदलने के पहले हमारे माननीय मंत्री जी बदलने की कोशिश करें। अगर पार्टी बाजी को नहीं लाना है तो हम किसी तरह से भी कोआपरेशन करने में किसी भी तरह से उनका साथ देने को हम तैयार हैं। फिर आप पूछेंगे कि आपका सुझाव क्या है ? लोग मुझको कुछ नान सीरियस समझ लिया करते हैं। यह न समझना चाहिये कि मैं कुछ नान सीरियस बात कह रहा हूं। वह सुझाव यहां से लागू नहीं हो सकता, वह तो प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के लिये है। वह यह है कि अगर आप उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा सुझाव यह है कि माननीय नियोजन मंत्री, गुप्ता जी को किसी प्रदेश का गवर्नर बना दीजिये और ऐसे प्रदेश का गवर्नर बना दीजिये जिसमें भुखमरी हो, लेकिन वे वहां भी चन्दा वसूल करके अपनी पार्टी को खड़ा कर लेंगे। अन्त में मैं सरकार से चाहूंगा कि वह जो सोशलिस्ट स्टेट कायम करना चाहती है उसको कायम करने का पूरा-पूरा प्रयत्न करे।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस ढंग से इस सदन में बजट पेश किया उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री जी, सुनते हैं कि दूसरे सदन में बजट पूरा पढ़ भी न सके, न अच्छे ढंग से पेश ही कर सके। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में बहुत कुछ विकास के कार्यों का जिक्र किया गया है। मैंने इसको आदि से अंत तक पढ़ा लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि क्या वास्तव में यही समाजवादी बजट है अगर वह वास्तव में ऐसा है तो "टेढ़ी खीर" वाली कहावत इस पर चरितार्थ होती है। थोड़े से शब्दों में अगर मैं कहूं तो यह बजट साधन सम्पन्न व्यक्तियों का बजट है। जिनके पास साधन हैं उन्हीं को और साधन जुटाने का प्रयत्न इस बजट में किया गया है। जिनके पास कुछ नहीं है उनको कुछ दिया नहीं गया है, बल्कि उनसे और लेने का प्रयत्न किया गया है। क्या इसी प्रकार से हमारे इस देश और हमारे सूबे का कल्याण होगा, इसमें मुझे संदेह है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी और सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस बजट को बनाते समय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को बनाते समय, अपने प्रदेश में और गांवों में इस बात की गणना की है कि

आपके गांवों में अब भी दासता की प्रथा चली आ रही है । अब भी ऐसे बच्चे आपके यहां पैदा होते हैं कि जिनके पैदा होने के दिन से दासता की वृत्ति उनके ऊपर लगा दी जाती है । हर गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो जन्म जन्मान्तर से दासता ही करते चले आ रहे हैं । आपको यह भी पता होगा कि गांव में ऐसे कितने ही खेतिहर मजदूर हैं जो पहले के कहे जाने वाले जमींदारों या बड़े काश्तकारों के यहां काम करते हैं और जीवन भर काम करते हुए मर जाते हैं लेकिन अपना कर्जा नहीं चुका पाते और वह कर्जा उनकी आने वाली संतानों को चुकाना पड़ता है । क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों का इस बजट में क्या प्रबंध किया है ? सरकार, उनके दासता के बंधनों को छुड़ा कर उनकी आगे आने वाली संतानों को सेवा करके जीवन-यापन करने का मौका दें । मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा कदम होगा, क्या इसमें उनके लिये कुछ किया गया है ? क्या वे लोग जो इस प्रकार से दासवृत्ति के लिये मजबूर किये जाते हैं यह अनुभव करते होंगे कि अंग्रेज चले गये और आज उनका देश और प्रदेश स्वतंत्र हो गया है । जब अंग्रेजों के समय से उनकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वे किस प्रकार से गौरव कर सकते हैं कि उनका सूबा स्वतंत्र हो गया है । मुझे तो अफसोस होता है जब कुछ लोग कहा करते हैं कि हरिजनों के लिये यह किया, बैकवर्ड क्लासेज के लिये वह किया । क्या किया अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नहीं समझा, और समझा तो केवल यही कि जिस प्रकार कुछ कुत्तों को टुकड़े फेंक कर उनको आपस में लड़ाया जाता है उसी प्रकार कुछ रुपये फेंक कर हरिजनों को लड़ाये जाने की व्यवस्था है । हरिजनों को जो दीनहीन हैं और करोड़ों की तादाद में हैं, कितना रुपया दिया गया है? एक रुपया भी तो एक आदमी पर नहीं पहुंचता है । किस तरह से उनका कल्याण होगा? हां, इससे एक लाभ अवश्य होता है कि जो वोटिंग डिवाइस की व्यवस्था हो सकती है और हरिजनों से वोट प्राप्त करने के लिये कुछ को मिनिस्टर कुछ को डिप्टी मिनिस्टर और कुछ को और पद दे दिये जाते हैं और ग्रान्ट कुछ उनके कहने पर कुछ लोगों को दे दी जाती है ताकि ऐसे लोग चारणों की भांति उनके गीत गा कर सरकार का प्रचार करें । इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है । मैं आज जब शुरू-शुरू में आया तो मैंने एक दो सज्जनों के भाषण सुने तो मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसा सामन्तशाही के वक्त में, नवाबों के जमाने में चारणों की दशा होती थी—वैसी ही है कि हमारा सूबा क्या कर रहा है, हमारा राज्य क्या कर रहा है और उनकी बढ़ाई करने में ही वे अपना अहोभाग्य समझते हैं । इस सम्बन्ध में मुझे उस कवि की याद आ जाती है जिसने यह कह कर असावधान राजा को सावधान किया था :—

"नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास यहिकाल,
अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल ।"

तो अभी तो हमारा पूर्ण विकास हुआ नहीं, हमने अपनी मंजिल पार की नहीं, अपने सूबे को धनधान्यपूर्ण कर लिया ऐसी बात तो है नहीं, तो अभी से ये क्या राग अलापने लगे । हां, यह बात सही है कि इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं क्योंकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की भांति हर चीज में दो पक्ष मिल ही जायेंगे । इसी तरह से बजट में कुछ अच्छी बातें हैं यह निश्चित है लेकिन सवाल यह है कि हमारा प्रदेश स्वतंत्र हुआ, प्रदेश की सरकार अपने लोगों के हाथ में आयी तो उन्होंने अपने उन लोगों के लिये जो हजारों वर्षों से नेगलेक्टेड हैं, दुखी हैं, परेशान हैं उनके लिये क्या किया है । माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इस बजट में बेकारी को दूर करने का प्रयत्न किया गया है । क्या किया है ? इस बजट में ब्यूरोक्रेसी की एक बड़ी भारी पल्टन दिखायी पड़ती है । बड़े-बड़े अफसरों की एक बहुत पल्टन आप तैयार कर रहे हैं जो सारे समाज पर शासन करेगी, और क्या बात इसमें है ? इसमें कहा गया है कि इसमें सोशलिस्टिक पैटर्न की व्यवस्था करने के लिये क्या-क्या काम किये गये हैं और गत वर्ष का जिक्र भी उन्होंने किया है कि चपरासी की तनख्वाह २ रुपये बढ़ा दी और जिनको १ सौ रुपया तक मिलता था उनके डी० ए० का आधा पे में जोड़ दिया और इस साल जो दो सौ तक पाते हैं उनका डी० ए० का आधा आप जोड़ देंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चपरासी की तनख्वाह का डयोढ़ा दूना नहीं किया जा सकता था । जो लोग सैकड़ों रुपया पाते हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाती है बढ़ाइये, ठीक है, लेकिन सिर्फ

[श्री जोरावर वर्मा]

दो रुपये उसके बढ़ाना क्या महत्व रखता है ? क्या समानता है तनख्वाहों में, कितनी बड़ी विषमता फैली हुयी है कि कोई कई हजार पाते हैं और कोई एक सौ भी नहीं पाता है। तो आखिर आप किस प्रकार से इस समाज में समता लायेंगे ? कोई तो निश्चित स्थान होगा जहां पर आप समाज को एक समता की सीढ़ी पर ला सकेंगे।

एक बात की चर्चा हमारे कुछ माननीय मित्रों ने की कि साहब गवर्नर साहब के लिये ३२ हजार रुपये की कार खरीदी गयी है उससे हमारे प्रदेश की, हमारे गवर्नर की शान व शौकत बढ़ेगी। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ, महात्मा गांधी—उस राष्ट्रपिता के मानने वाले जिसने खद्दर पहन कर मोटा कपड़ा पहन कर लोगों को इज्जत और स्तर को बढ़ाया जो कभी रेशमी कपड़ा और महीन से महीन कपड़ा पहनने वालों को प्राप्त न हो सकी, केवल इसी देश में नहीं, संसार में अकेले लंगोटी लगा कर उन्होंने सारे संसार को दिखा दिया। कि अगर देशसेवा का भाव है तो वह पूज्य हो सकता है, जो कि आज सूटेड बूटेड हो कर बड़े से बड़ा आदमी उस ख्याति को प्राप्त नहीं कर सकता। उस महात्मा के अनुयायी इस बात को आज कहें कि जितनी बढ़िया कार हो, जितनी अधिक कीमत की कार हो उस से उतनी ही राष्ट्र की ख्याति बढ़ेगी, मैं समझता हूं कि इस से महात्माजी की आत्मा, जहां भी वह होंगे, क्या कहती होगी। उन्होंने पाठ पढ़ाया कम खर्च करने का और यहां ज्यादा खर्च करने में शानशौकत समझी जाती है। एक साहब ने कहा कि हमारे दूसरे साहब आयेंगे वह पुरानी बैल गाड़ी की चर्चा करेंगे। अगर हमारे गवर्नर महोदय बैलगाड़ी पर भी बैठें तो क्या बुरा है, आपको याद होगा कि विलायत के बने हुए सेफटी रेजर से महात्मा जी ने कभी अपने बाल नहीं बनवाये, जो उस्तरा यहां का लुहार बनाता था उसी से उन्होंने बाल बनवाये, तो अगर राज्यपाल महोदय बैलगाड़ी पर चढ़ें और अनुभव करें कि देहात के साधारण आदमी का क्या स्तर है, उस पर चढ़कर उसे क्या कष्ट और आनन्द होता है तो इस में कोई बुराई थोड़े ही है। इस प्रकार की भी इस में कई बातें रखी गयी हैं। एक और बात—जब से यह सदन बैठा है ४ साल हो गये जमींदारी अबालिशन के गीत गाये जा रहे हैं, हमारी सरकार ने जमींदारी मिटा दी तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया, यह मेरी समझ में नहीं आया। पहले गांव में एक जमींदार था वह जमींदारी अब आप ने ५० किसानों को दिला दी। आप देखें कि जिस समय जमींदारी नहीं मिटी थी उस वक्त किसान और और मजदूर सब एक थे। जमींदार के अत्याचार और जुल्मों से लड़ने के लिये वह सब एक हो जाया करते थे लेकिन अब किसान भी जमींदार हो गये और गांव में जो साधनहीन हैं जिनके पास जमीन नहीं है, उनको अब किस तरह से परेशान किया जा रहा है, उस का अनुभव वही कर सकता है कि जो देहात में जाता हो। जमींदारी खत्म कर दी तो क्या सरकार बता सकती है कि उन से जो जमीन खाली हुई आप ने उसमें से कितने बेजमीन वालों को जमीन दिलवाई। आप कहेंगे कि किसी को नहीं, तो जमींदारी मिटने से फिर कौन सा अच्छा काम हो गया। कुछ भी हो देश स्वतंत्र हो जाने के बाद आज वे लोग अपने को समाजवादी तो कहते हैं क्योंकि जैसा कि झारखंडे राय जी ने कहा कि यही लोग जो पहले समाजवाद का नाम सुन कर बुरा मानते थे आज कहते हैं कि हम समाजवादी हैं। तो मैं भी यह समझता हूं कि जिन को राम राम नहीं आता है वह अगर मरा मरा कहकर राम कहना सीख जायं और ठीक रास्ते पर वह आ जायं तो अच्छा है। मुझे आशा है कि सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि हमारा प्रदेश दिन प्रति दिन सम्पन्न हो।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है यह बजट एक बहुत महत्व का है, इसलिये कि पहली पंच-वर्षीय योजना के ५ वर्ष समाप्त हो चुके हैं और दूसरी पंच वर्षीय योजना के आरम्भ काल का यह बजट है। मुझे इस बजट पर कहने के पहले जरा सी एक बात कहना जरूरी है कि अगर यह बजट फाइनेन्स कमेटी में होकर पूरे तौर से आया होता, तो इस हाउस की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो सब-कमेटी, जिसके सुपुर्द उसने डिटेल्स में जाने की बात कही है, वह पूरी हो गई होती तो ज्यादा अच्छा था। दूसरी बात यह है कि इस बजट में कई आइटम्स में यह मान लिया गया है कि इस वर्ष के आइटम्स पास हो जायंगे और बाक़ी ४ वर्ष के लिये वे आइटम्स रख दिये जायंगे। ज्यादा अच्छा होता कि जो आइटम्स इस साल के हैं वही रहते और अगले वर्ष इस सदन के सामने यह सरकार बताती कि इस तरह से खर्च करने का यह नतीजा हुआ। ज्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ और अगले वर्ष ही यह आइटम्स सदन के सामने आये होते तो उस वक्त सदन बता सकता कि कहां तक मुनासिब खर्च हो रहा है और जिस तरह से प्लान्ड आइटम्स पर जो खर्च हो रहा है, वह मुनासब है या नहीं क्योंकि मैं समझता हूं कि वह प्लान पूरी तरह से बन चुका है और उस प्लान में ५ वर्ष की योजना है और करीब-करीब सब आइटम्स, शायद ही एक आध फी सदी आइटम्स ऐसे हों जो इस वर्ष शुरू न हों — इस पंचवर्षीय योजना में सब आइटम्स हैं यानी सारी पंच वर्षीय योजना की शुरुआत इस बजट में हो रही है। और अगर यह कह दिया जाय कि बाक़ी चाल में भी वे आइटम्स आ जायंगे तो इसके माने यह हैं कि हम बहुत कुछ पंचवर्षीय योजना के बजट को मंजूर कर लेते हैं। इसलिये हर साल आता जाता तो अच्छा था। बहरहाल, यह तो मैंने एक बात कही जिसकी तरफ मैं समझता हूं कि मेरा ध्यान दिलाना जरूरी था।

मैं, डिटेल में १५ मिनट के समय में नहीं जा सकता लेकिन जिस आधार पर दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी है, उस आधार पर इस बजट को देखने और समझने की कोशिश करूंगा। दूसरी पंच वर्षीय योजना के ३ खास खास अंग हैं, एक यह है कि आमदनी बढ़ाई जाय, दूसरे यह कि बेकारी दूर की जाय और तीसरे यह कि जो आमदनी बढ़े उसका बराबर बटवारा हो ताकि सोशलिस्ट पेटर्न आफ सोसाइटी कायम हो सके। बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री जी ने सोशलिस्ट पेटर्न आफ़ सोसाइटी का शब्द इस्तेमाल किया है। हमने एक वर्ष पहले सोशलिस्टिक पेटर्न आफ़ सोसाइटी को इस्तेमाल किया था। एक साल में अवादी से लेकर अमृत सर तक तरक्की की ओर अब कांग्रेस सोशलिस्ट पेटर्न आफ सोसाइटी चाहती है। उसने सोशलिस्टिक पेटर्न आफ़ सोसाइटी छोड़ दिया है, इसलिये सोशलिस्टिक शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। जहां तक आमदनी का ताल्लुक़ है, हिन्दुस्तान भर की आमदनी १८ प्रतिशत बढ़ी है; लेकिन बजट स्पीच को पढ़ने के बाद मैं यह नहीं समझ पाया कि यू० पी० की आय कितनी बढ़ी। एक जगह फिगर्स दिये हैं कि २१ प्रतिशत आय बढ़ी है, लेकिन वह आय ४८—४९ से लेकर ५५—५६ तक की मालूम होती है। उसमें कितनी प्लान्ड पीरियड की है यह इससे अन्दाज़ नहीं होता। मैं चाहता था कि यह मुकाबला हो जाता कि देश की आमदनी तो इतनी बढ़ी और उसमें से यू० पी० की इतनी बढ़ी क्योंकि उसमें हमें मालूम होना चाहिये कि सारे देश के मुकाबले में हम आगे बढ़े या पीछे रहे। क्योंकि जो और चीजें हम देखते हैं उसमें हमें मालूम होता है कि हम ज्यादा तरक्क़ी नहीं कर पाये। हमने, जो विकास में खर्च किया है, वह दूसरे सूबों के मुक़ाबले में बहुत कम है। उसके आंकड़े मैं देख चुका हूं और अब भी सवा ९ रुपया फी कस हम ने खर्च किया है जब कि बम्बई ने साढ़े २३ रुपया फी कस और मद्रास और बंगाल ने और ज्यादा खर्च किया है। तो हमने विकास कार्य में उतना व्यय नहीं किया। सरकार ने कोई अपना कारखाना नहीं बनाया यहां पर मल्टी परपज प्रोजेक्ट्स में सरकार ने आरम्भ में ज्यादा व्यय नहीं किया। पहले ३ साल में तो बिलकुल खर्च नहीं किया जब कि २५४ करोड़ रुपया सारे देश में खर्च हुआ। हमारे उद्योग भी आगे नहीं बढ़े, जो पहले ३ साल में आंकड़े दिये गये थे उसके अनुसार वह ज्यादा नहीं बढ़े। यू० पी० सरकार की एक किताब "यू० पी० इन फिगर्स" को देखने से पता चलता है कि उस समय लेबर की संख्या क्या थी? दूसरे इस समय जो हमें दिया गया है, उस में लेबर की संख्या बढ़ी है या घटी है, यह नहीं दिया गया है, मालूम होता है कि वह बढ़ी नहीं है, घटी ही है। तो लेबर की संख्या घटी है, विकास में हमने खर्च कम किया है, सेन्टर ने कोई कारखाना खोला नहीं, मल्टी-परपज प्रोजेक्ट

[श्री मोहनलाल गौतम]

में कुछ खर्च नहीं किया जिससे आय बढ़ती। तो यह किस तरह से इतनी हमारी आमदनी बढ़ी, और कैसे बढ़ी यह सवाल है ? हमने कृषि में बहुत तरक्की की, जितना हमने अपना लक्ष्य बनाया था उससे कहीं ज्यादा हमने पूरा किया। लेकिन कृषि की जो आज हालत है और जिस तरह से क़ीमतें घट रही हैं उस की वजह से हमको बैचेनी हो रही है। हम ही को नहीं, प्लानिंग कमीशन को बेचैनी हो रही है। उस की वजह से क्या असर हमारी आमदनी पर पड़ा इसका कोई अन्दाज हमको न बजट से और बजट स्पीच से मिलता है। अगर मालूम हो जाय कि किस तरह से हमारी आमदनी पर असर पड़ता है, और यू० पी० सारे देश के मुकबले में कहां है, तो आसान होगा असेस करना कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमको कितनी कामयाबी हुई और कितनी नहीं हुई।

जहां तक बेकारी का ताल्लुक़ है उसमें प्लानिंग कमीशन भी कहता है कि बेकारी बढ़ रही है।

"There are, however, disquieting features. Agricultural prices are declining. Unemployment, specially in rural areas is increasing."

यह सेकेन्ड फाइव इयर प्लान का फ्रेम वर्क कहता है कि अनएम्प्लायमेंट बढ़ रहा है। हमको अपने सूबे में यह नहीं मालूम हुआ कि बेकारी कितनी कम हुई या ज्यादा हुई, हिन्दुस्तान में बढ़ी है। हमारी हालत हिन्दुस्तान से ज्यादा बेहतर नहीं है। तो हमको यह नहीं मालूम कि हमारी बेकारी बढ़ी है या घटी है। पर अगली पंचवर्षीय योजना बनी है, उसमें यह अन्दाज़ किया है कि हर साल १५ लाख इंसान बढ़ेंगे, उसमें दस फीसदी इंसानों को अगर काम मिल जाय, यानी १८ लाख आदमियों को काम मिल जाय, तब जितनी आबादी बढ़ेगी, उस के हिसाब से उनको काम मिल जायगा तो अनइम्प्लायमेंट नहीं बढ़ेगा। पांच साल में ३० लाख को काम मिल जाय तो उतनी बेकारी रहेगी जितनी आज है। उन्होंने एक करोड़ इन्सानों को रोज़गार देने का प्लान किया। हम देखें कि हमने क्या किया ? हमारे बजट की स्पीच में माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि साढ़े तीन लाख आदमियों को पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिलेगा। बाक़ी रोजगार मिलने की पोटेंशियलिटी बढ़ जायगी। वह कितनी होगी, उसका अन्दाज हमको नहीं है। यानी हमारे सामने कोई तस्वीर नहीं है कि हमारी कितनी बेकारी पहली पंचवर्षीय योजना के शुरू होने पर थी और आज कितनी है, उसका पता नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना के खात्मे पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में हिन्दुस्तान भर में बेकारी को दूर करने के लिए कोई योजना नहीं बनायी है। पहले से जितनी बेकारी है उतनी रहेगी और सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को काम मिलेगा जो आबादी के बढ़ने से बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में यह भी नहीं मालूम कि हमारी बेकारी कितनी बढ़ेगी या घटेगी। इसलिये बेकारी के बारे में भी इस बजट से कोई अन्दाज़ नहीं होता। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कोई अन्दाज नहीं होता।

अब सवाल यह है कि हम इनइक्वैलिटी कैसे दूर करेंगे, सोशल जस्टिस कैसे करेंगे, सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी कैसे लायेंगे ? अगर सब बातें मिला कर कोशिश करें तो इसका सवाल है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जब वह मिनिस्टर बने थे, उस वक्त यह कहा था कि सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी में उनका ध्यान जरूर गया कि जो नौकरियों में फर्क है, वह कुछ कम होना चाहिये। टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन कहता है कि ३० और एक होना चाहिये। कांग्रेस कमेटी कहती है कि २० और १ होना चाहिये। और अभी अशोक मेहता के नाम से पायनियर में निकला था स्वीडन और नार्वे में ३ और १ है। इंग्लैंड में १० और १ है। हिन्दुस्तान में १०० और १ तो हैं सरकारी नौकरियों में और हजार और एक है प्राइवेट इन्टरप्राइज़ में। गलत हो या सही हो मैं नहीं जानता। मैं तो अखबार की बात कहता हूं लेकिन मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं चाहे ये आंकड़े सही

हों या नहीं लेकिन एक बात साफ है कि आमदनी में पिछले साल जो फर्क था, उससे फर्क और बढ़ा है, घटा नहीं। इसलिये कि तीन हजार रुपये पाने वाले आदमियों की संख्या बढ़ गई। जो यहां सेक्रेटरीज हैं उनको २५० स्पेशल एलाउन्स मिलता था अब ३०० हो गया और २० रुपया पाने वाले आदमी जिनका २ रुपया बढ़ने वाला था बहुतों को अभी तक नहीं मिला है। इसलिये २० रुपया वाला वहीं रहा और २५० रु० जिसको एलाउन्स मिलता था उसका ३०० रुपया हो गया। ३,००० रु० वालों की संख्या बढ़ गई। इसलिये गैप बढ़ा है घटा नहीं, ऐसा मेरा कहना है। फिर सोशलिस्ट पैटर्न आफ़ सोसाइटी में क्या हुआ? सब से बड़ी बात यह है कि जो हाफ़िज़ साहब ने फ़र्माया है स्टेप टु वर्ड्स सोशलाइजेशन ऐण्ड अदर फ़ीचर्स में.....

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---हाफ़िज़ साहब ने नहीं बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर ने।

श्री मोहनलाल गौतम---इसमें हाफ़िज़ साहब का नाम बड़े लफ्ज़ों में लिखा है और फ़ाइनेन्स मिनिस्टर छोटे में। तो जो उन्होंने फ़र्माया है उसमें ज़मींदारी अबोलीशन का ज़िक्र किया है। उसके लिये सरकार और यह प्रदेश बधाई के पात्र हैं। वाकई यह एक बहुत बड़ा स्टेप हुआ है और इस बात में हम दूसरे सूबों से आगे हैं। उसमें जो कमी है, वह सब पूरी हों, यह हमारी ख्वाहिश है।

अब सवाल यह है और क्या-क्या हुआ? दो कारखानों का ज़िक्र है, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का और प्रिसीज़न इन्स्ट्रूमेंट फ़ैक्ट्री, लखनऊ का। वक्त कम है इसलिये डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। लेकिन चुर्क फ़ैक्ट्री का इंतज़ाम जैसा है सह कुछ संतोषजनक नहीं है और ज्यादा अच्छा इंतज़ाम होना चाहिये, इसकी कई वजह हैं। एक तो यह हैं कि जो अफ़सर इसका इन्चार्ज हो उसका बार-बार आप ट्रांसफर न करें, यह मेरी सरकार से प्रार्थना है। हर आई० सी० एस० और आई० ए० एस० को चुर्क फैक्ट्री में ट्रेनिंग न दें क्योंकि एक आदमी जो शुरू में गलती करे उसके हटने पर जो दूसरा आदमी आता है वह भी फिर वही ग़लती करता है। और मेरा ख्याल यह है कि श्री बी० जी० राय को बदलना बड़ी भारी ग़लती हुई। जो प्रोडक्शन हुआ है वह कम हुआ है पिछले साल में और उसको टीथिंग ट्रबल कहते हैं, ऐसा डिपार्टमेंट की राय है। अब इस ट्रबल को हल करने की कोशिश होनी चाहिये थी क्योंकि यह हमारा पहला वेन्चर है। हमने सोशलिस्ट पैटर्न आफ़ सोसाइटी की तरफ़ जाने में एक बड़ा क़दम उठाया है। जो गवर्नमेंट की फ़ैक्ट्री बनी थी उसकी कामयाबी बहुत ज़रूरी थी और अगर उसके लिये खास तौर से एक मिनिस्टर को चुर्क में जा कर रहना पड़े और उसको वह कामयाब बना दे और यह बता दे कि दूसरी प्राइवेट फ़ैक्ट्रीज़ से हम किसी तरह पीछे नहीं हैं बल्कि ऊंचे हैं तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा कदम होगा।

प्रीसीज़न फ़ैक्ट्री में सिवाय मीटर बनाने के कुछ नहीं है। कोआपरेटिव सोसाइटी में प्राफ़िट मोटिव काम कर रहा है, सर्विस मोटिव नहीं है। हम सीमेंट को, कोल को, साल्ट को, इन सबको कोआपरेटिव की मार्फ़त बेचें तो ज्यादा अच्छा होगा। गेहूं ९ रुपया किसान से मिला और अब १६, १७ बिक रहा है। यह सब रुपया कहां जा रहा है? मेरी समझ से यह ठीक नहीं है। 'लेबर पार्टीसिपेशन इन दी मैनेजमेंट' का कोई ज़िक्र नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं अगर सोशलिस्ट पैटर्न आफ़ सोसायटी लाना है तो यह जो डैमोक्रेटिक सेट अप है यह बड़ा खतरनाक है। मार्क्स इसीलिये आर्म्ड रीसरक्शन के फ़ेवर में थे क्योंकि इलेक्शन जो होते हैं उसके लिये रुपया चाहिये, रुपया लेने जाते हैं पूंजीपतियों से तो हम उनके दबाव में आ जाते हैं, और इसलिये हम जब इलेक्शन में हो कर आयेंगे तब हमको दिक्क़त पड़ेगी। इसलिये अगर 'सोशलिस्ट पैटर्न आफ़ सोसाइटी' लाना है तो मिनिस्टरों का कैपिटेलिस्टों से रुपया लेना बन्द करना चाहियें, तब हम 'सोशलिस्ट पैटर्न आफ़ सोसायटी' में क़दम बढ़ायेंगे। अगर नहीं करते तो सोशलिस्ट पैटर्न नहीं आ सकता। डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी से मैं यह अपील करूंगा कि वह एक पुराने नेता हैं, केपिलिस्ट लोगों से रुपया लेना हम लोग बन्द कर दें, इसका वह उपाय करें।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम वित्त मन्त्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके लिये उनको धन्यवाद दे दूं और , उसके साथ ही, आपकी आज्ञा से, सदन का यह सत्र जब से प्रारम्भ हुआ, तब से जो भाषण हो रहे हैं यद्यपि यह थोड़ा सा अप्रासंगिक होगा, उस पर भी आप की आज्ञा से एक संकेत कर दूं तो बहुत अच्छा होगा। इस परिधि में जो हम लोग बैठे हैं उसकी कुछ मान्यतायें हैं और उन मान्यताओं के आधार पर यहां भाषण होना चाहिये। राज्यपाल का सम्बोधन हुआ, उसमें भी उसी तरह के भाषण हुए, अनुपूरक अनुदान पेश हुए, उसमें भी वही तर्ज तरीका रहा और यह बजट पेश हुआ उसमें भी उसी तरह की कहानियां गायी गयीं। इसलिये, आप की आज्ञा से, मैं इस सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिन लोगों को कानून की किताबों को देखने का अवसर मिला है, वे जानते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड एक कानून की किताब है, उसमें जजमेंट का एक चेप्टर आता है। उसमें बताया गया है कि जजमेंट क्या कहलाता है। कौन-कौन सी चीज न रहे तो वह जजमेंट नहीं कहलाता है। उसी प्रकार जब राज्यपाल का सम्बोधन होता है तो उसमें भी चन्द ऐसी मान्यतायें हैं जिनके आधार पर राज्यपाल महोदय सम्बोधन करते हैं और उन्हीं मान्यताओं के आधार पर ही उसका क्रिटिसिज्म भी होना चाहिये। उसी प्रकार अनुपूरक अनुदान की भी कुछ मान्यतायें हैं, कुछ रूल्स रेग्यूलेशंस हैं। उसी प्रकार जब कोई कंडोलेंस रिजोल्यूशन रखा जाय तो उस की भी कुछ प्रथा होती है उस के भी कुछ तरीके होते हैं, जिनके मुताबिक उस पर भी भाषण होना चाहिये। लेकिन एक ही तरीके से जब कभी मौका मिल जाय, तब वही पुरानी गाथा गायी जाय, इससे सदन की शोभा नहीं बढ़ती है। इस सदन की परिधि में बोलने के लिये हम लोगों को किस समय क्या कहना चाहिये, इसमें दिक्कत होती हो तो, इसी की सीमा से , सदन की सटी हुई एक लायब्रेरी है, वहां भी हम लोगों को कुछ समय देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य बजट पर जरा भाषण दें।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि यह जरा अप्रासंगिक है, पर जिस प्रकार के ये भाषण हो रहे हैं उसी के सम्बन्ध में ....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह यहां का तरीका नहीं है कि जो भाषण हुये हैं उनके सम्बन्ध में आमतौर पर कहा जाय कि सदस्यों के भाषण "ठीक तरह के भाषण नहीं हुए हैं" न ऐसी सदन की प्रथा ही रही है। तो इसका भी जरा आप ख्याल रखें। आप सब के भाषण के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—मैं माफ़ी चाहता हूं। इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि इन ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से तो जितने दोस्त हैं वह दोषपूर्ण हैं ही, तो उनका बजट जब आया है तो वह दोषपूर्ण होगा ही। पर जिन लोगों के दामन साफ हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वह अपने साफ दामन को देखें कि उनके भाषण, उनके क्रिटिसिज्म से उनके दामन गन्दे तो नहीं होते? मरने और जीने के बीच विरोधी पक्ष की स्थिति है? यदि ट्रेजरी बेंचेज ग़लती न करें तो आपका जीना या रहना बड़ा मुश्किल हो जायगा। इसलिये आपने जो क्रिटिसिज्म का ढंग अपनाया है उसके लिये तो बहुत समय चाहिये कि उसके हर पहलू पर कोई प्रकाश डाला जाय। सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी का नाम, वित्त मंत्री के भाषण में आया। इससे बहुत ही बेकली हमारी अपोजीशन बेंचेज को हुई। पता नहीं कि जब अपोजीशन के कथानानुसार सोशलिस्टिक पैटर्न के तरीके को ट्रेजरी बेंचेज अपनाती नहीं हैं, तो नुक्सान किसका होता है? उससे तो ट्रेजरी बेंचेज को नुक्सान पहुंचेगा, फिर अपोजीशन को क्या परेशानी है? यदि वह इस चीज को साफ़ तरीके से कहते कि सोशलिस्ट पैटर्न का नाम लेने से उनके दल (विरोधी), को नुक्सान होता है तो हमारी समझ में भी आता। इसी तरह से अपोजीशन के सदस्य यह कहा करते हैं कि जमींदारी अवश्य खत्म की, पर यह नारा आप कब तक लगाते रहेंगे?

मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जमींन का बटवारा करो, इस नारे को जब से आप ने शुरू किया उसको आप अभी तक लगाते रहते हैं तो क्या आपने अपनी पार्टी के सदस्यों के लिये यह नियम बना रखा है कि वही पार्टी के मेम्बर हो सकते हैं जो उचित मात्रा में जमीन रखते हों अथवा अपनी जमीन का उचित बटवारा करके आये हों? यदि ऐसा नियम नहीं है तो जिस पार्टी ने जमींदारी को वाकई में खत्म किया है, यदि वह पुकारती है तो इसमें दोष क्या रह गया है? मेरी आप से प्रार्थना है कि पहले अपने दामन को देखें, उसके बाद दूसरे की तरफ निगाह डालें। विरोधी दल की तरफ से माननीय गुप्ता जी को एक पार्टीबाज कहा गया है। मैं इस बारे में भी एक संकेत कर देना चाहता हूं। जिन लोगों के लड़के-बच्चे हैं और वह बड़ी-बड़ी विभूतियां हमारे आदर की पात्र भी हैं, वह भी मरते वक्त पार्टी का नाम लेते हुये मरते हैं, तो फिर गुप्ता जी जिनके कोई बाल-बच्चा नहीं अगर वह अपने जीवन भर पार्टी का नाम लेते हैं तो इसमें कौन सी अनुचित बात है? इसमें क्या दोष है। जब मरते-मरते लोग पार्टी का नाम लेते हैं, फिर गुप्ता जी जीते जी नाम क्यों न लें।

समय बहुत कम है, इसलिये मैं बजट के चन्द पहलुओं पर भी एक सुझाव पेश करना चाहता हूं। यहां हरिजन सदस्य और बैकवर्ड सदस्य और उनके कुछ साथी यह शिकायत करते हैं कि इस सरकार ने हरिजनों के लिये कुछ नहीं किया। मैं आपकी आज्ञा से इस सदन में एक नम्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि वाकयात को आप न भूलें। इस सदन को देखें, इसमें करीब ८६ हरिजन और बैकवर्ड सदस्य हैं। उनके साथ इस कांग्रेस सरकार ने क्या नहीं किया। इस सरकार की हिस्ट्री देखी जाय तो जो कुछ काम किये उनमें सब से अधिक काम हरिजन को उठाने के लिये ही किया गया है और इस बजट को आप देखें तो काफी मात्रा में उनके ही उद्धार के लिये रुपया भी रखा गया है। इस सदन के ८६ सदस्य हम लोगों के पास समान रूप से बैठते हैं। दारुलशफा में भी उनके साथ वही समानता का व्यवहार किया जाता है। हां, एक असमानता उनको जरूर खटक रही है कि वह देहात में यह समानता नहीं पाते हैं, जिसके लिये उनको कष्ट अवश्य है। पर उत्थान का यही तरीका होता है कि कहीं थोड़ी सी कमी रहे पर यदि रास्ता उत्थान की तरफ जाता हो तो वाकयात को नहीं भूलना चाहिये।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि हमने तीन तीन रोज से कोशिश की कि कौन तरीका अख्तियार किया जाय कि हमें इजहार खयाल का मौक़ा मिले पर नाकामयाबी हुई। या तो हुजूरवाला कुछ वक्त बढ़ा दें, आज दो घंटे दूसरे रोज के और ले लें, वरना हमारे लिये मुश्किल होगा कि कैसे अपना इजहार खयाल करें?

श्री अध्यक्ष—वक्त बढ़ाने के लिये मैं समझता हूं कि जब सवा दो बजे हम फिर बैठें उस वक्त बातचीत हो सकती है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—आप दूसरे वक्त जनाबवाला मिनिस्टरों को पुकार लेंगे।

श्री अध्यक्ष—एकदम, फौरन् नहीं पुकारेंगे।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—तो फिर सवा दो बजे आप तशरीफ यहां रखें।

श्री अध्यक्ष—अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आ जाऊं।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—अध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय बहुत ही कम है इसलिये बजट के हर पहलू पर जैसा कि सरकार का बजट भाषण हुआ है, कहना बड़ा मुश्किल सा है। मैं एक नम्र निवेदन आपकी आज्ञा से मंत्री महोदयों से करना चाहता हूं और वह यह कि विभागीय

[श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी]

बजट का जो का साल में होने वाला है उस पर जरा बड़ी निगाह से गौर करें क्योंकि यदि आप उस पर देखें तो हर विभाग में ऐसी कमियां दीख पड़ती हैं जिसका उल्लेख किया जाय तो उसके लिये काफी समय चाहिये।

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बिजनौर जिले को देखें। १९१४ की लड़ाई के बाद फ्रांस में एक अवस्था आयी थी और उस में पुरुषों का बहुत ह्रास हुआ था और वहां ऐसे ऐक्ट्स बने थे कि एक पुरुष तीन-तीन शादी करे। पर बिजनौर की परिस्थिति को देखते हुये औरतों के अस्पतालों के बारे में क्या वजह प्रतीत नहीं होती है। बिजनौर के जिले में उसकी कितनी आबादी है, उसमें केवल ५ महिला अस्पताल हैं और इसकी पुष्टि के लिये मैं और जिलों के बारे में अधिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि समय नहीं है। गोरखपुर प्रान्त का सबसे बड़ा जिला गिना जाता है। कई मानों में इसका अंग भंग पर भी वह दूसरे तीसरे नम्बर का जिला है, इसमें केवल एक महिला अस्पताल है। (एक आवाज वहां १४ म्युनिसिपैलिटीज हैं)। मैं जैन साहब की बात समझ रहा हूं लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मुख का काम है कि जो खाना खाये उसको जहां खून की जितनी जरूरत हो वहां उतनी पहुंचा दे। इसीलिये जब वहां १४ म्युनिसिपैलिटीज हैं तो १४ महिला अस्पताल भी होने चाहिये।

दूसरी चीज मैं यह अर्ज करना चाहता हूं और वह भी नियोजन से ही सम्बन्ध रखती है। गोरखपुर जिले में एन० ई० एस० ब्लाक्स बहुत खोले गये और बहुत अधिक संख्या में और खोले भी जावेंगे। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि इससे शायद उस जिले को क्षति पहुंच जाय। पर वाकया यह है कि वहां सर्व प्रथम जो ब्लाक खोला गया है वह किस तरह से खोला गया है इस पर माननीय मंत्री जी गौर करने की कृपा करें।

तीसरी बात पावर से सम्बन्ध रखती है। गोरखपुर में बांसगांव तहसील में करीब-करीब ६५ ट्यूबवेल हैं, मगर उनके लिये पावर नहीं है। सूचना मंत्री जी को मैं अवश्य धन्यवाद देता हूं क्योंकि किसी न किसी प्रकार वह डीजल आईल से व कुओं को चला रहे हैं। गोरखपुर के सिसवा कस्बा में एक बिजली का कारखाना बनाया जा रहा है और जल्दी बनकर तैयार भी हो जायगा। वजह क्या है, मैं संकेत ही करना चाहता हूं।

चौथी प्रार्थना शिक्षा मंत्री जी से करना चाहता हूं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी बिल जल्द से जल्द पारित न हुआ तो जुलाई में कोई कार्यवाही न हो सकेगी और उसके लिये फिर अगली जुलाई तक इंतजार करना होगा। इसलिये वह तो शिक्षा के पंडित हैं, इस पर भी गौर करें और समय के पहले इस बिल को यहां लायें ताकि यूनिवर्सिटी को इतना समय तो मिले कि वह अपना भवन तथा अन्य कार्यक्रम दुरुस्त कर सकें।

इसके बाद पोलिटिकल पेंशन के बारे में एक मिनट का वक्त लेकर मैं भाषण समाप्त करूंगा। पोलिटिकल पेंशन जो दी गयी है वह बहुत अच्छी है, पर जिनको दी गयी है उन पर भी मुख्य मंत्री जी का कुछ ध्यान होना चाहिये। बस्ती जिले के एक सज्जन जिनकी आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी है, वह करीब तीन ही चार दिन के लिये जेल गये थे इस आंदोलन में, उनको ७५ रुपये की पेंशन दी गयी और जेल में सालों सड़ने वालों की आज क्या गति है इस पर वह स्वतः विचार करें।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अनुग्रहीत हूं आपका कि जो बजट इस सदन में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा सन् १९५६-५७ के लिये प्रस्तुत हुआ है, उस पर सामान्य विवाद में आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया। मैं माननीय मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतना बड़ा बजट, जिसको दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभिक बजट कहते हैं, इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया। मैं यह जानते हुये भी कि हमारी सरकार के मंत्री, जिनको जब भी सदन में बोलने का अवसर होता है, प्रायः यही कह दिया करते हैं कि हमें कोई सुझाव नहीं आया, बहुत बड़ी किसी मंत्री महोदय की कृपा हुयी तो वह यह कहा करते हैं कि कोई टेक्निकल सुझाव नहीं आया, अपने सुझाव देना चाहता हूं। जैसे समाजवाद की बातें यहां कही जाती हैं उनको देखते हुए भी मैं यही कह सकता हूं कि मैं भी जनता के बीच घूमता हूं और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन कागजों में और भाषणों में तो समाजवाद हो सकता है लेकिन आज जनता में समाजवाद नहीं है और यदि कोई भी समाजवाद का पैमाना लाया जाय और अपने यहां के छोटे और बड़े कर्मचारियों की तनख्वाहों को देखा जाय तो उस अन्तर को सामने रखते हुये वह फेल हो जाता है। पिछले वर्ष मुख्य मंत्री जी ने दो रुपया बढ़ोत्तरी की घोषणा चपरासियों की तनख्वाहों में की थी। लेकिन इस दो रुपया बढ़ा देने से और आज चौकीदार को ५ रुपया मिलता है, क्या होता है ? जब बड़े सरकारी कर्मचारियों को ५००० और ४००० रुपया मिलता है। यह दो सौ, ढाई सौगुने का अंतर समाजवाद का द्योतक नहीं है। अगर हम इस बात को कहें कि संविधान हमारा बदला नहीं है और यह हमारी मजबूरी है तो मैं समझता हूं कि इसको हम ज्यादा दिन तक नहीं कह सकते। हमारा संविधान चाहे केन्द्र में बना हो या सूबे में, सब हमारा बनाया हुआ है। आज यदि जनता के स्तर में, ऊंचे और नीचे लोगों के गरीब और अमीर लोगों के स्तर में, ग्रामीण और धनी आदमी के स्तर का अन्तर देखा जाय तो वह जमीन और आसमान का अन्तर है। यदि सरकार सारे साधन गरीबों की गरीबी दूर करने में लगाये होती तो मुझे यह कहने में जरा भी हिचक न होती कि हम समाजवाद की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं।

आज बेकारी के नाम पर कितने ही बेकार विभाग खोल कर कुछ बेकार लोगों को तनख्वाह देकर इस प्रदेश का आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता। मैं ऐसे कितने ही उदाहरण देने के लिये तैयार हूं। मुझे बड़ी हिचक होती है प्लानिंग डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में कुछ कहने में। अध्यक्ष महोदय, यदि कोई सुझाव समझा जाय तो मैं यह कहता हूं कि प्लानिंग विभाग को बंद कर दिया जाय। इसमें जनता का भारी रुपया अपव्यय किया जा रहा है और यदि प्लानिंग की जाय तो वह हर विभाग अलग अलग करे। सिंचाई विभाग अपनी प्लानिंग स्वयं करे, निर्माण विभाग की प्लानिंग निर्माण विभाग द्वारा हो, शिक्षा की प्लानिंग शिक्षा विभाग द्वारा हो और जो हमारा स्वायत्त शासन विभाग का कार्य है वह उनके द्वारा हो। इस प्लानिंग विभाग पर पानी की तरह से रुपया बहाया जा रहा है। अगर यह काम विभाग के जिम्मे किया जाय तो तब जनता का ज्यादा काम होगा और साथ ही खर्चा भी कम होगा। आज इस प्लानिंग विभाग में जो काम हो रहा है उनमें इस बात का अन्दाजा लगाना मुश्किल है कि किसकी जिम्मेदारी है। आज वहां पर अधिकारियों में झगड़े होते हैं एक कहता कि मैं बड़ा हूं और दूसरा कहता है कि मैं बड़ा हूं। जो सही मायने में जनता का काम है वह नहीं होता है। मैं उदाहरण देता हूं हमारे देश में श्रमदान का काम सहारनपुर जिले में बहुत हुआ। वहां पर प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू भी आये थे और उन्होंने भी उसको देखा। कितने सरकारी कर्मचारी कई महीने पहले से वहां पर लगाये गये और काफी रुपया उसमें व्यय हुआ।

लेकिन जब मैंने सिंचाई विभाग के पूर्वी जमुना नहर के अधिकारियों से बात की जहां पर कि श्रमदान से सफाई की गयी थी तो उन्होंने बतलाया कि सिंचाई विभाग को इसकी सफाई में और ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा बमुकाबिले इसके कि जनता के द्वारा जो रुपया श्रमदान में खर्च किया गया। तो क्या इस प्रकार के प्रदर्शन से, इस प्रकार के श्रमदान में पानी की तरह रुपया बहाने से कोई आर्थिक विकास या समाज को विकास की तरफ ले जायगा यदि इस प्रकार से मुल्क में काम किया जाय, प्लानिंग विभाग में पानी की तरह से रुपया बहाया जाय तो इससे देश का भला होने वाला नहीं है। उसमें ऐसे-ऐसे सरकारी अधिकारी हैं जिनमें जनता में काम करने की प्रेरणा देने की कोई क्षमता नहीं है और जिनको गांव की धूल में चलने से जुकाम हो जाता है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि जो लोग २४ घंटे श्रमदान करते हैं उनके लिये अनेक प्रकार से पानी की तरह जीप में पेट्रोल पानी की तरह से बहाकर समाज कल्याण नहीं हो सकता है। यह तो और भी गरीबी को बढ़ाने वाली बात है।

[श्री रामचन्द्र विकल]

हमने देखा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर उद्योग की तरफ निगाह की जा रही है। हमारे यहां उद्योग धंधे होने चाहियें। परन्तु जैसा कि मुझको थोड़ा-बहुत तजुर्बा है, चन्द उद्योगपतियों को आप सहायता पहुंचाकर या कुछ ऐसे लोगों को रुपया देकर, जो निजी जीवन पर खर्च कर दें, उद्योग का विकास नहीं कर सकते हैं। इससे गरीबी का ही विकास होगा। छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को मुख्य रूप से नहीं देखा जाता। उनकी सहायता नहीं की जाती और यह सारा रुपया जिस प्रकार से जाता है, वह सब हमको मालूम है। आज जो खेती के नाम पर कुछ होशियार लोगों की सहायता की जाती है, उसमें वह होशियार लोग रुपया ले जाते हैं और वह जाकर खेती का कोई विकास नहीं करते हैं। जिस प्रकार से वह करते हैं वह भी हमको मालूम है। वह रुपया वह होशियार आदमी ले जाकर सरकारी कर्मचारियों में इनाम लेकर हिस्सा बांट देते हैं। आज देश में अन्न का उत्पादन बढ़ गया है। आज इन आंकड़ों पर परिपूर्णानन्द जी का विश्वास है जो अन्तर्राष्ट्रीय जगत से लाकर यहां पर सदन में पेश करते हैं। मैं भी जनता में रहता हूं। जिन दिनों इस देश में कंट्रोल लगाया जा रहा था तो हमारे सब माननीय मंत्री जी और बड़े लोग यह कहा करते थे कि देश पर भारी अन्न का संकट है, लेकिन जिस दिन रफी साहब की कृपा से इस देश में कंट्रोल हट गया तो फिर सब लोगों की तरफ से यह कहा गया कि अन्न का उत्पादन बढ़ गया है और भारी अन्न पैदा हो गया है। जनता जब कहती थी कि इस कंट्रोल को हटा दो तो आप कहते थे कि अन्न की कमी है, और जब कंट्रोल यहां से हटा दिया, तो आप कहने लगे कि अन्न का उत्पादन बढ़ गया है। चरण सिंह जी कहा करते हैं कि किसानों की पैदावार कम होती रही है मैं भी मानता हूं कि नयी जमीन तोड़ी गयी हैं लकिन क्या इतना अन्न बढ़ गया है कि जिसकी वजह से आज किसान के गल्ले का भाव इतना कम हो गया। सब कहते हैं कि किसान की हालत खराब है और किसानों के ऊपर करों का बोझ पड़ा हुआ है और आज किसान परेशान है, लेकिन अगर किसान आज परेशान है तो जिसकी तरफ सरकार की निगाह क्यों नहीं जाती है? आज यह कहना गलत होगा कि पश्चिमी जिलों के किसानों की हालत कुछ अच्छी है। वहां के किसानों से आज भी आबपाशी का चौगुना रूपया वसूल किया जाता है। मैंने इस विषय में माननीय मंत्री जी से कहा तो उन्होंने कहा कि बहुत पहले कमेटी बैठी थी उन्होंने यह सुझाव दिया था। मैं नम्रता के साथ मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पश्चिमी जिलों के किसानों की आमदनी, जो साल भर तक अपने परिवार के साथ खेत पर पड़ा रहता है, आज गन्ने के भाव में और दूसरी फसल की बिक्री के भाव में जो बाजार में बिकने जाती है कितना अन्तर है तो जो आज पश्चिमी जिलों में आबपाशी की दरें हैं उनको वहां के किसान बरदाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारी प्रार्थनाओं के बावजूद भी आबपाशी की दरें कम नहीं की गयीं। इसी प्रकार से, जो और टैक्सेज हमारे ऊपर हैं, वे बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। पंचायतों के टैक्स हर गरीब से बड़ी निर्ममता के साथ वसूल किये जाते हैं। यहां सवाल किये जाते हैं, बताया जाता है कि तहसील में जमा है और वह वाकई पंचायत अधिकारियों के प्राइवेट कोष में मिलता है। तहसील के गांव के लोगों को पैसा मिलने में कितनी तकलीफ होती है यह भी किसी से छिपा नहीं है। रोजाना प्रश्न आते हैं लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लोगों का यह कहना गलत नहीं है कि आज जनतंत्र केवल सरकारी कर्मचारियों की मुट्ठी में है और बचा-खुचा थोड़ा बहुत मंत्रियों की मुट्ठी में है। अगर हम ४६-४७ के मंत्रियों को देखें तो वे उस समय जनता में काम करने वालों से सलाह लिया करते थे लेकिन अब वह सुकड़ते-सुकड़ते यहां तक आ चुका है कि अगर किसी के लिये यदि माननीय मंत्री जी फोन कर देते हैं तब तो उसकी बात सुन ली जाती है नहीं तो किसी की कोई नहीं सुनता। मैं विधान सभा के सदस्य होने के नाते कहता हूं कि जिलों में आज कितने ही अत्याचार हो रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।

मैं भूल करूंगा यदि मैं इस समय पुलिस के बारे में कुछ न कहूं और वह इसलिये कह रहा हूं कि जिले के अन्दर डाकुओं का प्रभाव बहुत बढ़ा हुआ है। वहां पुलिस के सामने माननीय राज्यपाल महोदय ने पुलिस परेड के समय एक भाषण दिया था कि पुलिस के कर्मचारियों के करप्शन

को दूर करने के लिये भिन्न-भिन्न योजनाओं पर विचार करना होगा। लेकिन जब जिले और गांवों में जाकर वह सब देखते हैं जो कि पुलिस करती है तो बजाय इसके कि करप्शन बंद होता रिश्वत लेने के नये-नये ढंग निकाले गये हैं। हमारे यहां ५ थाने हैं, यदि जांच की जाय तो इन थानों की पुलिस द्वारा जितना जनता को लूटा गया है उतना डाकुओं के द्वारा एक वर्ष में नहीं लूटा गया होगा, डाकुओं न इतनी औरतों की बेइज्जती न की होगी जितनी पुलिस ने की है, डाकुओं ने लोगों की इतनी मूंछों को न उखाड़ा होगा जितनी पुलिस वालों ने, लोगों के उतने सिर डाकुओं ने न तोड़े होंगे जितने पुलिस वालों ने, लेकिन आज इसकी कोई जांच नहीं की जाती है। आज पुलिस सरे आम रिश्वत लेती और अत्याचार करती है। रिश्वत लेने के उसने नये-नये ढंग निकाले हैं। हमें जनता में जाने को मिलता है। वह पुलिस से डाकुओं को अच्छा समझती है। वह कहती है कि डाकू तो हमें रात में ही लूटते हैं लेकिन पुलिस तो दिन में ही लूटती है और पीटती है लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिये मैं कहता हूं कि जनतंत्र का थोड़ा बचा-खुचा भाग ही मंत्रियों के हाथ में है वरना सारा नौकरशाही के हाथ में है। जनतंत्र और समाजवाद का ढांचा किताबों में हम क्यों न बता दें लेकिन यह सच है कि जनता जो महसूस करती है यहां बैठकर आप लोग महसूस नहीं करते। मंत्रियों को यह सोचना पड़ेगा कि हम गांवों में जाकर समस्याओं का कैसे अध्ययन करें वरना खाली किताबों से जनतंत्र नहीं चल सकता। समस्याओं को सुनने के लिये और उनको समझने के लिये आपके पास समय होना चाहिये, और जब आपके पास इनके लिये समय होगा तभी आप कुछ कर भी सकेंगे। लेकिन जिस ढंग से आप चल रहे हैं वह सही तरीका नहीं है। मंत्रियों पर तो पुलिस का पहरा लग जाता है लेकिन आज विधान सभा के सदस्य और जन साधारण का जीवन खतरे में है और यदि वह होशियारी के साथ नहीं रहता तो उसका जीवन खतरे में है। बाराबंकी में ही नहीं दूसरे स्थानों में भी हालत बिगड़ती जा रही ह। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वे अपने काम के ढंग को थोड़ा बदलें और जनता क बीच में चलें और जिस नौकरशाही का आप हृदय परिवर्तन कर देना चाहते थे वह आज आपके ऊपर छा चुकी है। आप जिसका हृदय परिवर्तन करना चाहते थे जिसके कपड़ों को आप बदलवाना चाहते थ, मेरा तो अनुभव यह है कि उसने आपके हृदय को परिवर्तित कर दिया है और आपक वस्त्रों को बदल दिया है। आप उस के प्रवाह में बहे जा रहे हैं और यही कारण है कि आपको जनता के आदमियों पर विश्वास नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमसे कुछ कहा जाता है और कांफीडेंशियल आर्डर कुछ और ही जाते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे समाजवाद के ढांचे को अपनान में उसको कुछ देर लगे लेकिन उसको जनता की जान की रक्षा करने की सबसे पहले जरूरत है।

*श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे वक्त दिया। हमारे इधर के कुछ दोस्तों ने मुझे मशविरा दिया है और कुछ दोस्तों ने इजहारे ख्याल भी किया है कि मैं कुछ एहतियात करूं और दो लफ्ज न कहा करूं एक 'उर्दू' और दूसरा 'मुसलमान' तो। मैं कोशिश करूंगा कि इससे अपने को इस वक्त जरा दूर रखूं।

मैं परसों से इस बजट के बारे में बहस को सुन रहा हूं। जहां तक सयासी अल्फाज का ताल्लुक है पोलिटिकल डिक्शनरी का ताल्लुक है, बड़े-बड़े अल्फाज से सोशलिस्ट और सोशलिस्टक पर मुख्तलिफ तरीकों से इजहारे ख्याल किया गया। लेकिन अगर आप देखेंगे, मैंने उस तकरीर को बहुत गौर से देखा है, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बजट पेश करते हुये इरशाद फरमाई है, तो हम यह कहने पर मजबूर हैं कि उस पर गौर करने की जरूरत है। जो कुछ हो चुका है उसको बजट में दिखाया है और उस पर स्पीच सुनने के बाद जहां तक मैं बजट को देख पाया हूं मैं यह कहने पर मजबूर हूं कि यह बजट वाकयात पर मबनी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

इसके लिये फाइनेंस मिनिस्टर साहब यकीनन इस ऐवान के मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और वे उस मुबारकबाद को कबूल करने के अहल हैं। यह ठीक है कि बजट के मौकों पर जो तकरीरें की जाती हैं कुछ तकरीरें ऐसी हैं जो एक मियार से गिर कर हुई, लेकिन चन्द साहबान, जिनमें से एक साहब जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, ने कहा और एक वजीर साहब का नाम ले कर कहा कि पार्टीबाजी करते हैं। एक पार्टी में बैठकर दूसरी पार्टी वाले को इस तरह से कहें। यह तो न उन वजीर साहब के लिये मुनासिब था और उनके लिये भी मुनासिब नहीं होगा। आप भी हर जायज और नाजायज तरीकों से अपनी पार्टी को कायम रखने की कोशिश करते हैं और जो भी पार्टियां होंगी जो मुकाबिले में आ रही होंगी वह भी कोशिश करती होंगी। मैं खुद आपके उन उसूलों का जिनका आपने दावा किया था उन पर तनकीद कर सकता हूं लेकिन मैं एक लमहा भी यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं और न बरदाश्त करने के लिये तैयार हूं कि उपाध्याय जी पार्टीबन्दी करते हैं या दूसरे भाई पार्टीबन्दी करते हैं। अगर यह कहना ही है तो उसके लिये मैदान, या अमीनुद्दौला पार्क मुनासिब जगह होगी। उस जगह के लिये यह अल्फाज मुनासिब हैं लेकिन इस जगह पर ऐवान के अन्दर हम इसको बरदाश्त नहीं कर सकते।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जब यहां का रुपया खर्च कर रहे हैं तो यहां कहा जा रहा है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मैं उन लोगों में से हूं जो अपनी पार्टी के हर लीडर को और आपकी पार्टी के हर लीडर को भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपकी तरह से आपकी पार्टी के लीडरों के लिये ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करूं और इसलिये मैं इन अल्फाज को इस्तेमाल करने के लिये आपको ही मुबारकबाद देकर इस चीज को आपकी ही खिदमत में छोड़ना चाहता हूं।

मैं तनकीद करने वाला बदनाम भी हूं। कहीं और किसी मुसीबत में न पड़ जाऊं इसलिये मैं अपने को महदूद रखूंगा कि जो तरक्की सूबे में हो चुकी है और जो खिदमत सूबे के लिये की गई है उन की तरफ से कैसे आंखें फेर लूं यह तो बड़ी बददयानती होगी। अगर मैं यह न कहूं कि सूबे में नहरों का जाल नहीं बिछा है, चीजें मुकम्मल नहीं हुई हैं तो यह गलत होगा। हमारे मुअज्जिज वजीर ने निहायत अक्लमन्दी से नहरों और आबपाशी का सिलसिला शुरू किया है और जो रुपया बजट में रखा गया है वह भी काम को देखते हुये काफी नहीं है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें मिला है उस को मिला कर भी जरूरतों के एतबार से काफी नहीं है। स्कीमें बड़ी हैं, रुपया कम है लेकिन निहायत अक्लमन्दी की गई है कि जो इन चीजों को छोड़ दिया गया है जिनको बिल आखिर यह सरकार पूरा करेगी और जब यह स्कीमें पूरी हो जायंगी तो सूबे के अन्दर पैदावार आज जो बढ़ी है वह दुगुनी, तिगुनी और चौगुनी हो जायगी। और जो अवाम के लिये राहत का बायस होगा। ४,२०० ट्यूबवेल जून तक मुकम्मल हो जायेंगे यह ऐसी चीज नहीं है जिस से हम अपनी आंखें बन्द कर लें। इसके लिये मुअज्जिज वजीर साहब और यह पूरी गवर्नमेंट मुबारकबाद की मुस्तहक है।

जहां तक तालीम का ताल्लुक है मैं एतराज करने वालों में से हूं। मैंने मुख्तलिफ शोबो पर एतराज किया लेकिन उन पर तवज्जह नहीं की गई लेकिन फिर भी खामियां और कमजोरियां मौजूद हैं जिन को दुरुस्त करना है। यह मैं तस्लीम करता हूं कि कई लाख रुपया बच गया, खर्च नहीं हो सका। ८ करोड़ रुपया के करीब पुलिस के लिये था इसका हम एतराफ करते हैं और इसी तरह से बहुत बड़ी रकम हमने तालीम के लिये रख दी, तालीम की बड़ी रकम या पुलिस की बड़ी रकम मखसूस करने से काम नहीं चलता। देखना है कि तालीम कितनी दूर तक पहुंचेगी, आगे न बढ़ायें लेकिन कालेजों मदरसों को आंखें बन्द कर के एक गैरजानिबदाराना तरीके से इमदाद दें और जो इमदाद अब तक दी गई है उस में

बड़ी हद तक दयानतदारी बरती गई है, कहीं गलती भी हुई है, इसलिये एक माहिरे तालीम और रखा जाय जो इमदाद के तकसीम करने में मदरसों की जरूरियात को देखें । यह चीज बुरी है कि किसी स्कूल से कोई मिनिस्टर साहब खफा हो गये तो वहां की इमदाद बन्द कर दी, ऐसा न होना चाहिये ।

जहां तक पुलिस का ताल्लुक है उसके मुताल्लिक मैं समझता हूं कि यह मुहकमा बड़ी हद तक दुरुस्त होना चाहिये और जो हमारे मोअज्जिज चीफ मिनिस्टर साहब इस मुहकमें के इन्चार्ज हैं वह चीफ मिनिस्टर जिसकी काबलियत का एतराफ इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सभी लोगों ने किया है जब कि वह पहले मिनिस्टर तालीम थे। लेकिन इस मुहकमे में हम कोई नुमांया इस्लाह नहीं पाते हैं, जिस तरह से बड़े-बड़े डाकुओं ने हमारे सूबे की इज्जत को लूटा है उस से कहीं ज्यादा हमारी इज्जत और आबरू पर पुलिस वालों ने हमला किया है। आप कुछ भी करें मैं तो कहता ही रहूंगा, मैं कहने का तो आदी हो गया हूं और इस यू० पी० के अन्दर जो हो रहा है उसे हम बरदाश्त कर रहे हैं और बरदाश्त करते रहेंगे लेकिन मैं एक लम्हा भी यह सुनने को तैयार नहीं हूं कि हमारी औरतों की पुलिस के हाथ इज्जत बरबाद हो, मैं यह उम्मीद तो नहीं कर सकता कि इस ऐवान का कोई रुक्न यहां आकर गलत बात कहे। लेकिन एक आदत सी पड़ गई है कि हम कितने ही अदब के साथ अर्ज करें, वाकयात की छानबीन करने के बाद अर्ज करें लेकिन एक नीचे से नीचा और अदना चपरासी जो कह देता है, हम कितना ही कहें उस का यकीन नहीं किया जाता लेकिन उस की बात मान ली जाती है। यह कोई हुकूमत चलाने का बेहतर तरीका नहीं है।

जहां तक पी० डब्लू० डी० का ताल्लुक है। पिछले ४ साल गुजरे मैंने लिख कर दरख्वास्त भी दी लेकिन उस के बावजूद भी अतरौला की हालत वैसी ही है और आबादी के अन्दर से जो सड़क गई है उधर से एक मोटर गुजर जाती है तो कई घंटे के लिये जाड़े के जमाने में धूल अन्दर भर जाती है। एक तरफ तो लाखों करोड़ों रुपया मुख्तलिफ प्लान्स पर खर्च किया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ सरकार मनकापुर से अतरौली तक चन्द मील की सड़क का टुकड़ा नहीं बनवा सकती। मैं नहीं समझता कि किस खसूसियत के साथ तरजीह दी जाती है, नाप जोख भी हुई लेकिन कोई तजवीज वहां के लिये नहीं हुई।

जहां तक पूरब और पश्चिम के जिलों की तकसीम का मामला है, किधर कम खर्च हुआ और किधर ज्यादा, मैं उस मामले में मिनिस्टर को बहुत ज्यादा दयानतदार पाता हूं । चाहे पूरब में काम हो या मगरिब में लेकिन चीजों को फैलाने में उन्होंने गैरजानिबदारी से काम लिया है, मुझे एक भी वाकया नहीं मिला जिसमें कोई शिकायत का मौका हो। कभी-कभी कुछ टेक्निकल दिक्कत भी सड़कों के मामले में पड़ती है, पी० डब्लू० डी० कहता है कि सड़क हमारी नहीं है और बोर्ड कहते हैं कि हमारी नहीं है और इसी झगड़े में सड़क नहीं बन पाती। मैं सरकार से बताना चाहता हूं कि अगर इस तरफ़ खास तौर से तवज्जह नहीं की गई तो लोगों की तरफ से सख्त तरीके से शिकायतें आनी शुरू हुईं तो वह इस में हकबजानिब होंगे।

जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन को देखता हूं तो मुझे शिकायत करनी पड़ती है कि आप बाज चीजों की तरफ तवज्जह नहीं करते। सन् ४२ में अंग्रेजों ने लूटमार की है। आप के कानपुर और इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी के ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं, बड़े-बड़े मिश्र के बादशाह गुजरे हैं और बड़ी बड़ी हुकूमतें उन की हुई लेकिन उन में से किसी ने अवाम को इतना नहीं सताया और लूटा जितनी कि अवाम इन ऐडमिनिस्ट्रेटर्स साहबान के जरिये लूटी जा रही है और उनके मकानों तक को चन्द घंटों में खोद कर फेंका जा रहा है, फरयाद करने उनके पास कोई जाता है तो उस की बात भी नहीं सुनी जाती, फिर मजबूर हो कर यहां गवर्नमेंट के सामने उन शिकायात को लाना पड़ता है, इलाहाबाद की लीडर रोड पर जो कुछ हुआ

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

उसको सुनकर आप को हैरत होगी, यहां पर कुछ गरीबों की दुकानें थीं कुछ रिफ्यूजीज की थीं सात आठ और ८ दुकानें हरिजन भाइयों की थीं उनसे हद दर्जा किराया लिया जा रहा था। मिनिस्टर साहब को उनके मुताल्लिक मैंने दरख्वास्त दी तब जा कर सेक्रेटरी साहब ने स्टे आर्डर दिया कि सख्ती न की जाय लेकिन आर्डर देने के बावजूद भी वहां पर दुकानें इस तरह से लूटी गई हैं कि मानों कोई दुश्मन दूसरे मुल्क पर चढ़ गया हो। वक्त हो गया है, बहुत सी बातें अर्ज करनी थीं उनके मुताल्लिक फिर कभी अर्ज करूंगा। आप देखें कि साल डेढ साल से बहुत से मामले ऐसे चल रहे हैं, आप नाराज न हों, गुस्सा न हो, धमकी देने की कोशिश न करें मैं इतना पुराना आप का खादिम हूं कि रोज की धमकियों से दिमाग-पर कोई अब बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है क्योंकि जहां तक अर्ज करने का ताल्लुक है आप ज्यादा से ज्यादा दरवाजा बन्द कर देंगे, तो भी मैं आपके दरवाजे पर जा कर अर्ज करूंगा और जो वाकयात हैं वह तो बेनकाब हो कर कभी न कभी दुनिया के सामने आवेंगे। मैं जल्दी से जल्दी दो चार बातों की तरफ आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं अवाम की हालत आज अच्छी नहीं है। तालीम का जहां तक ताल्लुक है उस में स्कूलों को इमदाद बहुत कम दी जाती है। अवाम उन स्कूलों को चला नहीं सकती लिहाजा उनको इमदाद बढ़ाई जाय। मैं किसी एक मखसूस नहीं, हजारों मदरसों के लिये कह रहा हूं। एक चीज यह भी अर्ज कर दूं कि सूबे में अमनोअमान के लिये और कम्युनल हारमनी के लिये एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाय जो सरकार को मशविरा दे और छोटी-छोटी चीजें जिनमें कि गवर्नमेंट बदनाम होती है उनको उसके जरिये हल किया जाय और उसके मशविरे पर आप अमल करें। मैं एक बात और अर्ज करूं कि मुझे मालूम हुआ है कि एक ऐसा कानून आप के सूबे के अन्दर आनरेबिल चीफ मिनिस्टर जो हमारे सबसे बड़े मुहतरिम लीडर हैं, कानपुर के कुछ लोग आकर उनसे मिले, और उन्होंने उनसे वादा किया, अखबारों में निकला था तारीख भी दे दी गयी थी, आपने वादा कर लिया है कि एक कानून बहुत जल्द बनायेंगे, जिससे किसी मजहब के पेशवा पर कोई हमला न हो। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, अगर यह वाकया है। अगर यह वाकया नहीं है तो तवज्जह करेंगे। मैं चाहता हूं कि जितने भी मजहब यू० पी० के अन्दर ह, चाहे उसका मानने वाला एक ही आदमी हो वह कांग्रेस गवर्नमेंट के जेरे साया खड़े हो कर ऐलान कर सके, कि हमारा मजहब महफूज है, हमारा कल्चर महफूज है, हमारी जबान महफूज है, हमारी तालीम महफूज है, हमारी रवायात महफूज है, हमारी इज्जत महफूज है, हमारे बाल-बच्चे महफूज हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने किसी को जबान देकर इनको महफूज करने का वादा किया है। मैंने जो अर्ज किया है उस पर गवर्नमेंट पूरे तौर से ध्यान दे।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बजट पर बहस होते हुए तीसरा दिन है। और बजट के फाइनेंशल ऐस्पेक्ट के ऊपर, और सरकार की नीति और समाजवाद के प्रत्येक पहलू पर पूरी तौर पर इस सदन में विचार विवेचनात्मक ढंग से हुआ है। उस मामले में मुझे और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात जो स्पष्ट मालूम हुई वह यह कि दो किस्म की विचारधाराएं इस सदन में प्रस्तुत की गयी हैं। एक विचारधारा इस बात की तरफ है कि सरकार ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप आशातीत प्रगति की है। उन्होंने अपने टार्गेट्स से अधिक उन्नति की है और लोगों की खुशहाली बढ़ी है। जब कि इसके बरक्स दूसरा व्यू भी इस सदन में रखा गया। वह यह है कि लोगों की हालत पहले से खराब है। लोगों की हालत में कोई फर्क नहीं हुआ है। इस बात को मानते हुए भी कि सरकार ने पंच-वर्षीय योजना में कई करोड़ रुपये रखे, वह खर्च हुए और आज भी कोई परिवर्तन और प्रगति नहीं दिखाई देती इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हमारी सरकार और सरकार के पक्ष को प्रतिपादित करने वाले प्रगति का जो चित्र देखते हैं वह उन आंकड़ों

से देखते हैं, उस आइने में देखते हैं जो कि उनके कर्मचारियों द्वारा उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है और दूसरा पक्ष तो यह देखता है कि कोई भी प्रगति नहीं हुई है वह इसलिये है कि वह लोग जनता के सम्पर्क में रहते हैं, उनकी वास्तविक स्थिति को समझते हैं और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भवन के बाहर जो बड़ा भारी प्रदर्शन हो रहा है उससे आंका जा सकता है, आखिर आपस में इस दृष्टिकोण में इतना विरोध क्यों है ? मेरी समझ में इस दृष्टिकोण में विरोध यह है कि इस प्लान से कुछ ही व्यक्तियों को फायदा पहुंचा है, उस प्लान में कैपिटलिस्ट इकोनोमी पर अमल किया गया है। अमीरों को ही ज्यादा फायदा पहुंचा है। आमतौर पर जो ग्रामीण जनता है, जो मजदूर क्लास है, जो कि गांवों में बसते हैं, जिसे सही हिन्दुस्तानी कहते हैं, उनको सही मानी में कोई फायदा नहीं पहुंचा। इसका कारण यह है कि हमारा जो प्लान है वह बिलकुल अनप्लांड, अनसिस्टेमेटिक, अनसाइंटिफिक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कभी यह आशा नहीं की जाती थी। सरकार ने यह आदेश जारी किये थे कि ग्राम स्तर से योजनाएं तैयार हों। जो जिलों से योजनायें बन कर आयीं उनके आधार पर सरकार ने पंचवर्षीय योजना न बना कर अपना ही प्लान जनता के ऊपर थोप दिया। इस प्रकार की योजनाओं से ग्रामीण जनता का, कृषक वर्ग का, जिसकी तरक्की करने के लिये यह सरकार कहती है, कोई तरक्की नहीं हो सकती है। श्रीमन्, इस प्रकार के प्लान का क्या कारण है ? ऐसा क्यों बनता है ? इस पर काफी विवेचना इस सदन में हो चुकी है। इसका कारण जहां तक मैंने पाया, प्लानिंग कमेटी की मीटिंग अटेंड कर के भी, वह यह कि इस प्लान के बनाने में, बजट के बनाने में पालिटिकल कंसीडरेशंस होते हैं। इस से सब खराबियां पैदा हो गई हैं। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से प्लान न बनाया जाय, और समस्त प्रदेश का सर्वे कर इस दृष्टिकोण से बनाया जाय कि किस जिले में, किस हिस्से में कौन सी आवश्यकता है, वह पूरी की जाय, तो शायद सच्चा प्लान हो सकता है, राजनीतिक आधार पर जो प्लान बनता है उससे करप्शन फैलता है और सब से बड़ी बात यह है कि हमारी सिविल सर्विस का मारल कम होता है। आज सर्विसेज के लोग भी जिस ब्यूरोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ बयान किया जा चुका है, वह देखते हैं कि हमारे बासेज, हमारे पालिटिकल पार्टीज के लीडर्स, किस तरह का प्लान चाहते हैं। और उनके साथ मिल कर के वे सिर्फ़ अपनी सर्विस में मोनोपाली कायम चाहते हैं। सिवाय इसके और कोई बात नहीं मालूम पड़ती। श्रीमन्, डेमोक्रेसी में पार्टियां बदलती रहती हैं। आज कांग्रेस पार्टी है, कल सोशलिस्ट पार्टी आये। लेकिन सिविल सर्विस को फ़र्म स्टैन्ड होना चाहिये और उस स्टैन्ड के लिये आप क्या ट्रेडीशन कायम करते हैं यह रूलिंग पार्टी पर मुनहस्सिर करता है। इसके अलावा श्रीमन्, मैं तो समाजवाद के ऊपर विशेष बात नहीं कहना चाहता।

मैं तो समाजवाद इस सरकार का इसके बजट में देखता हूं। जब बजट भाषण के संदर्भ में बजट को उठा कर के देखते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो अलोकेशन आफ़ फ़ंड्स जिलों में किये गये हैं उनमें कौन सा समाजवाद है आप बजट उठाकर के देखें कि अगर एक जिले को, मसलन् कम्यूनिकेशन में ही, कई लाख रुपये दिये गये हैं तो दूसरे जिले को, जहां उनकी ज्यादा जरूरत है, नगण्य हिस्सा दिया गया है। मैं जब यहां बैठा हुआ था मैंने अपने मित्र जो अल्मोड़ा से आते हैं उनके भाषण को सुना और उसे सुन कर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा में कोई प्रगति नहीं हुई और सब से पिछड़ा हुआ है। मैं तो उस वक्त घबड़ा गया क्योंकि मैं सदन में यही कहने आया था कि इस प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जो ४ जिले मौजूद हैं, उनके सम्बन्ध में क्राइटेरियन यह होना चाहिये कि जो सब से ज्यादा पिछड़ा हुआ है उस की तरक्की की जाय। ऐसा नहीं कि जिसका पेट भरा हुआ है उसके पेट में और ठूंस दिया जाय और जो भूखा है उसको मरने दिया जाय। लेकिन उनके भाषण को सुनने के बाद जो बजट को उठा कर के देखा और यह कोशिश की कि वह कहां तक सही कह रहे हैं। मैंने देखा कम्युनिकेशन को ही लीजिये इसी साल के बजट में ५९ लाख रुपया अगर अल्मोड़ा को मिला तो टेहरी को ६ लाख रु० में यह नहीं कहता कि सडकें वहां नहीं बननी चाहियें, जरूर बनें। मैं नहीं कहता कि अगर हाल इलेक्शन के दौरान

[श्री सत्यसिंह राणा]

में माननीय मंत्री जी ने वहां के सब अस्पतालों को, स्कूलों को प्राविंशियलाइज़ कर दिया तो गलत है, बल्कि ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अल्मोड़ा के प्रतिनिधि को प्रज है तो हमारे क्षेत्र को उससे कई गुना मदद की जरूरत है और उसको उतना ही ज्यादा मिलना चाहिये। तब तो मैं समझूं कि समाजवाद है।

(इस समय २ बज कर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इस प्रकार श्रीमन्, हर क्षेत्र में अगर बजट उठा कर के देखें तो पता चलेगा कि मेरे जिले टिहरी-गढ़वाल का हिस्सा बजट में बिल्कुल नगण्य है और अगर हमारे मंत्री जी देखें तो पता चलेगा कि हम झूठ नहीं कहते। अगर गढ़वाल में बद्रीनाथ और केदारनाथ और टेहरी में गंगोत्री और यमुनोत्री न होते तो क्या उन जिलों को कोई पूछने वाला था? आप बजट में देखें कि इन्हीं हिस्सों की ओर सरकार का ध्यान कुछ क्षेत्र में है। टेहरी-गढ़वाल के इस लगभग १/४ हिस्से तक ही सीमित है। सरकार यह नहीं देखती कि गंगोत्री के इस तरफ भी ३/४ हिस्सा है, जिस तरफ सरकार का ध्यान कतई नहीं है। इस का कारण है।

माननीय नरेन्द्र सिंह विष्ट जी कहते हैं कि अल्मोड़े को दो हिस्सों में बांट देना चाहिये। अगर ऐसी स्थिति है तो जरूर हो। लेकिन मैं एक प्रैक्टीकल सुझाव देता हूं और आशा है कि सरकार गौर करेगी। असल में कुमायूं के चारों जिलें एक डिवीजन में हैं और हमारे यहां डेवेलपमेंट के जितने फंड्स होते हैं उनका कामन अलाटमेंट होता है जब कि जिलेवार उसका अलाटमेंट होना चाहिये। इसके अलावा जो हमारे यहां डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज होते हैं वे नैनीताल में रहते हैं, कन्जरवेटर आफ़ फारेस्ट्स नैनीताल में रहते हैं। अ० डेवलपमेंट ओ० व डिप्टी डाइरेक्टर आफ़ इंटस्ट्रीज भी नैनीताल में रहते हैं और डाइरेक्टर आफ़ फ्रूट यूटीलाइजेशन जिनका वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में जिक्र किया वह रानीखेत में रहते हैं। तो वहां से टिहरी और गढ़वाल में आवागमन के साधन प्रचुर मात्रा में न होने के कारण इन जिलों का पीछे रह जाना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में मेरा सुझाव सरकार के सामने यह है कि जिलेवार अगर फंड्स का अलाटमेंट हो और उसके साथ-साथ जैसा कि आप ऐडीशनल कमिश्नर्स बढ़ा रहे हैं तो एक कमिश्नर गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल के लिये अलग से नियुक्त हो। और मैं यह भी समझता हूं कि डाइरेक्टर आफ फ्रूट यूटिलाइजेशन का दफ्तर लखनऊ में हो तो ज्यादा फायदा हम लोगों को पहुंच सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब कि इस प्रकार फंड्स का कामन पूल है हम बटवारे में सब से पीछे रह जाते हैं। यह हमारा सब से बड़ा रिसेंटमेंट है। यह मैं इस गरज से नहीं कह रहा हूं कि किसी को ज्यादा तरजीह क्यों दी जा रही है। वहां भी डेवेलपमेंट होना चाहिये। लेकिन हमारा जो कि ज्यादा बैकवर्ड क्षेत्र है उस को उससे भी ज्यादा मिलना चाहिये, इस बात की मेरी पुकार है। मैं सरकार के सामने क्या अर्ज करूं। मैं तो सुझाव के तौर पर यह सब बातें कह रहा हूं और यह कहूंगा कि सरकार अगर सचमुच यह चाहती है, समाजवाद चाहती है, तो कम से कम समाजवाद इस दृष्टिकोण से देखे कि वह रुपये का बटवारा कैसे करती है। वह जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उनकी तरक्की के लिये कैसे अपना प्लान बनाती है। हमारे जिले में किस बात की कमी है? हमारे जिलों में बिजली की शक्ति बहुत ज्यादा है। उसका सदुपयोग किया जा सकता है। हमारे जिले में मिनरल रिसोर्सेज बहुत पड़े हुये हैं। लेकिन मेरी बदकिस्मती है से, जब-जब मैंने क्वेश्चंस आन्सर्स को देखा, या बजट स्पीच को देखा तो उसमें गढ़वाल और अल्मोड़ा का जिक्र है, टेहरी-गढ़वाल का कोई जिक्र नहीं है। अगर वहां की पावर को इकट्ठा किया जाय, अगर वहां के मिनरल रिसोर्सेज को टैप किया जाय तो यह सारी कंट्री के लिये एक देन हो सकते हैं। क्या वजह है कि अलकनन्दा, गंगा, जमुना, टोंस जैसी नदियों के बहते हुए भी सारी जमीन पानी के लिये तरसे? क्या किसी ने जानकारी करने की कोशिश की? मैं तो यह कहता हूं कि जिले के जो अधिकारी

होते हैं वह भी अपने हेडक्वार्टर्स से बाहर जाने का नाम तक नहीं लेते। क्या सरकार को जानकारी हो सकती है इन जिलों के मुताल्लिक़ ? नरेन्द्र सिंह जी कहते हैं कि पहाड़ में ऐसे हिस्से हैं जहां लोग लंगोटी पहनते हैं। सरकार की आंखें वहां पहुंच ही नहीं सकतीं। ऐसी स्थिति में मैं पूरे तौर से सरकार को यह कन्वे कर देना चाहता हूं कि चाहे हम लोग अपोजीशन में हों, कांग्रेस पार्टी के मेम्बर न हों लेकिन तो भी सरकार का यह फर्ज है कि सरकार उस व्यू से ऊपर उठ कर के वहां डेवलपमेंट की पूरी कोशिश करे।

श्रीमन्, इसके साथ-साथ हमारी बदकिस्मती एक और यह भी है कि हमारा जिला मर्ज्ड स्टेट्स में से है और यह पर्वतीय होने के साथ-साथ दूसरा डिस्क्वालीफिकेशन है उसके लिए। मर्ज्ड स्टेट्स के साथ सरकार ने जो रवैया अख्तियार किया है वह निहायत शर्मनाक रवैया रहा है। वहां की पूरी सर्विसेज अब तक ऐजार्ब नहीं हो पायीं और उनकी सीनियारिटी जो फिक्स की गई वह तो अन्याय की पराकाष्ठा है। वह चाहे वहां ज्यादा तनख्वाह पाते रहे हों, चाहे उनका एक्सपीरिएंस ज्यादा हो, लेकिन जिस दिन वह इस प्रदेश में मर्ज हुए, उस दिन से वह यू० पी० में दूसरे कर्मचारियों से नीचे कर दिए गए। क्या न्याय है इसमें, क्या क्राइटेरियन है, सरकार बता दे ? इस विचार को बिला किसी आधार के, सीधे तौर पर एक ऐसी आज्ञा जारी कर देना जिसकी तहत में कोई न्याय नहीं, यह उचित नहीं है।

तो श्रीमन्, मेरी अर्ज इस सम्बन्ध में यही है कि हमारे यहां की समस्या, काश्तकारों की समस्या पूरे तौर पर है। हमारे यहां की समस्या गरीब मजदूरों की समस्या है। जमींदारी उन्मूलन सब जगह हो गया है, हमारे यहां नहीं हुआ, शायद होगा, और हो या न हो, बराबर है, उससे कोई लाभ किसानों को होने वाला नहीं है, उससे क्या भूमिहीनों की समस्या हल होगी। आज कैपिटलिस्ट्स और मजदूर वर्ग जो हैं क्या उनकी समस्या हल हो गई है ? बड़ी तनख्वाह पाने वाले और छोटी तनख्वाह पाने वालों के बीच की असमानता दूर हो गई ? जिनके पास पैसा ज्यादा है उनके हाथ में आज नकेल है उस मैन पावर की, उस जनशक्ति की जो कि हिन्दुस्तान की एक मात्र पूंजी है और अगर यही तरीका रहा तो इस क्लास को चन्द शीर्षक जिन्दा रखेंगे किसी न किसी तरीके से, इस जनशक्ति को उनके भूखे पेटों के ऊपर कूदने के लिये और उनकी कब्र के ऊपर मौज उड़ाने के लिये। मैं यह कहता हूं कि अपनी इकोनामी आप अमेरिका की तरह अख्तियार न करें, रूस की तरह न करें लेकिन जमीन का बटवारा तो कर सकते हैं, जो समाजवाद का नारा है। जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट्स हैं उनकी पूंजी पर इस तरह बन्दिश करिये कि उनको अपने फायदे की ज्यादा पूंजी इकट्ठा करने की गुंजायश न हो और वे उसको मजदूर और किसान वर्ग के शोषण की दिशा में इस्तेमाल न कर सकें ? समाज की इस असमानता को दूर किया। जब तक ये बातें नहीं होतीं तब तक मैं कहता हूं कि सही समाजवाद नहीं आ सकता और अगर समाजवाद नहीं आ सकता तो बहुत जल्द एक ऐसी क्रान्ति आने वाली है जिसकी रूप रेखा आज इस सदन के बाहर अभी देखने को मिल सकती है।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हाउस में तीन दिन से लगातार माननीय वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उस पर भाषण हो रहे हैं। तीन दिन से बराबर ही दोनों ओर के भाषणों को सुना और विचार भी साथ में किया। समाजवाद की क्या परिभाषा होनी चाहिये और समाजवादियों द्वारा उसकी क्या परिभाषा है इसका भी यहां पर जिक्र किया गया। सबसे पहले और बातों में न जा कर मैं वित्त मंत्री को हार्दिक धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने अपने प्रदेश का बजट पेश करा, जिसमें यह दर्शाने की कोशिश की कि अपने प्रदेश में समाजवाद का नमूना बनाने की कोशिश की जा रही है। बजट के देखने से यह नहीं कहा जा सकता कि अपने प्रदेश में कल्याण के कार्य छोड़ दिये गये हैं। जनता भी यही चाहती है और हर साल यह

[श्रीमती चन्द्रवती]

प्रतीक्षा करती है कि इस वर्ष हमारी सरकार उनके कल्याण के लिये क्या-क्या और अच्छे काम करने को रख रही है। मेरी समझ में, यदि मैं भूल न करूं, तो यह कहूंगी कि हर साल घाटे का बजट पेश होना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती। अच्छी बात नहीं मानी जाती इन मानों में कि उसका बोझ हमारी गरीब जनता के ऊपर पड़ता है। यदि बजट बनाने से पहले जब हमारी पंचवर्षीय योजना लागू की जाने वाली थी, सरकारी अफसरों द्वारा इतना सहयोग न ले कर कुछ थोड़ा सा जनता की ओर से प्रोत्साहन लिया जाता तो वह अधिक रुचिकर हो सकता था। जैसी कि हमने सदन में समय समय पर इस बात की चर्चा की है कि आज जिलों में जो कमेटियां बनायी गयीं हैं और सरकार की भी भावना यह थी कि जिलों में ऐसी कमेटियां बनायी जायं, पंचवर्षीय योजना बनाने के पहले जो कि वहां की जनता की वस्तुस्थिति का ज्ञान करके अपनी मांग पेश करें और वे मांगे यहां पर अधिकारियों द्वार जांच करके पंच वर्षीय योजना बनाने का कार्य हो सकता था। यह बहुत ही अच्छा मौका था जनता के दिल को जीतने का। जनता के हित के लिये काम करने में यदि थोड़ा सा व्यय करना पड़ता तो मैं इसे फिजूलखर्ची नहीं कह सकती। आज हमारे सब के सामने देश की भलाई का एक नक्शा है। हमारे देश में सब एक ही दृष्टिकोण से सोचते हैं, यह कहना भी बड़ा मुश्किल है। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि अपने सोचने का सब का दृष्टिकोण एक ही हो। यदि ऐसा हुआ तो फिर अन्तर ही क्या रह जायगा।

हमारे समाजवादी भाई जो समाजवाद का दम भरते हैं और जब उनके इस समाजवाद को ही सरकार ने अपना लिया तो फिर उनके पास क्या रह जाता है, तो वह समाजवादी से खोखे रह जाते हैं। जब हमारी सरकार ने उनके समाजवाद के ऐसे "सोशलिस्टिक पैटर्न" को अपना लिया तो फिर उनके पास क्या रह गया है? जमींदारों को तो जमींदारी समाप्त करते समय कुछ न कुछ मुआवजा भी दिया गया लेकिन इन समाजवादी भाइयों का "सोशलिस्टिक पैटर्न" अपना कर फिर भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इसके लिये मैं क्या कह सकती हूं? इतना सब कुछ होने पर भी यह मैं अवश्य कहूंगी कि अपने प्रदेश में गतवर्ष से प्रगति का कार्य दिखाई पड़ता है। अन्न की समस्या भी काफी सुलझाई जा चुकी है। फिर भी यदि परिस्थिति विपरीत हो जाय तो मैं समझती हूं कि हमारे स्थान पर वह भाई भी होते तो कुछ नहीं कर सकते थे। यहां पर अब मैं समय के अभाव में अधिक गहराई में न जाकर बजट के दूसरे दृष्टिकोणों को उठा कर देखती हूं।

इस बजट में साढ़े नौ करोड़ का घाटा गरीब जनता की पीठ पर लदने वाला है। अच्छा नहीं लगता है कि गरीब जनता की कृषि उत्पादन का क्रय-विक्रय होता है तो उसमें भी उनको कम मूल्य मिलता है। फिर वह टैक्स के रुप में कहां से लायें। मैं अपने तीन चार सुझावों पर माननीय नियोजन, वित्त और शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, इस बजट को बनाने से पहले थोड़ा सा इकोनोमी की तरफ ध्यान कर लिया जाता तो इतनी डेफीशियेन्सी बजट में नहीं हो सकती थी।

हमारे सामने दो तीन समस्यायें आती हैं। एक तो यह कि नियोजन मंत्री के ऊपर काफी बौछार की गई है। उनके विभाग की सबसे बड़ी समस्या है। प्लानिंग विभाग ऐसा है कि इसमें अधिक खर्च करना लाजमी हो जाता है। इन चीजों पर जो अधिकारी वर्ग द्वारा फिजूल खर्ची से खर्च किया जा रहा है उस पर अधिक ध्यान दिया जाय। मैं अधिक न कह कर केवल इतना कह सकती हूं कि आपके प्लानिंग के अधिकारी हैं, जैसा कि सदस्यों ने कहा है वह सरकारी गाड़ियों में घूमते हैं और अपने ऐश आराम पर ज्यादा ध्यान देते हैं, सरकारी काम हो या न हो। एक महिला मंगल योजना जारी की गई है, वहां महिलाओं का जो काम होता है वह प्लानिंग के अधिकारी के अधीन कर दिया गया है। वह महिला चाहे पैदल जाय, या बस से जाय। चाहे तांगे से जाय उसको कोई परवाह नहीं होती और

वह इतना भी समझने की कोशिश नहीं करता कि यह भी इसी प्रदेशीय सरकार का नौकर है। इसको मैं उस महिला का दुर्भाग्य कहूं अथवा उस नियोजन अधिकारी का सौभाग्य कि यदि उस महिला को जिले में कहीं जाना पड़ता है तो उसको गाड़ी नहीं मिल सकती है, लेकिन यदि नियोजन अधिकारी अपने अन्य १० अफसरों को बैठा कर पिकनिक करने जाना चाहता है, या शिकार खेलने जाना चाहता है तो उसको कोई रोक नहीं है। मैं समझती हूं कि इस बात पर आपको गौर करना होगा कि या तो आप इस महिला मंगल योजना को ही खतम कर दें या फिर इसको स्वतंत्र रूप से चलावें। इसको इस रूप में चलाना खतरे से खाली नहीं है। मेरे अनुभव में यह भी आया है कि जो महिलायें इसमें कार्य करती हैं उनको एक नियोजन अधिकारी के चरित्र पर भी विश्वास नहीं है और उनके सामने ऐसी समस्या खड़ी कर दी जाती है कि उसको अपना चरित्र सम्हालना मुश्किल पड़ जाता है। नियोजन मंत्री स्वयं जानते हैं, ऐसे अनुभव उनके सामने आये हैं उन पर क्या कार्यवाही हुई, यह मुझे नहीं मालूम।

मैं एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। हमारे बजट में जो कंटीजेन्सी फंड रखा गया है उस सिलसिले में तीन चार दिन हुए वित्त मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया था कि उसमें कुछ परसेंट कर देने से कई लाख की बचत गत साल हुई है। मैं सोचती हूं कि जब बचत की इतनी गुंजाइश है तो इस कंटिजेन्सी फंड को क्यों नहीं घटा दिया जाता या इसको क्यों नहीं एक बहुत अल्प मात्रा में रख दिया जाता। एक बचत हमारी इस कंटिजेन्सी फंड से हो सकती है। दूसरी बचत जो हमारी एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्टस् हैं उनकी तरफ ध्यान देने से हो सकती है। उसका चर्चा भी यहां पर हुआ, बहुत से भाइयों ने उसकी चर्चा की। मैं इस पर अधिक बात न कह कर इतना कहना उचित समझती हूं कि अगर उनकी रिपोर्टस् पर अमल किया जाता तो वह एक अच्छा बचत का साधन हो सकता था और ऐसा करने से जो इस कमेटी पर व्यय होता है उसका सदुपयोग हो सकता है। आज हमारे सामने एक समस्या है, हम उसके लिये कमेटी बना देते हैं। एक खलबली सी चारों तरफ मच जाती है। उसके बाद उसके मेम्बर्स नियुक्त होते हैं, लेकिन उसके बाद मैं देखती हूं कि जब उस कमेटी की रिपोर्टस् पर कार्यवाही होने की नौबत आती है तो वहां शून्य होता है। इस पर मैं अधिक न कह कर यह कहना उचित समझती हूं कि उसकी रिपोर्टस् पर अच्छा होता अगर विचार कर लिया जाता। नहीं तो इस कमेटी को भी खत्म करके धन के अपव्यय को बचा लिया जाता।

अब एक समस्या यहां के विरोधी दल के नेता श्री गेंदा सिंह जी ने रखी, शुगर केन के बारे में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के सामने कह देना चाहती हूं कि इस बात में मैं उनके समर्थन में हूं और उनको इस समस्या को सुलझाने में सहयोग देना चाहती हूं। मैं मानती हूं कि मैं ही नहीं भवन के सभी सदस्य इस बात को मानेंगे कि शुगर केन की समस्या गरीबों और काश्तकारों की समस्या है और यह समस्या हमारे सारे प्रान्त की समस्या है और इसको जितना ही जल्दी सुलझाया जाय उतना ही अच्छा होगा। माननीय मंत्री जी के कुछ अधिकारी इस बात के लिये नियुक्त किये गये थे कि वह और प्रदेशों की परिस्थिति का ज्ञान कर लेने के बाद रिपोर्ट पेश करें और फिर यहां कोआपरेटिव बनाने के लिये और सोसायटी फैक्टरी स्थापित करें तो निश्चय ही इस देश और प्रदेश में किसानों की शुगर केन की समस्या हल हो सकती है। और इस प्रकार बजट के उस घाटे को बहुत अंशों में कम करने में भी सहायता मिल सकती थी।

†नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा इस समय बोलने का नहीं था क्योंकि ऐसा मेरा विश्वास था कि सदन के उप नेता वित्त मंत्री महोदय उन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे जिन प्रश्नों को माननीय सदस्यों ने अपनी विभिन्न आलोचनाओं में उठाया है। परन्तु मेरा नाम बार बार याद करने से मुझे भी थोड़ी ऐसी उमंग पैदा

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

हुई कि २, १ शब्द में भी इस सदन में उन माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत कर दूं जिन्होंने मुझे बहुत तरह से सम्बोधित किया है और बहुत तरह से याद किया है। मैं जानता हूं कि ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आता जायगा तब तक मेरी याद मेरे मित्रों को ज्यादा होती जायगी और यह कोई नई बात नहीं है। मैं सन् १९५१–५२ को भूला नहीं हूं और इस सदन के सदस्य भी अभी उस जमाने को भूले नहीं हैं। वही दोनों कुर्सी थीं जहां पर विरोधी दल के नेता और उपनेता बैठते थे और ज्यों-ज्यों चुनाव का जमाना नजदीक आता गया त्यों-त्यों मेरे प्रति याददाश्त उनकी बढ़ती गयी और आज जब माननीय गेंदा सिंह जी और माननीय उपाध्याय जी को मेरी याद विभिन्न मौकों पर आयी तो मैं ऐसा समझता हूं कि कदाचित् वही अवसर फिर से आने वाला है। मैं उस जमाने को भूला नहीं हूं और उन बातों को भी नहीं भूला हूं और अपने उन विभिन्न नामों को नहीं भूला हूं जिनको माननीय विरोधी दल के नेता और उपनेता ने मेरे सम्बन्ध में व्यक्त किये थे। मुझे थोड़े बहुत नज्जारे उसी जमाने में देखने को मिले।

मैं नहीं जानता कि नियोजन विभाग ने या उद्योग विभाग ने या स्वास्थ्य विभाग ने कौन सा ऐसा कसूर कर दिया जिनसे माननीय उपाध्याय जी ने मेरे लिये इस प्रदेश से निकालने की व्यवस्था रख दी। सिर्फ एक बात ही मैं समझ सका और वह बात यह है कि कदाचित् विरोधीदल के नेता और उपनेता ऐसा समझते हैं कि प्रदेश में इधर बैठने वाले व्यक्ति अभी ऐसा अनुभव करते हों कि जिन बातों का वह प्रचार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं कदाचित् उनके द्वारा उनकी भ्रमात्मक बातों से, उनकी गलत बातों से और उनकी गलत नीति से इस प्रदेश के रहने वालों के दिलों में असर होने वाला है। कदाचित् उनके साथी मुझे प्रतीक बना कर इस सदन में कोई बात नहीं कहते थे। मुझे उन बातों की चिन्ता नहीं है क्योंकि जिस व्यक्ति ने विभिन्न नाम विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा पुकारे जाने को देख रखा हो वह आज भी प्रदेश में प्रदेश के विनाशक के नाते पुकारा जाय तो फिर उसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैं तो इस मायने में इसको गौरव की बात समझता हूं। मैं भले ही अपने उस दल के विचारों का प्रतिनिधित्व करने के योग्य न हूं किन्तु मैं केवल उमंग और उत्साह के द्वारा यदि वह भ्रमात्मक बातें, गलतफहमी के आधार पर गलत क्षेत्रों में बातें कह कर विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश के इस प्रकार के विभिन्न नाम सुनने को मिलें तो मैं इसको गौरव की बात मानता हूं।

आज शिकायत यह है कि यह कांग्रेसी दल समाजवादी व्यवस्था की रचना की बातें करता है परन्तु यह समाजवादी व्यवस्था की रचना नहीं चाहता है और यह जनता को समाजवादी रचना के विषय में जनता को धोखा देना चाहता है। मैं नहीं जानता कि धोखा यह दल दे रहा है, इस दल की नीति धोखा दे रही है, या धोखा वे लोग दे रहे हैं जो उन कार्यों में सहयोग प्रदान नहीं करते हैं, जो उन कार्यों के सिद्ध होने में बाधक सिद्ध होते हैं, जो देश को विकास की तरफ ले जा सकते हैं और जो देश में नई व्यवस्था उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, और इसके लिये प्रत्यक्ष प्रमाण यह देना चाहता हूं कि आज इस दल की शिकायत यह है कि जिस दल ने आवडी में यह घोषणा की कि देश में शीघ्रता के साथ समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जायगी और उसके लिये बराबर प्रयत्नशील रहेगी और वह दल जो इससे बाहर है वह भी इस देश में समाजवादी व्यवस्था के रचने की चेष्टा करेगा और अपने विचारों के नजदीक समाजवादी व्यवस्था को लायेंगे।

आज इस प्रदेश के इस सदन के सदस्यों को यह देखना है कि वह दल जो घोषणा करता था समाजवादी व्यवस्था लाने की या वह दल जो इस व्यवस्था लाने को कहता है वह वाकई में समाजवादी व्यवस्था लाने की चेष्टा करता है और इस देश और प्रदेश की जनता को इस योग्य बनाता है जिससे हमारे बीच में शीघ्र समाजवादी व्यवस्था आये। समाजवादी व्यवस्था को लाना एक रोज की बात नहीं है। कौन नहीं जानता कि चीन समाजवादी

व्यवस्था की तरफ जा रहा है ? उसके माओ ने कहा कि २५ वर्ष हमारे बीच व्यतीत हो जायंगे तब भी हम समाजवादी व्यवस्था की सड़क की तरफ नहीं चल सकते हैं। तो आज इस समाजवादी व्यवस्था को रचने की तरफ इस प्रदेश की सरकार को कुछ दूर तक उस तरह से तेजी के साथ कार्य करने का मौका नहीं मिल रहा है जैसा कि होना चाहिये, किन्तु कुछ चेष्टा की है। तो आज वह व्यक्ति जिसने समाजवाद के इतिहास का अध्ययन किया है उनके समक्ष में यह निवेदन करना चाहता हूं कि कदाचित् वह उस वास्तविकता को तथ्य से अलग रख रहे हैं जिस वास्तविकता से आज देश को गुजरना पड़ रहा है। आवडी रेजोल्यूशन हमको समाज की तरफ ले जाने की प्रेरणा प्रदान करता है आज इस बजट में कहीं-कहीं समाजवादी व्यवस्था को रखने की चेष्टा की गयी है लेकिन क्या दिखाई देता है। यदि हम इसका अध्ययन अपने केन्द्रीय सरकार के बजट के साथ करते हैं और बिना उसकी नीति का अध्ययन किये हुये इसका अध्ययन करते हैं और उसकी आलोचना करने की चेष्टा करते हैं तो हम सही तस्वीर उस समाजवाद की नहीं निकाल सकते हैं। कदाचित् उसके समझने में असमर्थता प्रकट करेंगे। आज कोई भी नक्शा, कोई भी समाज का अध्ययन तब किया जायगा जब कि उन तमाम नीतियों का अध्ययन किया जाय जो कि केन्द्रीय सरकार ने मुल्क में हमारे लिये निर्धारित कर रखी हैं।

जब हम इस बजट का अध्ययन करने की चेष्टा करें तब हम अनुभव करेंगे कि क्या वास्तविक ढंग से हम उस समाजवाद की ओर नहीं जा रहे हैं, जिसे स्थापित करने की लालसा हमारे प्रत्येक के हृदय में है। आज कौन ईमानदारी से यह कह सकता है कि केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय सरकार, देश के नेतागण और उनके तहत में कार्य करने वाली विभिन्न सरकारें उस समाजवाद व्यवस्था के रचने की ओर नहीं जा रहे हैं और शीघ्रता से उसे नहीं करने जा रहे हैं ? यदि ऐसी बात नहीं है तो फिर आज इम्पीरियल बैन्क का, इन्शोरेन्स का नैशनैलाइजेशन क्या मानी रखता है ? कम्पनी ऐक्ट में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करने के, विभिन्न प्रकार के टैक्सों को लगाने के, सुपर टैक्स की व्यवस्था में परिवर्तन करने के, ३–३ बड़े-बड़े स्टील के कारखाने लगाने के पब्लिक सेक्टर में और बिजली के सामान का कारखाना लगाने के क्या मानी हैं ? मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ये सब कार्य समाजवादी ढांचे की ओर हमें नहीं ले जा रहे हैं तो फिर हम कैसे और किधर समाजवाद की ओर जावेंगे। जो वास्तविक घटनाओं को अपनी आंखों के सामने घटते हुये देख रहे हैं उन्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हम उत्तरोत्तर समाजवाद की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या आप केन्द्रीय सरकार से कहने के लिये तैयार हैं कि वह शुगर इन्डस्ट्री को नेशनैलाइज करे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे कहने दीजिये, तो मैं बतलाऊंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं।

क्या कोई प्रदेशीय सरकार शुगर इन्डस्ट्री को स्वतः राष्ट्रीयकरण कर सकती है ? यदि वह नहीं कर सकती है और केन्द्रीय सरकार ने अपनी किन्हीं दिक्कतों के कारण उसे करने का प्रयास नहीं किया है तो जो आज प्रदेशीय सरकार को इसके लिये दोष देते हैं, दोष तो उनका स्वयं का है। यदि वे लोग उस कांस्टीट्यूऐंट असेम्बली में बैठे हुये होते जिसने इस देश का संविधान बनाया है और विभिन्न अधिकार प्रदेशीय सरकारों को प्रदान किये हैं कदाचित् वहां लोग प्रदेशीय सरकार को अधिकार प्रदान कर सकते थे और तब वह कह सकते थे कि शुगर इन्डस्ट्री का राष्ट्रीयकरण प्रदेशीय सरकार करे। तो वही लोग सब से बड़े दोषी हैं जिन्होंने समाजवाद की रचना में उसकी व्यापकता को बढ़ाने में रोड़े अटकाये हैं। परन्तु कहां थे वे हमारे साथी उस अवसर पर जब कान्स्टीट्यूऐन्ट असेम्बली बैठी हुई थी और विधान की बहुत सी धाराओं को बना रही थी ? उस समय तो हमारे समाजवादी ढांचे के प्रसारक शायद यह नारा बुलन्द करते हुये दिखायी पड़ते थे कि ऐसी विधान

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

परिषद् में किसी को बैठना नहीं चाहिये जिसे अंग्रेजों के कानून ने बनाया है और जो ऐसा विधान बनावेगी जिससे अंग्रेजी हुकूमत देश के अन्दर अधिक दिनों तक रहेगी। हमें देखना है ऐसे समाजवादियों की दूरदर्शिता और उनके प्रगाढ़ पाण्डित्य को। क्या यह सत्य नहीं है कि वे तो उससे भागते रहे और आज यदि इस सदन के लोग समाजवाद को विकसित करने की चेष्टा करते हैं तो कौन दोषी है समाजवाद को न फैलने देने का? मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के इस ओर के बैठने वाले व्यक्ति समाजवाद में रुकावट डालने वाले नहीं हैं। यदि कोई इसमें दिक्कत पैदा करता है तो वे हमारे बहके हुये साथी हैं जो भ्रमात्मक बातों का प्रचार करके उद्योग धंधों को विकसित नहीं होने देते हैं।

समाजवाद बातों से नहीं आता है। वह कार्यों से आता है, उस कार्यक्षेत्र को विकसित करने से आता है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और वे तमाम समस्यायें हल की जा सकें जिनसे लोग रोजमर्रा सताये जाते हैं। क्या यह सरकार उस तरफ नहीं जा रही है और समाजवाद लाने की चेष्टा नहीं कर रही है और क्या यह सरकार अपनी नीतियों का पालन करते हुये, अपने विभिन्न विचारों को उस नीति के तहत में चलाते हुये, समाजवाद की ओर नहीं जा रही है? जहां तक केन्द्रीय आयोग का सम्बन्ध है वह हमें अवश्य समाजवादी व्यवस्था की ओर ले जा रहा है। यदि आप इस सदन में ऐसे माननीय सदस्य हैं जो यह कहने की धृष्टता कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है तो मैं यही कह सकता हूं कि वह आज सामने की घटनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं और जो तथ्य है या जो प्रकाश हमारे सामने है, उससे ओझल रहना चाहते हैं।

आज यदि हम इस बजट का, इसी वाल्यूम ३ के एक-एक पन्ने का अध्ययन करें तो मालूम होगा कि जो काम हम आगे करने वाले हैं वे हमें किधर ले जा रहे हैं। यदि हमने १७,१८ करोड़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था की है उद्योग धंधों के लिये और २.६० करोड़ रुपया हम टैक्निकल एजूकेशन पर खर्च करने वाले हैं तो ये सब बातें किधर ले जाने वाली हैं? क्या कोई उद्योग धंधा बिना टेक्निकल परसोनैल के कामयाब हो सकता है? अगर हम बिना टेक्निकल परसोनैल के उद्योग धंधे चलावेंगे तो क्या वे चल सकेंगे? अगर लोगों को उस ओर शिक्षित करके लाना चाहें तो क्या कदम समाजवाद की प्रथा की ओर नहीं है? यदि हम जियोलाजिकल सर्वे करा कर खनिज पदार्थों के बारे में यह मालूम कराने की चेष्टा करते हैं कि अपने प्रदेश में क्या-क्या और कहां-कहां खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं, तो क्या समाजवाद नहीं है? यदि हम यह सब कुछ करा कर यह जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा क्या-क्या उद्योग धंधे यहां संचालित किये जा सकते हैं तो क्या हमारा मुल्क इन साधनों को अधिक मात्रा में मुहैया करने के लिये प्रयत्न नहीं कर रहा है, जो साधन कि हमें समाजवाद की व्यवस्था की ओर ले जा सकते हैं? जो संस्थाएं हमने प्राविधिक शिक्षा प्रदान करने के लिये खोली हैं या खोलने वाले हैं, क्या वह समाजवाद की रचना के लिये नहीं हैं? अगर हम अपने बीच में ऐसे नागरिक पैदा कर लें जो कि उद्योग धंधों में लगाये जा सकें, जो विभिन्न प्रकार के कामों में लगाये जा सकें, तभी हमारे बीच में उद्योग धंधे पनप सकते हैं, लोगों को रोजगार मिल सकता है, उनके गरीबी के स्तर में परिवर्तन किया जा सकता है! आज अगर हम घरेलू उद्योग धंधों को विकसित करने की चेष्टा करते हैं और उनको विकसित करने के लिये ९–१० करोड़ रुपया हम रखते हैं, ऐसी स्थिति में जब कि यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में खनिज पदार्थ नहीं है, वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि बड़े-बड़े उद्योग धंधे खोले जायं तो क्या छोटे-छोटे घरेलू उद्योग धंधों को खोल कर हम समाजवाद की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं? क्या यह नीति समाजवाद की ओर ले जाने वाली नहीं है? क्या इससे लोगों को अधिक रोजगार मिलने वाला नहीं है?

रूस, जिसका जिक्र जगह-जगह पर किया जाता है, जिससे आंशिक मात्रा में प्रेरणा हमारे माननीय विरोधीदल के लोग लेते हैं, जो मार्क्सवाद के हामी हैं, मैं उनसे पूछना

चाहता हूं कि क्या रूस ने अपने सारे स्तर को ऊंचा कर लिया है ? क्या रूस के नागरिकों का स्तर बिलकुल ऊंचा हो गया है ? क्या कंज्यूमर गुड्स की उसकी सारी आवश्यकतायें पूरी हो गयी हैं ? अगर आवश्यकताएं पूरी हो गयी होतीं, तो मेलनकोव को जाना न पड़ता और नयी पंचवर्षीय योजना बनाने की आवश्यकता न पड़ती। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो रूस से अधिक दूसरे देशों में उत्पन्न होती हैं, कई दिशाओं में वहां के नागरिकों का स्तर रूस के नागरिकों के स्तर से ऊंचा है। जब ऐसी बात है तो क्या जो प्रयास हमने किया है और जो प्रयास हम करते जा रहे हैं वह हमको आगे ले चलने वाला नहीं है। लेकिन हमारे माननीय विरोधी दल के लोग केवल यही कहते हैं कि हमने यह नहीं किया, वह नहीं किया। मैं बहुत नम्रता से निवेदन करूंगा कि यह आलोचना कोई मूल्य नहीं रखती, न कोई वास्तविकता ही रखती है, वह गलतफहमी पर निर्भर और भुलावे में डालने वाली है और केवल वोटरों का ध्यान आकर्षित करने वाली है, जिसकी तरफ हमारे माननीय नेता विरोधी दल और उपनेता का ध्यान है। हम समाजवाद की व्यवस्था बनायेंगे या न बनायेंगे, समाजवाद की ओर जायेंगे या न जायेंगे, उसकी ओर कदम उठाया जा रहा है या नहीं उठाया जा रहा है, इसका निर्णय तो इस सदन में नहीं हो सकता, इसका निर्णय तो इस प्रदेश की जनता ही करेगी जैसा कि निर्णय उसने उस समय किया था जब हमको विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, हमारे नेताओं को अनेक नामों से पुकारा जाता था, उन नेताओं को जो आज इस देश का ही नहीं सारे संसार का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या हम उन शब्दों को भूल गये हैं जो जनता के बीच में, प्रदेश के विभिन्न नगरों और विभिन्न सड़कों पर कहे गये थे ? क्या यह नहीं कहा गया था कि "पूंजीपतियों के तीन दलाल, गुप्ता, पंत, जवाहरलाल" जिस दल के नेतागणों ने इस प्रकार की नीतियों को बरता क्या वे इस सदन और देश का नेतृत्व करना चाहते हैं ? क्या वह इसी प्रकार की समाजवाद की व्यवस्था और समाजवाद की परंपरा देश और प्रदेश के सामने रखने की चेष्टा कर रहे हैं। वोटों के हासिल करने का यह ढंग भले ही हो लेकिन समाजवाद पर पहुंचने का यह ढंग नहीं है। जो सच्ची बात है उसको इस तरह से छिपाया नहीं जा सकता। सत्य तो प्रकाश में आता ही है, चाहे हम कैसा ही प्रयत्न क्यों न करें लेकिन हम उसको हमेशा के लिये ढक नहीं सकते।

यदि हम बजट के आंकड़ों को ईमानदारी से अध्ययन करें तो हमें बहुत कुछ ऐसा मसाला मिलता है जो एक ही तरफ ले जाने वाला है और वह यह है कि देश में समाजवाद की व्यवस्था किसी न किसी तरह से स्थापित हो। यह जो हमने अपने मेडिकल के बजट में तीन करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी, हेल्थ इन्श्योरेन्स स्कीम को जारी करने की व्यवस्था रखी और पांच मील के दौरान में अधिक अस्पतालों की रचना करने की और अधिक संख्या में मैटरनिटी सेन्टर्स रचने की व्यवस्था की तो क्या यह उन व्यक्तियों को अधिक साधन उपलब्ध कराने वाला है या नहीं जो साधन विहीन रहे हैं और जिनको वह चीजें अब तक नहीं मिलती रही हैं, जिनके पाने की वे आशा रखते रहे हैं और जिनको चन्द व्यक्ति ही अब तक पाते रहे हैं। यदि गांव-गांव में पांच मील की दूरी पर अस्पताल खुल जायं, मैटरनिटी सैन्टर्स खुल जायं, तो, जो इन सुविधाओं से वंचित रहे हैं, क्या उनको यह सुविधायें नहीं मिलेंगी। आज आधुनिक विज्ञान तेजी से बढ़ रहा है यदि उसकी देन जिले के स्तर तक पहुंचा दें, जिले-जिले में आधुनिक विज्ञान की देन को रख दें तो वह गांव के रहने वाले जो उससे अब तक वंचित रहे हैं जिन्हें लखनऊ आना पड़ता है या आगरा जाना पड़ता है क्या उनको यह सुभीते नहीं मिलेंगे और क्या यह व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था की तरफ ले जाने वाली नहीं है जिससे हम प्रत्येक को साधन प्रदान करना चाहते हैं, जिसे प्रत्येक को सुभीता देना चाहते हैं, प्रत्येक जो गरीब है, जो बीमार है और जो परेशान है।

यदि हम इंडस्ट्रीज के बजट की तरफ ध्यान दें जिसमें हम करीब १७, १८ करोड़ रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यय करने वाले हैं और काफी मात्रा में राशियां रखी हैं तो उसमें भी जो गुड़ का रोजगार चल रहा है, जो हजारों की संख्या में गुड़ के रोजगार में लोग लगे हैं उसका कैसे अधिक उपयोगी ढंग से विकास हो, उस पर यदि धन व्यय करने

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

वाले हैं, वेयर हाउसेज बनाने वाले हैं, और उन वेयरहाउसेज में गुड़ के रखने की व्यवस्था करने वाले हैं तो वह भी तो उस किसान के फायदे की ही चीज है जो काफी संख्या में इस रोजगार में लगे हैं और जिनको आज वह सुभीते नहीं मिले और जिनकी वे लालसा लगाये हैं सरकार से और देश के नेतागण से। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम बजट के विभिन्न प्रकार के घरेलू धंधों के विकास के लिए रुपया लेते जाते हैं। जिआलोजिकल सर्वे की स्थापना करना और विभिन्न उद्योगों में अनुदान इत्यादि दे कर उनका विकास करना यह सब कार्य ऐसे हैं जो अधिक उत्पादन की तरफ हमको ले जा सकते हैं और जो अधिक मात्रा में लोगों को रोजगार में लगा सकते हैं।

यदि हम ऐग्रीकल्चर विभाग के बजट की तरफ नजर डालें तो वूल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिये हम शीप ब्रीडिंग करना चाहते हैं, डेरी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, या कोआपरेटिव्ज को अधिक संख्या में बढ़ाना चाहते हैं तो वह क्या ऐसे कार्य हैं जो यहां कैपिटलिस्ट राज्य कायम करने वाले हैं? वह क्या कार्य ऐसे हैं जो हमारे बजट में पूंजीवादी व्यवस्था को रखने वाले हैं? पूंजीवादी व्यवस्था में आप जानते हैं कि हुकूमत को पूंजीवादी व्यवस्था के कार्यों में ज्यादा दखल देने की हालत नहीं होती है। आज तो यदि प्राइवेट सेक्टर में भी इंडस्ट्री करने वाले हैं तो उसे भी विभिन्न प्रकार के कंट्रोलों और नियंत्रणों के द्वारा इस प्रकार से करना चाहते हैं जिससे हमारे यहां उद्योग धंधे विकसित हो सकें। बड़े शोर के साथ यह आपत्ति की गई कि इस सरकार ने उद्योग विभाग के तन्वावधान में एक जो फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी नियुक्त की है उसके सभापति श्रीमान् बी० एम० बिड़ला जी को क्यों बनाया है या उनके अन्य साथियों को इसमें क्यों रखा गया है? जैसा कि माननीय सदस्यों को अब तक भलीभांति भासित हो गया होगा यह कमेटी एक खास काम के लिये बनाई गई है और एक खास काम इस कमेटी के सुपुर्द किया है। माननीय सदस्य यह तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां तक बड़े-बड़े उद्योग धंधों का विषय है वह तो हमारे विधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखते हैं। कौन से बड़े उद्योग धंधे पब्लिक सेक्टर में लगाये जायं, बिना केन्द्रीय सरकार की आज्ञा के तो वह हम नहीं लगा सकते हैं। उनको लाइसेन्स नहीं मिल सकते और जो उद्योग धन्धे प्राइवेट सेक्टर में इस प्रदेश में लगें उनका संचालन सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा होता है। इसलिए इस बात के लिए हमारा बहुत आग्रह पहले भी था कि अपने प्रदेश के स्तर को ऊंचा करने के लिए, उद्योग धन्धों को विकसित करने के लिए केन्द्रीय सरकार हमारे यहां ऐसे उद्योग धन्धे विकसित करे जिससे हमारे देश के लोगों को काफी रोजगार मिल सके। दुर्भाग्य से अभी पब्लिक सेक्टर में इस प्रदेश में केन्द्रीय सरकार क्या-क्या उद्योग धंधे लगायेगी इसका कोई निर्णय नहीं हुआ लेकिन पब्लिक सेक्टर में उद्योग धन्धे लग सकते हैं, उसके लिए तो बाजार खुला हुआ है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश को ऊंचा करने के लिए और लोगों को रोजगार देने के लिए, हम प्राइवेट सेक्टर के द्वारा यदि यहां उद्योग धन्धों को विकसित करना चाहते हैं और उनके अनुभव और उनकी सहायता से लाभ उठाना चाहते हैं और जो साधन उपलब्ध हों उनकी मदद से प्राइवेट सेक्टर में नए उद्योग धंधे लगाने का प्रबन्ध करें, तो आज प्राइवेट सेक्टर में नए उद्योग धन्धों को चलाने के लिए अनुभव किस व्यक्ति का मिले? क्या उन व्यक्तियों का न हो जो विभिन्न प्रकार के उद्योग धन्धों में पहले से लगे हुए हैं? या वह उन व्यक्तियों का हो जिन्होंने कभी कोई रोजगार नहीं किया है? हम दो महीनो में रिपोर्ट चाहते हैं कि कौन-कौन से उद्योग इस प्रदेश में लगाये जा सकते हैं। इस पर कोई निर्णय दे और हमें जानकारी करा दे, इस जानकारी के लिए किन व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता है? क्या वे व्यक्ति वह नहीं होंगे जिन्हें यह अनुभव है और जिन्हें उद्योग धन्धों की, उनको चलाने के कारण जानकारी है? तो फिर आज आपत्ति किस बात की?

श्री बिड़ला जी ने विभिन्न प्रकार के उद्योग धन्धे चलाये हैं, पदमपत, नवेटिया और राम रतन जी ने तरह-तरह के उद्योग यहाँ चलाये हैं तो उनके अनुभव से लाभ क्यों न उठाया जाय ? अगर समाजवाद उन लोगों में परिवर्तन करा सकता है जो बीस-बीस साल से समाजवाद के विरोधी रहे तो यह जो विभिन्न प्रकार के उद्योगों में लगे लोग हैं जो समय की गति को अच्छी तरह से समझते हैं, माननीय उपाध्याय जी और गेंदा सिंह जी से भी अधिक, जो हर चीज को नापते हैं और तोलते हैं । त्रिलोकी सिंह जी और कृपलानी जी जब बदल कर समाजवादी हो सकते हैं जिन्होंने जिन्दगी भर समाजवाद का विरोध किया तो यह लोग जिनके लिए सारे प्रकार के प्रतिबन्ध आज भी सरकार के हाथ में हैं क्या नहीं बदल सकते ? या हमें वे अपने अनुभव का लाभ नहीं दे सकते ।

तो मैं ऐसे आलोचकों से नम्रता से कहना चाहता हूं कि अगर प्रदेश के अन्दर उद्योग धन्धे विकसित हो जायं, आज की परिस्थिति और आज के कानून के मातहत, तो आपको जिस तरीके से और जिस ओर से सहायता मिले आप वह सहायता लीजिए और अनुभव प्राप्त कीजिए और उससे इस प्रदेश के उद्योग धन्धों को बढ़ाइये और विकसित कीजिए । मैंने बताया कि आज हमारे ऊपर यह आपत्ति है कि उत्तर प्रदेश की भूमि बड़े-बड़े उद्योग धन्धों के लायक नहीं है, अगर वह इस लायक नहीं है तो यही लोग बतायेंगे जो और प्रदेशों में उद्योग धन्धे लगाये हुए हैं कि यहां वह व्यवस्था हो सकती है या नहीं । अगर हमारे प्रदेश के जंगल कोई रा मेटिरियल पैदा करते हैं, अगर हमारे प्रदेश में बिजली और खनिज पदार्थ मौजूद हैं और अपने अनुभव की बुनियाद पर वह बता सकें कि यह उद्योग धन्धे यहां लग सकते हैं तो क्यों न हम केन्द्र के पास जाकर कहेंगे कि आप तो कहते हैं कि उद्योग धन्धे नहीं लग सकते लेकिन यह उद्योगपति जो अन्य प्रदेशों में उद्योग लगाये हुये हैं वह यहां लगाने के लिए सलाह हमें देते हैं, तो फिर हमारे प्रदेश में क्यों न उद्योग धन्धे लगाये जायं ? क्यों लाइसेन्स न दिया जाय ? यह कहा गया कि हमने उसमें कोई विशेषज्ञ नहीं रखा, तो हमने श्री दीनदयाल गुप्त जी हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के डीन आफ दि फैकल्टी आफ कामर्स हैं और जो टैरिफ कमीशन के सदस्य रहे हैं वह एक ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार के उद्योगपतियों को अपनी नजर से गुजरते देखा है और उस में लक्ष्मीपति मिश्र जैसे व्यक्ति हैं जो बड़े-बड़े उद्योगपति के उद्योग धंधों को चला रहे हैं, श्री नवेटिया हैं जो कि संसद के सदस्य भी हैं, कर्नल जैदी हैं जिन्होंने रामपुर में विभिन्न प्रकार के उद्योग चलाए हैं, अगर उनके सहयोग, सहायता और अनुभव से हमें उद्योगों को अपने यहां चलाने के लिए कुछ मशविरा मिल सकता है तो फिर आपत्ति किस बात की है ? यह कहा गया कि यह जो पूंजीपति हैं हम उनकी ओर नजर डालते हैं ताकि हमें चुनाव में पैसा मिले और इसलिए हम यह कर रहे हैं । मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातें करने से न तो हमारी ख्याति बढ़ती है और न हम अपने उस ध्येय तक ही पहुंच सकते हैं जिस पर हम और आप दोनों पहुंचना चाहते हैं । इसलिए आवश्यकता है कि हम ऐसे व्यक्तियों से सहयोग और सहायता लें जो उद्योगपतियों के नजदीक रहे हैं । केन्द्रीय सरकार से भी नजदीक रहे हैं क्योंकि धीरे-धीरे जो टैक्स आदि लग रहे हैं और जो नियंत्रण आदि हम लगाते जाते हैं उन को भी वे नामंजूर नहीं करते हैं और वह ऐसे व्यक्ति हैं जो समय की गति को समझते हैं और बदले हुए वातावरण में चलने की चेष्टा कर सकते हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारा कदम क्या होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को बदलें ? हमने जमींदारी प्रथा को और राजा महाराजाओं को हटाया तो क्या वह बदले नहीं ? क्या उन्होंने अपने को उन नीतियों के अनुसार परिवर्तित नहीं किया जो आज देश की मांग है और जो युग की मांग है । तो हम किसी को तिरस्कृत क्यों करें और अपने बीच से दूर करने की चेष्टा क्यों करें ? इसलिए मैं यह नम्रता से कहना चाहता हूं कि कमेटी इसलिए बनाई गई है कि उसका यह उद्देश्य है जिसका मैंने वर्णन आप के समक्ष किया । जहां तक इन पूंजीपतियों की व्यवस्था की रचना की बात है तो उस व्यवस्था का बनाने वाला यही सदन है और आप हैं न कि वह व्यक्ति जो कि केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए कमेटी में रखे गए हैं । मुझे दुख है कि दो तीन और बातें कहनी थीं लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी आशा है कि उन पर प्रकाश डाल देंगे । मैं आखिर में यह निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव में किससे मदद मिलेगी यह बातें तो इस समय सदन के

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

लिए निरर्थक है क्योंकि चुनाव में तो विरोधी दल भी जायगा और यह दल भी जायगा और इस प्रदेश की जनता से और विभिन्न क्षेत्रों से प्रत्येक प्रकार की सहायता लेंगे और यदि मैं यह जवाब में कह दूं कि विरोधी दल यह पैसे कहां से लाता है, यह बड़े-बड़े मार्चेज कहां से कराता है, एयर में उन के नेता कैसे चलते हैं तो वह बात यहां कहना मेरे लिए शोभा नहीं देता, मैं उस बात को कहना नहीं चाहता। एक आध साहब ने दीक्षा दी कि पूंजीपतियों से चन्दा नहीं लेना चाहिये, मैं उन व्यक्तियों से नम्रता से कहना चाहता हूं कि "फिजिशियन हील दाईसेल्फ" ऐसे व्यक्ति जो मिथ्या बातों का प्रचार कर के सलाह देना चाहते हैं अगर मैं अपशब्द न कहूं तो वह "अपना उल्लू सीधा करने के लिये" तो उससे सदन प्रभावित होने वाला नहीं है। हम सबको प्रदेश की भलाई का ख्याल है तो हमारा यह कर्तव्य है कि सारे प्रदेश के साधनों को मुहैया करने के लिए प्रत्येक से सहायता प्राप्त करते रहें और इस सूबे में समाजवादी व्यवस्था लाने का प्रयास करते रहें। लेकिन उसके लाने में समय लगेगा, जिसकी पूर्ण व्यवस्था करने के लिए हमें अभी बरसों व्यतीत करने पड़ेंगे, इसलिए व्यतीत करने पड़ेंगे कि हमें अपने तरीकों से काम करना है और उन तरीकों की नकल नहीं करना है जो विदेशों में रचे गये और जिन के द्वारा विदेशों में उन्नति हुई। अधिक न कहते हुए मैं और बातों का वर्णन अब उस समय करूंगा जब अपना बजट पेश करूंगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे मुह से कोई ऐसी बात निकल गई हो जो किसी सदन के सदस्य को तकलीफ देने वाली हो तो वह मुझे माफ करेंगे।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अध्यक्ष महोदय, मेम्बरान ने मुझको इस बजट के सम्बन्ध में जो पेश किया गया बधाई दी, मैं सब साहबान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने इस बजट के बनाने और उस स्पीच के तैयार करने में जो मैंने इस सदन में पढ़ी इस बात की ओर ज्यादा ध्यान दिया और मेरे ख्याल में वह जरूरी था कि इस देश के रहने वालों के सामने एक नक्शा यह आये कि सन् १९४६ से अब तक, जब कि जंग के बाद कांग्रेस ने इस देश की हुकूमत अपने हाथों में ली, उस वक्त से और अब तक क्या हुआ? और उसी के साथ जो कुछ आइन्दा होने वाला है उसका भी एक नक्शा मैंने उसमें रखा और मैं समझता था कि मैंने इस कदर साफ और खुले तौर पर बात कही है कि उसको सब साहबान अच्छे तरीके से समझेंगे। मगर मुझ को अफसोस है कि आज बाज मेम्बरान हमारे इस सदन के उसको गालिबन उस मानी में समझे नहीं।

समाजवाद की निस्बत बहुत कुछ कहा गया और मैंने यह अर्ज किया अपनी स्पीच में कि यह बजट अपने अन्दर समाजवाद का रंग रखता है। मैं नहीं जानता हूं कि जिन साहबान से मैंने इसके मुताल्लिक तकरीरें सुनीं वह किस समाजवाद के कायल हैं, उस समाजवाद में क्या होता है? यह मैं जरूर अर्ज करूंगा आपके द्वारा इस हाउस के मेम्बरान से कि जिन्होंने यहां के समाज को सोशलिस्ट बनाने का इरादा जाहिर किया और उसका फैसला किया उन्होंने यह बात भी कही कि वह समाजवाद जिसको अबादी रेजोल्यूशन ने कहा वह रूस का समाजवाद नहीं है। वह चाइना का समाजवाद नहीं है। यह वह समाजवाद है कि जो हिन्दुस्तान के हालात को और यहां की खास जरूरतों को सामने रख कर, यहां के आदमियों का कल्याण कर सकता हो। तो मैं अर्ज करूंगा और मैं शायद यह कहने की जुर्रत कर सकूंगा कि मैं इसकी तरदीद का खौफ नहीं करता हूं कि इस बजट के अन्दर जो इस साल इस ऐवान के सामने रखा गया हिन्दुस्तान में उस किस्म का समाज बनाने का रंग मौजूद है जिस किस्म के समाजवाद की हिन्दुस्तान को जरूरत हो सकती है, और उत्तर प्रदेश को जरूरत हो सकती है। और उसी के साथ यह भी ध्यान में रखने की बात है कि हमने सिर्फ यही नहीं कहा समाजवाद ने दुनिया में जहां नशवोनुमा पाया है डिक्टेटरशिप से लोगों के जब्र और तशद्दुद से, और जोर से। लेकिन हमने यह कहा कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारा डेमोक्रेटिक समाजवाद है, जनतन्त्र है और उस जनतन्त्र के अन्दर हम समाजवाद पैदा कर रहे हैं। तो उन बातों को भूलो, तो मैं तो नहीं उन्हें भुला सकता। मेरा तो फर्ज यही था कि मैं इस बात को आपके सामने रखूं कि अवादी रिजोल्यूशन ने क्या कहा, हम क्या करने जा रहे हैं। तो मैंने वह रंग उसको दिया। अब उस पर मैंने सुना। मैं अर्ज करता हूं कि या सुनो या समझो। मैं स्पीच को पढ़ूं उसमें लिखा हुआ है कि आज इस ऐवान के सामने जमींदारी अबोलीशन के दो बिल हैं। एक तो किसी वजह से हटा था फिर आ रहा है और एक जौनसार बावर जमींदारी अबोलीशन और एक यू० पी० अर्बन एरिया जमींदारी अबोलीशन बिल और कुमायूं का भी आने वाला है। हुजूरवाला, मैं मुख्तसर तौर पर अर्ज करूं कि अगर मैं अपनी इस स्पीच के बजाय इस तमाम बात को जो इसमें लिखी हैं, और एक मजमून में लिखता और प्रेस में उसे छपने को देता तो उसकी हेडिंग में क्या देता? उसका हेडिंग यह होता कि "सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट इन ऐक्शन इन यू० पी०" मैं अर्ज करता हूं कि आज हमारे सामने यू० पी० के रहने वालों की बुरी हालत का नक्शा खींचा, जैसा कि कहा गया कि फलां की यह हालत है, फलां की यह है। हां, मैं कहता हूं है, तमाम खराबियां हैं, मुफलिसी है, मुसीबत है सब कुछ है। मैंने क्या कहा अपनी स्पीच में, मैंने तो नहीं कहा मैंने समाजवाद बना दिया। मैंने तो यह कहा कि हम समाजवाद बना रहे हैं, उसके बनाने की तरफ क़दम उठा रहे हैं, उस मकसद को हासिल करना चाहते हैं और साफ लफ्जों में कहा स्पीच के अन्दर, जो कुछ हुआ है वह कम है, बहुत कम है। इसलिये कहता हूं कि आगे बढ़ो मगर मैं सुनता क्या हूं उसके बजाय कि साहब जमींदारी अबोलीशन के बिल पर कह दिया। और चलिये उसी में लिखा, स्पीच में उसका भी हवाला आया यातायात का। ट्रान्सपोर्ट का नेशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो जिस दिन से शुरू हुआ है सन् १९४७ से आज तक बराबर चला आ रहा है और उसके लिये रुपया इस बजट के अन्दर मौजूद है। फिर उससे अगली बात पर चलिये। मैंने अर्ज किया कि बिजली यहां सरकार बना रही है, तो क्या गलत है? या मैंने ऐसा कहा कि सन् १९०५ में बनाती थी सरकार? अरे मैं तो आज की बात कह रहा हूं कि सरकार के पावर हाउस बन रहे हैं, उसके जरिये से बिजली फैला रहे हैं, यह काम हो रहे हैं बराबर और क्या-क्या बताऊं। मैं अर्ज करता हूं, खुलासा बात यह है कि जितना काम इस बजट के अन्दर रखा हुआ है और जिनसे यहां के रहने वालों को फायदा हो सकता है वह सब समाजवाद के काम हैं। उनमें कोई बेसमाजवाद का काम तो है नहीं। मैं अर्ज करूं कि इस बजट पर जो तकरीरें हुईं.....

श्री अध्यक्ष--इधर के सदस्यों ने आपकी बेसमाजवाद वाली बात नहीं सुनीं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने यह अर्ज किया कि जितने काम इस बजट के अन्दर रखे गये हैं वे सब यहां के रहने वालों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। उनको उठाने वाले हैं और वे समाजवाद के हैं, बेसमाजवाद का कोई नहीं है। तो उस बेसमाजवाद का सब कुछ उसमें है कैसे नहीं? मैं अर्ज करूं कैसे नहीं है। सड़कें बन रही हैं तो किसके लिये बन रही हैं, टयूबवेल लग रहे हैं तो किसके लिये बन रहे हैं, नहरें निकल रही हैं तो किसके लिये निकल रही हैं, शफाखाने बन रहे हैं तो किसके लिए बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं तो किसके लिए बन रहे हैं? और क्या हो रहा है इसमें कुछ और मुझे बतलाइए कि इस बजट में क्या हो रहा है? यह तो काम हो रहे हैं। वह काम कौन से हैं जो कि इस बजट में हैं और समाजवाद के नहीं हैं? अगर सरकार के नौकरों की तनख्वाह का रुपया इसमें रखा हुआ है तो वह भी तो इस समाज के फायदे के लिए ही है। वह किसी गैर के फायदे का नहीं है। तो कैसे मैं मान लूं कि इसमें समाजवाद नहीं है। मेरे एक दोस्त ने कुछ फरमाया। जो तकरीरें हुईं इस बजट के ऊपर, मैं आपसे अपना रिऐक्शन उसके मुताल्लिक अर्ज करूं। बड़ी उम्दा तकरीरें हुईं। सिवाय चन्द साहबान के और बहुत उम्दा-उम्दा तकरीरें

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

हुई और एक खास बात नोट करने की यह थी बरखिलाफ पिछले जमानों के जनरल डिस्कशन में बजट के ज्यादा लोगों ने अपनी अपनी जगहों की निस्बत नहीं कहा। बहुत कम किसी ने कहा किसी जगह के ऊपर। वरना सब उसूलों के ऊपर बंधे रहे। तो यह समाजवाद की बरकत है और इस बजट की। तो मैं एक बात अर्ज करूं और वह सबके समझने की है, बड़ी मोटी बात है। हम कभी यह नहीं कहते कि हमने काम कर दिया। हम यह कहते हैं कि बहुत कम अभी हुआ है, बहुत ज्यादा करना बाकी है और उसको करना है। तो आज अगर कोई साहब जिनके दिमाग में रूस का नक्शा हो, कोई उस नक्शे को देखना चाहे यहां तो वह तो जैसा मैंने पहले अर्ज किया वह तो जब भी नहीं होगा जब पूरा समाजवाद यहां मुकम्मिल आ जायगा, वह तो जब भी नहीं होगा। तो फिर आज तो उनको समाजवाद का कुछ भी नक्शा नजर नहीं आ सकता। हां, वैसे हर वक्त नजर आ सकता है जरूरत है देखने के लिए आंख की। बात को समझने के लिए अक्ल और देखने के लिए आंख के ये दो जरिये हैं। जिनके पास ये हैं, वह इसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं।

अब आगे उतरिए। प्लान नम्बर पहला, प्लान नम्बर दूसरा। मैंने यह अर्ज किया कि यह जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, यह जनता का प्लान है। और उसकी निस्बत यह कहा गया कि यह साहब जनता का प्लान कैसे? मैंने अर्ज किया था कि एक तरीका जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कुछ हो नहीं सकता दुनिया के अन्दर? आज जब प्लान कोई बनाये तो क्या होगा? जब प्लान में कोई स्कीम या कोई चीज रखी जायगी तो वह गवर्नमेंट की तरफ से चलेगी और किसी की तरफ से चल नहीं सकती। किन गांवों के रहने वाले आदमी, किन शहरों के रहने वाले आदमी पहाड़ों की खोहों में जा जाकर तलाश कर लेंगे कि इस जगह पर पानी की बिजली बन सकती है, इस जगह पर नहर बनाई जा सकती है, इस जगह पर फलां काम किया जा सकता है, यह तो गवर्नमेंट के सिवा कोई नहीं कर सकता। इस प्लान में स्कीम्स जैसी हैं वह इस किस्म की हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए निकलीं कि वह गवर्नमेंट की तरफ से ही निकल सकती थीं। रिहन्द डैम के अलावा और जितनी स्कीम्स इसमें रखी हुई हैं वह सब तो दिमाग से उतर गईं लेकिन रिहन्द डैम को देखिए वह किस गांव के आदमी से निकल सकती थीं? गवर्नमेंट ही तो उसको निकलवा सकती थी। मेरे पास वक्त है नहीं मैंने गलती की, एक-एक जिले का प्लान यहां पर बना हुआ है।

श्री गेंदासिंह—सभी जिलों का नाम है उसमें?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—हर जिला अलग-अलग है। बेखबरी का क्या इलाज? कहा गया कि प्लान की मेम्बरों को खबर नहीं। मैं तो अर्ज करता हूं कि मेम्बरान को, सब को खबर है प्लान की। कोई नयी बात मैंने नहीं कही। इस प्लान में किसी एक जिले को देखिये कि उसके किस कोने को छोड़ा गया है। सब उसके अन्दर है। अब मुलाहिजा हो कि हम प्लान बनायें, फिर बनायें और फिर बनायें और उसके बाद किसी वक्त अपने मकसद को हासिल करें। यह एक मियार है, इसके ऊपर जांचो इस बात को कि कौन ठीक है? एक बात मुझे और याद आ गयी, मैं भूल गया था। उस प्लान की एक और खराबी हो गयी। अगर वह फाइनेन्स कमेटी के सामने हो आती तो वह खराबी न रहती मैं मानता हूं। एक बात मैं अर्ज करूं हुजूरवाला के जरिये से इस हाउस से कि इस हाउस की बनायी हुई कमेटी तो क्या, मैं तो एक मेम्बर को अपना सरताज समझता हूं जहां तक कि उसकी इज्जत और उसके एहतराम का ताल्लुक है। फाइनेंस कमेटी का कायदा है, हुजूर को मालूम है कि वहां जो कुछ भी हो वह कहीं बयान नहीं किया जा सकता। मैं इसलिये उस बात को बयान

नहीं कर सकता। इस पोजीशन में यह ऐडवान्टेज उठाना था कि कोई साहबान उधर से कह दें और मैं उसके जवाब में कुछ कह नहीं सकता। अब मैं कहूं कैसे कि वहां हुआ क्या। जो हुआ वह तो वहां हुआ। अगर मेरे लिये मुमकिन होता कि मैं उसको डिस्कलोज करूं जो मैं उसको डिस्कलोज कर देता और मैं यकीन दिलाता हूं कि उसको सुनने के बाद इस हाउस का यह वर्डिक्ट होता कि फाइनेन्स कमेटी की किसी तरह की बेएहतरामी नहीं की गयी और जो कुछ किया गया वह बिल्कुल बजा था और ठीक था।

अब हुजूरवाला, मैंने यह दिखलाया और शायद गलत तौर पर कि जो कुछ अब तक हुआ है उससे इस राज्य की खुशहाली बढ़ी। उसके लिये मैंने जिक्र किया पर कैपिटा इन्कम का और उस पर कैपिटा इन्कम को सन् ४८-४९ के साल की जो कीमतें थीं उनकी रोशनी में दिखलाया। इसके मुताल्लिक उधर से एतराज यह हुआ कि साहब, वह तो करेन्ट प्राइसेज की हालत में दिखलाना चाहिये था। अगर दुनियां में कहीं ऐसे उल्टे उल्टे काम होते हों तो मैं भी करता। जो लोग स्टैटिस्टीशियन्स हैं वे जिस गरज से जिस काम को करते हैं उसका तरीका उन्होंने मुकर्रर कर दिया। एक बात मोटी सी मैं अर्ज करता हूं कि फर्ज कीजिये कि आपने १९५२ में इस यू० पी० के अन्दर एक लाख मन गल्ला ज्यादा पैदा किया। अब उस एक लाख मन गल्ले की शक्ल अगले साल में देखें तो कुछ और नजर आयेगी। इससे अगले साल देखें तो कुछ और नजर आयेगी यानी कहने का मतलब यह है कि वह घटती बढ़ती नजर आयेगी। इसकी सही शक्ल यानी मुस्तकिल शक्ल आप नहीं देख सकते क्योंकि वह हमेशा कीमत के फंदे में फंसी रहती है जो सुबह, शाम, दिन और महीनों में बदलती रहती है।

मैं एक चीज स्पेसिफिक इस हाउस के सामने पेश करता हूं। मैंने १९४८-४९ की कीमतों को कांस्टेंट मान कर दिखाया है कि इतनी आमदनी बढ़ी है। करेंट प्राइस की रोशनी में देखें और अगर कीमतें बढ़ी हैं तब तो जाहिर है कि वह बढ़ जाती है। मैं अर्ज करूंगा कि उन्होंने कहा कि तीन अरब की आमदनी थी वह घट कर २ अरब ७५ करोड़ रह गई। जब कीमतें बढ़ती हैं तो रुपया घटता है और जब कीमतें कम होती हैं तो रुपया बढ़ता है। यह एक कायदा है। मैंने करेंट प्राइसेज को छिपाने की गरज से नहीं छोड़ा बल्कि इसलिये छोड़ा कि क्वांटम आफ प्रोडक्शन है और वह जिस मिकदार में हुआ है वह अपनी जगह पर अटल है। यह अल्फाज मैंने इस्तेमाल किये थे। मैं अर्ज कर चुका हूं कि अगर कीमतें बढ़ती हैं तो रुपया कम घटता है। मैंने तो सारी चीजों को रोशनी में दिखाने की कोशिश की है। हुजूरवाला, एग्रीकल्चरल कीमतें दिखाईं और इंडस्ट्रियल कीमतें भी दिखाईं, जूतों की कीमतें दिखाईं और सब चीजों की कीमतें दिखाईं, जितनी कीमतें दुनिया में होती हैं यह पूरी की पूरी दिखाई हैं।

हुजूरवाला, मैंने एक जगह पैरिटी के बारे में दिखाया ऐग्रीकल्चरल पैदावार की कीमतें घटीं तो काश्तकार जो चीज पैदा करता था उसकी कीमतें कम हुईं और दूसरा रुख यह भी है कि जो चीज वह खरीदता था इसके दो पहलू हैं यह मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि यह काश्तकार के लिये अनफेवररेबिल हुआ। जो कीमतें घटी हैं वह ९८ से लेकर शायद ७५ तक पहुंचीं। लेकिन असली माने में नहीं हुआ। इसलिये कि अगर वाकई उसका प्रोडक्शन है जो बढ़ा है तो उसकी कीमत घटी जो चीज वह बेचता है और जिनको वह खरीदता है उनकी भी बढ़ीं उसके मुकाबले में मैंने बतलाया और २७० पर कैपिटा इंकम मैंने दिखाई है उसका मुकाबला किया जाय कि वह उससे कवर हुआ या नहीं। तो इसमें क्या फर्क पड़ा। अगर हो भी, मैं यह अर्ज करता हूं कि हो भी थोड़ी देर के लिये तो वह कौन सा दिन आयेगा, किस दुनिया में? अब वह दिन नहीं आ सकता है कि जिस दिन प्राइसेज में तब्दीलियां नहीं होंगी और किसी वक्त किसी क्लास को, किसी वक्त किसी क्लास को, किसी वक्त किसी को हमेशा कोई न कोई चीज अनफेवरेबिल होती रहेगी। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि वह कौन सी दुनिया है

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

कि जहां इस तरह के वाक्ये रोज नहीं होते, वह कौन सी दुनिया है कि जहां आपकी बताई खुशहाली रहती है। इसलिये यह जो हम कहते हैं कि खुशहाली नहीं है, यह बात गलत है।

अब एक चर्चा यहां यह हुआ कि अनइम्प्लायमेंट है और वह बहुत बढ़ गया है। उसको दूर किया जायगा और यह जो सेकिन्ड प्लान है उसमें उसका इलाज निकाला गया है कि उसमें ऐसे काम किये जायं कि जिनके जरिये से यहां पर बेरोजगारी जो है वह दूर हो। किसी साहब ने स्पीच को पढ़ा, मैंने तकरीर में सुना था कि इस तकरीर में यह बताना चाहिये था कि कितनी बेरोजगारी है और रोजगार से इसको दूर करने में कितनी मदद मिलेगी। चार जगह स्पीच में लिखा हुआ है कि टोटल १३ लाख आदमियों को रोजगार दिलाया जा सकेगा। पता नहीं वह कैसे इसे पढ़ सके बिना इसको देखे हुए। यह जो बात थी उसके लिये मैंने यह अर्ज किया।

समाजवाद कैसे बनता है यह भी मैं बतलाऊं। मैंने सुना है कि समाजवाद दो तरह से बनता है। उसकी पहली सूरत है कि जमीन का बटवारा होना चाहिये और वह बटवारा दुबारा होना चाहिये। पहले मैं इसी की बाबत अर्ज करूंगा। इसका मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि जिन आदमियों के पास जमीन नहीं है और उनसे काश्तकारी कराना है उनको जमीन मिल जाय। जिन आदमयों के पास जमीन कम है जितनी कि एक आदमी को जरूरत समझी जाती है उस हिसाब से, तो उसके पास वह पूरी हो जाय। इनके अलावा और कोई मकसद हो सकता है यह मैं समझता नहीं इस बटवारे का। जमींदारी का एबालिशन जब हुआ उस समय इस बात पर सोचा गया कि जमीन के बटवारे की क्या सूरत हो सकती है और उसका क्लाज इसमें रखा हुआ है। मैं पढ़ूं क्या, बतलाये देता हूं कि इसमें यह लिखा हुआ है कि नतीजा यह निकला कि जमीन के बटवारे से कोई फायदा नहीं हो सकता। जो आदमी थोड़ी जमीन रखता है उसको और ज्यादा जमीन मिले अगर, तो उतनी जमीन यहां नहीं है। जमीन कितनी है इसका तो हिसाब इस वक्त में नहीं बता सकता लेकिन उस जमीन को लेकर इसके अन्दर यह हिसाब लगाया गया, इस रिपोर्ट में और उस हिसाब से यह देखा गया कि उस जमीन के बटवारे से यहां के रहने वालों को कोई फायदा नहीं हो सकता और इसलिये इस सवाल को छोड़ दिया गया।

दूसरी चीज एक और हो सकती है समाजवाद की, इस समाजवाद की, इस जमीन के बटवारे के अलावा। उन्होंने सीलिन्ग की बात मुझे याद दिलाई। सही बात है। लेकिन यहां जमींदारी अबालीशन के जरिये से सीलिन्ग मुकर्रर हो गई है ३० एकड़ जमीन की लोगों के वास्ते। उसे छोड़ा ही इसलिये था कि अगर जमीन का बटवारा किया जाय तो वह लोगों को पहुंचती नहीं है और इसके मुताल्लिक चन्द बातें इसमें लिखी हुई हैं, मसलन पैदावार कम हो जायगी, वगैरह। इसलिये उसे हमने छोड़ दिया।

एक दूसरा काम सोशलिस्टपन का यह है कि जो मालगुजारी ली जाती है वह न ली जाय अच्छा, मैंने अपने बजट स्पीच के वक्त यह निवेदन किया था कि टैक्सेशन हमारे प्रदेश में दूसरे सूबों के मुकाबले में, जैसे बम्बई, बंगाल, वगैरह, कम है। मालगुजारी जिस चीज का नाम है उसे आम तौर से इकानामिस्ट टैक्स में शामिल नहीं करते और मैंने भी नहीं किया और इसकी वजह यह है कि वह टैक्स नहीं है। जैसा मैंने एक दिन इस हाउस में इर्रीगेशन रेट्स के बारे में कहा था कि वह टैक्स नहीं है, वैसी ही यह बात है। पानी देते हैं, उसकी कीमत लेते हैं। वैसे ही जमीन देते हैं काश्त करने के लिये और उसके बदले में उनसे मालगुजारी लेते हैं। चुनान्चे मैंने तो वह ३ प्वाइन्ट कुछ की फीगर दी है उसके अन्दर वह शामिल नहीं है। लेकिन अगर उसे शामिल भी कर लिया जाय और ५ उसे कर लिया जाय जोड़ कर, जैसी कि वह हो जाती है, और दूसरी स्टेट्स के टैक्सेशन के मुकाबला कर

लिया जाय कि उनसे कम है या ज्यादा है तो सही बात मालूम हो जायगी। यह कहा गया है कि मालगुजारी छोड़ दो। हां, एक ऐसा समाजवाद बने और उसका मेम्बर मैं भी होना चाहता हूं। मेरी तो तमन्ना है कि कोई ऐसा करिश्मा करे कि दुनिया में किसी से कुछ भी न लिया जाय और हर एक के घर में हरेक चीज पहुंच जाय। टोपी, शेरवानी, गल्ला और जो बैलगाड़ी चाहता हो उसे बैलगाड़ी भी पहुंच जाय। जिस वक्त किसी टैक्स का नाम आवे तो मत लगाओ, मालगुजारी छोड़ दो। यह भी एक तकरीर हुई कि जमींदारी मन्सूख होने से काश्तकार को क्या फायदा हुआ, इसलिये कि जो जमींदार लेते थे वह तुम भी ले रहे हो। लेकिन अगर दिमाग हो तो यह महसूस वह करें कि इंसान के लिये गुलामी सबसे ज्यादा बुरी चीज है, उसके सामने पैसे की कोई कीमत नहीं है, वह गुलामी अब खत्म हो गई है। किसान अब आजाद है, वह किसी का गुलाम नहीं है। पहले उसे कोई भी अखत्यार नहीं था और जमींदार की मरजी पर वह मुन्हसर था। जनाबबाला, मैं अर्ज करूं कि मैं भी वकील रह चुका हूं, मुकद्दमे लड़ाये हैं मैंने भी, जाती तजुरबा रखता हूं। पहले यह था कि एक काश्तकार छप्पर डालना चाहता है बैलों के लिये लेकिन जमींदार उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता था। अगर आज उनको स्वतंत्रता मिल गई तो वह कुछ नहीं है, तो मैं समझता हूं कि कल वह कहेंगे कि अंग्रेज चले गये तो भी कुछ नहीं हुआ, अगर रहते तो क्या होता और उनके जाने से क्या हुआ? अंग्रेज के जाने से भी कुछ नहीं हुआ। चलते फिरते हम तब भी थे तकरीरें भी इस हाउस में बैठकर अंग्रेजों के जमाने में कितने दिनों तक हमने की हैं।

अब जहां तक समाजवाद की बात है, जो समाजवाद हम कायम करने वाले हैं जिसको हम बनाना चाहते हैं उसकी एक सूरत यह होगी कि जब वह बन जायगा और यह समाजी सोसाइटी तैयार हो जायेगी उस वक्त आदमियों की आमदनी में जो अन्तर नजर आता है वह नहीं आयेगा। आज इसी लखनऊ में जाओ एक महल में हाफिज इब्राहीम साहब और उनके पड़ोस में एक आदमी जमीन के ऊपर छप्पर की एक झोपड़ी में बैठा है और उस तरह से अपनी जिन्दगी गुजारता है। एक घर में हो जिसके ऊपर छत नहीं और छप्पर हो तो वह छप्पर भी टूटा हो जिस पर बारिश हो तो बारिश जाय और धूप हो तो धूप जाय, यह जो नकशा हिन्दुस्थान के गांव का है इसीलिये तो है कि आमदनी उसमें बराबर नहीं है और आमदनी बराबर होने के माने में यह समझता हूं यह नहीं कि जो शायद कुदरत से न हो सका। अल्लाह मियां, परमेश्वर या परमात्मा इस दुनिया के अन्दर जिसे नहीं कर सका यानी जिस काम को मेरे दोस्त करने का दावा करते हैं कि हर आदमी के पास नपी तुली जमीन सवा ६ एकड़ हो। यह नहीं हो सकता। मगर हां यह जरूर है और यह नकशा इन्सान का हम नहीं देख सकते, उसको मिटाना चाहिये, उस नकशे में जहां तक इंसान की ताकत में उसका मिटा देना हो उस हद तक हम मिटायेंगे यह प्लान का लक्ष्य है, मकसद है इसी को हमने कहा है। हमने यही नहीं कहा कि दौलत बढ़ाओ बल्कि यह कहा कि दौलत इस तरीके से बढ़ाओ कि जिससे यह जो नाबराबरी नजर आती है वह न रहे। आमदनी की तकसीम जो है वह न्यायसंगत हो जाय इंसाफ के मुताबिक हो जाय यह लक्ष्य इस प्लान का है।

एक सदस्य—ऐड्रेस अध्यक्ष को करके कहें तो हम लोग भी सुनें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं ऐड्रेस जिधर को मुंह करके करूंगा वह उन्हीं को होगा।

श्री अध्यक्ष—अध्यक्ष के बजाय आप माइक्रोफोन को एड्रेस करें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—आपकी इजाजत हो गई इसलिये मैं ऐसा कर सकता हूं वरना आपकी इजाजत के बगैर तो मैं यही समझ रहा था। मुलाहिजा फरमाइये कि बड़ी तनख्वाह के लोग हैं। उनकी तनख्वाह के लिये उन्होंने यह कहा कि ५०० रुपये से ज्यादा

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

किसी को न मिलना चाहिये, यह उन्होंने उसकी सीलिंग बतलाई और यह बतलाया इस सिलसिले में कि पैसे की जरूरत को पूरा कैसे किया जाय। यह भी कहा गया कि कांग्रेस ने करांची में एक रेज्यूल्यूशन पास किया था। अब वह रेज्योल्यूशन पास किया था सन् ३१ में, उसमें बहुत सी चीजें थीं और यह भी कहा गया था, हिन्दी का लफ्ज तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अंग्रेजी का जो लफ्ज उसमें था वह था "आर्डिनरीली ५०० रुपये से ज्यादा न हो"। अब मैं सब की तनख्वाह ५०० रुपया कर दूं और उससे ऊपर १,००० या ३,००० जितने पाने वाले हैं सब को निकाल दूं, जिनमें मैं भी शामिल होता हूं (आवाज—खर्च न करें)। खर्च न करने के क्या माने हुये? उत्तर प्रदेश किसी मेम्बर को २००० रुपया तनख्वाह दे और कहे कि ५०० रुपये से ऊपर खर्च न करो उसके क्या मायने हुये? चाहे उस से २५,००० ले लो या यह कहो कि ५०० रुपया ही खर्च करने होंगे, बात तो एक ही है। लो या न लो, उसको दो या न दो। उसको तो प्रेक्टिकली खर्च करने के लिये ५०० ही मिलेंगे। हां, तो मैं इस बात को तो मान नहीं सकता कि जिन आदमियों ने उस रेज्योल्यूशन को बनाया था उनको अक्ल नहीं थी, उन्होंने यह कहा था उस रेज्योल्यूशन के जरिये, और यह रेज्योल्यूशन पास हुआ था १९३१ में, तो अब २०३१ में कोई शख्स इस बात को कहे कि अब भी ५०० ही रहने चाहिये। अब उस जमाने की आर्थिक स्थिति कुछ और थी और इस जमाने की आर्थिक स्थिति कुछ और है। जो कीमतें उस जमाने में थीं उनमें और आज की कीमतों में फर्क है। उस जमाने में जिन्दगी का जो स्टेटस था उसके हिसाब से ५०० रुपये की रकम काफी थी। वह जमाना ऐसा जमाना था जिसमें आदमी ५०० रुपये में अच्छी तरह से गुजर कर सकता था। मैं यह नहीं कहता कि किसी को ऐश करने की राहत दो, लेकिन उसकी जिन्दगी की जरूरयात को तो पूरा करना ही होगा।

इस लिहाज से आज यह कैसे कहा जा सकता है कि ५०० रुपये की सीलिंग मुकर्रर कर दी जाय तभी समाजवाद होगा? मेरे दोस्त लीडर आफ अपोजीशन ने जितनी बातें कहीं अपनी तकरीर में वह किसी न किसी दिन आने वाली हैं दो एक को छोड़ कर, जो बिलकुल गलत थीं और बाकी सबकी सब आनी हैं। लेकिन यह ५०० रुपये की सीलिंग आज की हालत में किसी तरह से मानी नहीं जा सकती। अगर हम ५०० रुपये सीलिंग रखें तो १,००० से ऊपर तनख्वाह पाने वाले आदमी आपकी मुलाजिमत में ३०८ हैं और १,००० तनख्वाह पाने वाले ८०० कुछ हैं। अब इन सब की तनख्वाह घटा कर ५०० रुपया कर दी जाय तो २५ लाख रुपया बच सकता है। "अब नंगी क्या नहाय और क्या निचोड़ें"। अब और रुपया कहां से आयेगा?

एक सदस्य—प्राइमरी तक की फीस तो माफ हो जायगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—फीस माफ और टीचर मुफ्त और यह जब कि हम कह रहे हैं कि हमने माफ की है और इसी बजट में की है। हम उसी तरफ कदम बढ़ा कर चल रहे हैं जिस तरफ वह कहते हैं। हम तो सफर कर रहे हैं। इस यू० पी० के और हिन्दुस्तान के रहने वाले हर आदमी को यह समझना चाहिये कि वह यात्रा कर रहा है। अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है और वह मंजिल समाजवाद की मंजिल है। उसमें मेरी पार्टी और आपकी पार्टी का कोई सवाल पैदा नहीं होता, कोई अन्तर नहीं है। यह तो सब को ही करना है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि उसमें से २५ लाख की बचत हुई। मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें किसी को यह मतलब नहीं निकालना चाहिये कि मैं तनख्वाहों की डिस्पैरिटी को दूर करना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि पिछले साल दो रुपया नीचे की तनख्वाह वालों का बढ़ाया गया था और वह समझते थे कि एक दो रुपया इस साल भी बढ़ेगा। मैं अर्ज करता हूं कि हमने पिछले साल दो रुपया बढ़ाया और सौ रुपया तक पाने वालों का डियरनेस एलाउन्स तनख्वाह में मिलाया, तो अब मैं वह कर रहा हूं जिस दिन वह हालत ही न रहेगी उस दिन एक नकशा सामने आ जायगा, जब ऐसे फर्क की जरूरत न रहेगी। अपनी बजट स्पीच

में जब मैं इस चीज को बयान कर रहा था तो मैंने हेडिंग पढ़ा था और कोई हेडिंग मैंने नहीं पढ़ा। वह इसलिये पढ़ा था कि उससे लोगों को स्ट्राइक हो जाय और अच्छी तरह से लोग उस पर ध्यान दें। मैंने पढ़ा था "सोशलिस्ट समाज की तरफ कदम"। हमने जो चन्द कदम उसकी तरफ उठाये हैं वह मैंने उसमें गिनाये। फिर भी किसी की नजर उस तरफ न जाय तो इसमें मेरी क्या गलती। पिछले साल जो बजट मैंने पेश किया था उसमें मैंने बताया था कि १०० रुपया तक पाने वाले के डियरनेस एलाउन्स को उनकी तनख्वाह का जुज बना दिया जाय और इस करेन्ट इयर के बजट में हमने वह २०० तक की तनख्वाह वालों के लिये कर दिया। अगर कोई शख्स, जब मैं एक कदम आगे को उठा रहा हूं, यह कहे "हां, हाफिज, आगे बढ़ा", तो मैं मानूं कि इंसाफ हुआ। लेकिन कोई यह कहे "हाफिज तू तो पीछे हट गया" तब मैं क्या कहूं ? हुजूर वाला, अगर यहां शायरी हुआ करती तो मैं भी देखता, वैसे मैं वह तो कर नहीं रहा हूं। यहां पर हम इसलिये हैं कि यहां के रहने वालों के लिये रोजगार बढ़ायें। तो जो बहस हुई और जो चन्द बातें कही गई उन बातों को मुझे दुहराना पड़ रहा है। यह मिल ओनर जो है यानी सब को यह अहसास होता है कि दूसरों को देखकर अपने आप हमारे अन्दर वह फीलिंग न हो और इस माने में कि वह यह कह सकें कि यह आदमी तो समाजवाद के काबिल ही नहीं है। उसको इसमें से निकाल दिया जाय। इसलिये कि बुग्ज या रगबत मिल ओनर्स से मुझे नहीं है। यू० पी० स्टेट जो कांस्टीट्यूशन के अन्दर कर सकती है उस से उसी को करने की तवक्को करते हैं और जो केंद्रीय सरकार कर सकती है उसकी तवक्को उस से रखी जा सकती है। हम संविधान के लिहाज से उसको नहीं कर सकते। यहां पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों कायम हुये। यह दोनों चीजें हमारे प्लान के जुज हैं, उनके मुताबिक काम करने के ख्याल से किस सूरत से चलेंगे, कैसे चलेंगे वह सूरतें सामने आती जायंगी, लेकिन चूंकि प्राइवेट सेक्टर हैं इसलिये हमने उससे यह चाहा कि हमारे यहां इस स्टेट में मुख्तलिफ किस्म की भारी इंडस्ट्री कैसे कायम हो सकती है। अभी गुप्ता जी अपनी तकरीर में कह रहे थे कि केंद्रीय सरकार से हमने कोशिश करा रखी है कि हमको हैवी इंडस्ट्री दो और हमको जो वह दे देंगे वह यहां लग जायंगी। इसके अलावा हम जो प्राइवेट सेक्टर से लगवा लें उनसे लगवाने के लिये ३ करोड़ ५४ लाख रुपया रखा था। उसके जरिये से आदमियों को रोजगार मिलेगा फिर हमने इस तरह से यह भी ख्याल में रखा कि जो यहां स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वह भी इस हैसियत से की जायंगी कि अगर हमारी स्टेट में हेवी इंडस्ट्री काफी कायम न हों तो भी उनके जरिये से यहां के रहने वालों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल जाय। इस तरह से हमने उस को कायम किया।

कुछ लोगों ने कहा कि शुगर इंडस्ट्री नैश्नेलाइज की जाय। मैंने तो साफ अर्ज कर दिया कि हम तो कर रहे हैं और करते-करते मालूम नहीं क्या करेंगे ? बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि वक्त के वक्त तक नहीं बतलाया जा सकता है उस में ही मसलहत होती है। जैसे टैक्स के मामले होते हैं। मैंने सेल्स टैक्स के बढ़ाने की बात कह दी थी और मैं हाउस का उस के लिये शुक्रिया अदा करता हूं। सिद्धांत के तौर पर सब साहबान की जो यहां तकरीरें हुईं उन्होंने इस बात को माना है। हां मैं यह मानता हूं कि जो बातें मेम्बरान ने कहा हैं उन्हें इस हाउस को मंजूर करना है। मैं इस हाउस का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरी जो मुराद थी इस बेड़े को उसने किसी तरह से पार लगा दिया। हाउस की मेहरबानी है कि उसने हमारे बजट की ताईद की है और इस के साथ-साथ मैं इस बात को भी मानता हूं कि जहां तक हो सके खर्च कम हो और एकोनामी हो और इसके लिये हमने एक एकोनामी कमेटी बिठा दी है और वह एक बहुत ही तफसीली तहकीकात कर रही है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक माननीय मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं तब तक यह सदन बैठा रहे।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि १५ मिनट का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं अर्ज कर दूं, मैंने किसी को पकड़ नहीं रखा है।

श्री अध्यक्ष—५ बजे के बाद अगर आप बोलते हैं तो समय बढ़ाना पड़ेगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं तो अगर हाउस चाहे अभी खत्म कर दूं, मैं नहीं बोलूंगा।

हम जहां तक हो सकता है खर्च के अन्दर कमी करने पर हमेशा नजर रखते हैं और कोशिश करते हैं और मैं मानता हूं कि हमारी इस तरफ मुस्तकिल नजर होनी चाहिये और हमने एक मुस्तकिल एकोनामी की कमेटी बिठा रखी है और जो कमेटी काफी वक्त लगाकर सब कामों को देख रही है और उसकी सिफारिशें हमारे सामने आयेंगी और इतना ही नहीं हम यह भी सोच रहे हैं कि इस काम के लिये एक मुस्तकिल कमेटी कायम की जाय जिसके जरिये से सूबे की एकोनामी की तरफ हर वक्त नजर रहे और वक्तन फवक्तन कमेटी कायम करने की जरूरत ही न रहे। जितना पैसा बचा कर किफायतशारी से काम कर सकते हैं वह होना चाहिये और जितने कम से कम में खर्च चलाये जा सकते हैं उस में हम चलायें। इन सब बातों को मैं मानता हूं और इसमें कोई उज्र या इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अब चूंकि हमारे दोस्त खफा हो रहे थे और नागवार खातिर न हो इसलिये मैं समझता हूं कि मैं अब और कुछ न कहकर खत्म कर दूं। इसलिये अब मैं माफी चाहता हूं।

सदन द्वारा प्रदत्त धन्यवाद के उत्तर में श्री राज्यपाल का पत्र

श्री अध्यक्ष—अब एक सूचना मैं सदन को देना चाहता हूं। श्री राज्यपाल जी के सम्बोधन के ऊपर जो यहां सदन में प्रस्ताव उपस्थित हुआ था और स्वीकृत हुआ था वह सदन की ओर से मैंने और कुछ और सदस्यों ने जा कर राज्यपाल जी को भेंट किया, उसके उत्तर में जो उन्होंने पत्र लिखा है वह मैं पढ़कर सुनाये देता हूं।

"अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पत्र दिनांक २८-२-१९५६ के लिये जिसे आपने व विधान सभा के कुछ अन्य सदस्यों ने स्वयं आकर भेंट किया, धन्यवाद देता हूं। मैं विधान सभा के प्रस्ताव के लिये जिसे उन्होंने अपनी २२-२-५६ की बैठक में स्वीकार किया, आभारी हूं।"

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ;
१ मार्च, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पा०—ए० पा०—२५१ एल० ए०—१९५६—७९६।